सत्र-04(भाग-2) 25मार्च, 2026

खण्ड- 08 .... बुधवार,............

अंक- 25 04 चैत्र,1948(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-04(भाग-2) में अंक 23 से 26 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-04(भाग-2) बुधवार, 25मार्च,2026/04 चैत्र,1948(शक्)अंक-25

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	विशेष उल्लेख(नियम-280)	6-31
3.	निंदा प्रस्ताव(नियम-114)	32-36
4.	ध्यानाकर्षण	37-39
5.	निंदा प्रस्ताव(नियम-114)	40-46
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	47
7.	माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जम्मू कश्मीर के 110 छात्र, छात्राओं का स्वागत	48
8.	सी.ए.जी. रिपोर्ट पर चर्चा	49-77
9.	विधेयक का प्रस्तुतिकरण	78
10.	वार्षिक बजट(2026-27) पर चर्चा	79-93
11.	माननीय अध्यक्ष द्वारा विधान सभा को धमकी वाले ई-मेल के विषय में सदन को सूचना तथा विपक्ष की सदन से अनुपस्थिति पर चिंता	94-96

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-04(भाग-2) बुधवार, 25मार्च,2026/04 चैत्र,1948(शक्)अंक-25

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 25.03.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्रं.सं.	सदस्य का नाम	क्रं.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	26.	श्री नीरज बैसोया
2.	श्री आले मोहम्मद इकबाल	27.	श्री ओम प्रकाश शर्मा
3.	श्री अभय कुमार वर्मा	28.	श्री पंकज कुमार सिंह
4.	श्री अजय कुमार महावर	29.	श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
5.	श्री अनिल कुमार शर्मा	30.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
6.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	31.	श्री पवन शर्मा
7.	श्री आशीष सूद	32.	श्रीमती पूनम शर्मा
8.	श्री अशोक गोयल	33.	श्री राज करन खत्री
9.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	34.	श्री राज कुमार भाटिया
10.	डॉ. अनिल गोयल	35.	श्री राज कुमार चौहान
11.	श्री गजेन्द्र दराल	36.	श्री रवि कान्त
12.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	37.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
13.	श्री हरीश खुराना	38.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
14.	श्री जितेन्द्र महाजन	39.	श्रीमती रेखा गुप्ता
15.	श्री कैलाश गहलोत	40.	श्री संदीप सहरावत
16.	श्री कैलाश गंगवाल	41.	श्री संजय गोयल
17.	श्री कपिल मिश्रा	42.	श्री सतीश उपाध्याय
18.	श्री करनैल सिंह	43.	श्रीमती शिखा रॉय
19.	श्री करतार सिंह तंवर	44.	श्री श्याम शर्मा
20.	श्री कुलदीप सोलंकी	45.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
21.	श्री कुलवन्त राणा	46.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

22.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	47.	श्री तिलक राम गुप्ता
23.	श्री मनोज कुमार शौकीन	48.	श्री उमंग बजाज
24.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	49.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
25.	श्रीमती नीलम पहलवान		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र 04(भाग-2) बुधवार, 25 मार्च, 2026/04 चैत्र 1948 (शक) अंक-25

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष (श्री मोहन सिंह बिष्ट) पीठासीन हुए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट (माननीय उपाध्यक्ष): सभी सम्मानित सदस्यों का मैं दिल की गहराईयों से आभार और अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सदन की एक स्वस्थ परंपरा और सदन के अंदर हम अपनी बात को ठीक ढंग से और अपने एरिया की समस्याओं को उठाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 280, मेरा डॉक्टर अनिल गोयल जी से अनुरोध है वो अपना 280 के तहत अपना विषय रखें। बोलिए अनिल जी।

<u>विशेष उल्लेख(नियम-280)</u>

डॉक्टर अनिल गोयल: माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद और आज इस सदन में आपकी अध्यक्षता में पहली बार 280 बोलने का मौका मिल रहा है इसके लिए भी धन्यवाद। पूर्वी दिल्ली में लंबे समय से जन-प्रतिनिधि और समर्पित निवासी के रूप में मैं आपका ध्यान बुनियादी ढांचे और नागरिक विकास की उन महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिनमें तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पूर्वी दिल्ली राजधानी के सबसे घनी आबादी वाले और तेजी से शहरीकरण होने वाले क्षेत्रों में एक है और फिर भी यह लगातार बुनियादी ढांचे की पुरानी बाधाओं, अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं, सीमित सामाजिक सुविधाओं से जोड़ रहा है और ये चुनौतियां लाखों निवासियों के दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और उत्पादकता को सीधे प्रभावित करती है। मैं आपको आपकी सहानुभूतिपूर्ण विचार आवश्यक कार्रवाही के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पहला पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र का पुनर्स्थापन एवं हैबिटेट सेंटर की स्थापना पूर्वी संस्कृति के एक दूरदर्शी सोच और धन भागीदारी के साथ किया गया था जिसमें करीब 4000 सदस्यों ने 25 हजार रुपये देकर करीब 12 करोड़ रुपये उसके इकट्ठे हुए थे और इसका एक उद्देश्य पूर्वी दिल्ली के निवासियों के लिए एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र बनाना था जहाँ वे सामाजिक, कलात्मक और शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले सकें। किंतु पिछले 12 वर्षों से यह महत्वपूर्ण संस्था निष्क्रिय बनी हुई है और अब इसको एक बैंक्वेट हॉल के रूप में परिवर्तित किया गया है जो की सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित थी, निजी

संस्थाओं को पट्टे पर दे दिया गया है, जिससे वास्तविक सदस्यों और व्यापक समुदाय को उनके अधिकारों और लाभों से वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग, निर्धारित उद्देश्य के विपरीत किए गए अनियमित आवंटनों की जांच हेतू एक स्वतंत्र जांच अत्यंत आवश्यक है अध्यक्ष जी ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष जी सी.बी.डी. ग्राउंड में पांच एकड़ भूमि जो मूल रूप से ईस्ट दिल्ली हैबिटेट सेंटर के लिए दी गयी थी, वो नागरिक एक सामुदायिक विकास के लिए आरक्षित थी। पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार, आपदा सरकार द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से आवंटित कर दी गई और इस भूमि को उसके मूल सार्वजनिक उपयोग के लिए पुन: बहाल किया जाना चाहिए। आज उसमें तीन-चार बैंक्वेट्स हैं जिनमें वो शादियां होती हैं जिसमें चलना भी सामने मुश्किल है। आपसे विनम्र निवेदन है कि पी.एस.के. के दुरुपयोग और सीबीडी ग्राउंड के भूमि के आवंटन की व्यापक ऑडिट जांच कराई जाए और पी.एस.के. को बहुउद्देशीय नागरिक सुविधा के रूप में पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित करके तत्काल कदम उठाएं, जिसमें कम से कम निम्नलिखित सुविधाएं हों। सामुदायिक जिम एवं वेलनेस सेंटर, सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं आर्ट गैलरी, सदस्यों और आगुंतकों के लिए रेस्टोरेंट कैफेटेरिया, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यशालाएं जिससे रोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। साथ ही सीबीडी ग्राउंड में हैबिटेट सेंटर की स्थापना पूर्वी दिल्ली के लिए केंद्रीयकृत सांस्कृतिक एवं बौद्धिक केंद्र के रूप में कार्य करेगी। ऐसा स्थान जहाँ कला, संस्कृति, नवाचार, सामुदायिक सहभागिता का समन्वय हो सके। इस प्रकार का विकास न केवल नागरिकों का विश्वास बहाल करेगा बल्कि पारदर्शी शासन और सार्वजनिक संपत्तियों के सम्मान का भी प्रतीक होगा। यहाँ पर माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बैठे हैं मैं जरूर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। टूरिज्म मिनिस्टर का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः नेक्स्ट, कुलदीप सोलंकी। जी कुलदीप जी बोलिए।

श्री कुलदीप सौलंकी: माननीय अध्यक्ष जी 280 पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपकी अध्यक्षता में आज पहली बार बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, आज कुछ नया-नया सा लग रहा है। अध्यक्ष जी, पालम गांव में एक पशु चिकित्सालय है बहुत पुराना 40-50 साल से और सब चीजों का ध्यान रखते हैं सभी लोग लेकिन पशुओं की भी कई बार दुदर्शा होती है, कहीं रोड एक्सिडेंट होता है, कहीं बीमार होते हैं। उनका ध्यान भी मैंने पहले भी, अरे भाई एक मिनट सुन लो रे चंदन भाई, आपका नम्बर भी आयेगा तो मैं भी होऊँगा यहीं पर। कोई बात चल रही है तो थोड़ा सा। सभी चीजों का ध्यान रखते हैं सभी मैम्बर, विधानसभा में भी रखते हैं लेकिन पशुओं की भी बड़ी समस्या कई बार होती है रोड

पर एक्सिडेंट, बीमार भी होते हैं। दिल्ली सरकार ने भी कल हमारे सीएम ने भी काफी बजट रखा इस बात पर रेखा गुप्ता जी ने कि भई इसका डव्लपमेंट किया जाये लेकिन समस्या क्या है मैं पहले भी इस बात को रखा है कि पशु चिकित्सालय में छोटे-बड़े मिलाकर कुल तीस हजार के आसपास उपचार होते हैं पूरे साल भर में। जिसमें छोटे पशु आते हैं कुत्ता, बिल्ली या पक्षी इस तरह के आते हैं लेकिन दवाईयों का इतना अभाव है कि लोगों को बाहर से ही खरीदकर लानी पड़ती हैं। केवल एंटी रैबिज ही सीमित है अन्य उपचार टीकाकरण, ऑपरेशन हेतु पर्याप्त दवाई नहीं मिलती हैं जिस कारण लोगों को आम तौर से अपनी जेब में हाथ डालकर और बाजार में भी जाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है ये इस बात को लेकर कि अगर पर्याप्त चीजें वहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से हों, अच्छे डॉक्टर हों, सुविधायें सारी अच्छी हों। तो इसको संज्ञान में लिया जाये। मैं मंत्रालय और मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर करवा रहा हूं कि भई इस चीज को ध्यान में लिया जाये, धन्यवाद जी।

माननीय उपाध्यक्षः रविन्द्र नेगी जी।

श्री रविन्द्र सिंह नेगीः आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी अध्यक्षता में मुझे 280 में बोलने का मौका प्राप्त हुआ और मैं आपके बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की डीडीए की बहुत सारी जमीनें हैं जो जनता के हित के लिये जमीनें हैं पर कुछ सालों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत से उन जमीनों में कब्जा हो चुका है। अवैध तौर पर लोगों ने भू-माफियाओं ने उस पर अतिक्रमण करके उनमें इमारतें खड़ी कर दीं, कईयों में चारदीवारी खड़ी कर दी, कईयों ने अपने बोर्ड लगा दिये। मेरी पटपड़गंज विधानसभा के एक पूर्वी विनोद नगर ईस्ट विनोद नगर में एक डीडीए का पार्क है जिसका खसरा नम्बर-32,33 और 79 ये तीन खसरा नम्बर में भू-माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश करी है और कुछ पर कब्जा भी कर लिया है। मेरा निवेदन है कि इस पर डीडीए द्वारा इस पर चारदीवारी कराई जाये, बोर्ड लगाये जायें और बताया जाये कि ये दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन है और पब्लिक इन्ट्रस्ट में इन जमीनों में पार्क बने, इन जमीनों में लाइब्रेरी बने, बुजुर्गों के लिये बैठने के लिये बने। इन जमीनों में पार्किंग बने और दूसरी बात एक खिचड़ीपुर सात ब्लाक मेरे यहां दो एकड़ की लैंड है इस लैंड में कुछ टाइम पहले एक अब्दुल नाम के कबाड़ी ने इसको घेरा हुआ था पांच एकड़, दो एकड़ लैंड को तो प्रशासन के माध्यम से हमने इसे खाली कराया और आज फिर इस लैंड में भू-माफियाओं ने कब्जा कर दिया है। मेरा निवेदन है कि इस जमीन को चारदीवारी कराके उस पे बोर्ड लगाये जायें डीडीए का और बताया जाये कि ये सरकारी जमीन है। इसी प्रकार खिचड़ीपुर गांव 311 खसरा नम्बर-316 खसरा नम्बर ये दो खसरा नम्बर 26 बीघा जमीन है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस

के टाइम पर इस जमीन पर अतिक्रमण हुआ और 2007 में इसपे स्टे भी मिला पर उसके बाद फिर कब्जा हुआ। मेरा निवेदन है इन जमीनों को खाली कराकर पब्लिक इन्ट्रस्ट की चीजें इस पर करी जायें क्योंकि बहुत सारी जमीनें हैं जो दिल्ली के लोगों के लिये काम आ सकती है। दिल्ली के विकास में काम आ सकती हैं पर वो भू-माफियाओं की भेंट चढ़ी हुई है। पिछली सरकारों में कोई सुनवाई नहीं थी। आम आदमी पार्टियों ने और कांग्रेस ने भू-माफियाओं को पाला हुआ था उनसे हफ्ता वसूली करते थे, महीना वसूली करते थे पर आज भाजपा की सरकार है मुझे पूरा विश्वास है कि इन जमीनों को खाली कराया जाये और जितनी भी जमीन पटपड़गंज विधानसभा के अन्तर्गत हैं उन जमीनों में चारदीवारी कराई जाये, उन जमीनों में बोर्ड लगाये जायें और बताया जाये ये जमीन किस यूज के लिये है। बहुत सारी जमीनें हैं जिसका लैंड यूज नहीं पता अगर लैंड यूज नहीं पता। अगर लैंड यूज हमें पता चल जाये तो हम दिल्ली सरकार के माध्यम से वहां पर्किंग बना सकें, वहां लाइब्रेरी बना सकें, वहां कम्यूनिटी सेंटर बना सकें। मेरा निवेदन है कि जितनी भी पटपड़गंज में जमीनें हैं इनका लैंड यूज जल्द से जल्द पता चले और इनमें चारदीवारी हो और बोर्ड लगे। आपने मुझे मौका दिया बोलने का मेरा पुनः दौबारा बोल रहा हूं मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी अध्यक्षता में आज बोल रहा हूं बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष: मेरा सम्मानीय सदस्यों से एक अनुरोध है, विशेष उल्लेख के तहत जो विषय हम लिखकर के देते हैं यदि उसी में आप बोलेंगे तो मेरे को लगता है मंत्री भी उस समस्या का समाधान करेंगे और समय भी बचेगा। अब श्री विशेष रवि जी(अनुपस्थित), करनैल सिंह जी।

श्री करनैल सिंह: अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया, सभी को जय श्रीराम और विशेष रूप से कल बजट सैशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। उन्होंने विशेष रूप से हरित दिल्ली के लिये और जल बोर्ड के लिये एक्स्ट्रा बजट रखा लेकिन मैं आपका ध्यान दिल्ली जल बोर्ड की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपसे मेरा अनुरोध है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन बदलने के लिये मेरी विधानसभा के काफी सारे एस्टिमेट दिल्ली जल बोर्ड में माध्यम से मंत्रालय में लम्बित हैं यदि सही समय पर कार्य नहीं हुआ तो रानी बाग, सरस्वती विहार और कुछ अन्य इलाकों में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जल भराव होने की समस्या बनी रहेगी। कृपया इस वर्क आर्डर को जल्दी से जल्दी बहाल करके मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको कार्यरूप में लेकर आयें। मेरा मंत्री जी से एक और महत्वपूर्ण निवेदन है मेरे क्षेत्र में एक सीवरेज एसपीएस बनाने की व्यवस्था की जाये क्योंकि हमारा सीवरेज रोहिणी सैक्टर-6 से होकर रिठाला जाता है जिससे मेरे क्षेत्र का सीवरेज डाउन होने में समय लगता है और बारिश के दिनों में सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होने की समस्या

उत्पन्न हो जाती है। मैं विशेष रूप से जो हमारे पैंडिंग जल बोर्ड के एस्टिमेट हैं पिछले छः महीने से मंत्रालय में उनको कार्यरूप में लिया जाये ताकि वो समय पर काम हो सके नहीं तो बरसात का मौसम आने वाला है फिर दौबारा से ओवरफ्लो होगा। अब भी मेरी विधानसभा में गंदा पानी आने की बहुत बड़ी समस्या है। मैं कई बार मंत्री जी के ध्यान में भी इस चीज को लेकर आया हूं तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। मैं पुनः अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करता हूं आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय उपाध्यक्षः चंदन कुमार चौधरी साहब।

श्री चंदन कुमार चौधरीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न एमसीडी के कुछ अधिकारियों एवं पार्किंग माफियाओं के बीच सांठ-गांठ, गुंडागर्दी तथा अवैध गतिविधियों के संबंध में है। मेरे क्षेत्र में रविदास मार्ग एक पार्किंग संचालित की जा रही है जिसके लिये मात्र 65 गाड़ियों की अनुमति दी गई है एमसीडी के द्वारा लेकिन उस माफियाओं के द्वारा लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर का पैच रोड कवर किया जाता है और उस पर अवैध पार्किंग किया जाता है। इससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यहार किया जा रहा है तथा उनके गुंडों द्वारा गाली-गलौच एवं धमकी दी जाती है जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और भी गंभीर बात यह है कि इस पार्किंग स्थल पर बीएसईएस के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से मीटर दे दिया जाता है अध्यक्ष जी और वहां पर ई-रिक्शा को चार्जिंग करने का प्वाइंट बनाया जाता है और उससे पैसे वसूली किये जाते हैं। मैं इस विषय को लेकर कई बार एमसीडी के अधिकारियों से कमिश्नर से, एडिशनल कमिश्नर से मिल चुका हूं प्रतिवेदन दे चुका हूं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग एक साल से उसको एप्लीकेशन देते-देते मैं थक चुका हूं। जिसको रिन्यू नहीं करना चाहिये उसको भी रिन्यू कर दिया गया और इस पार्किंग की वजह से लगभग छः मौत हो चुकी हैं अध्यक्ष जी और सभी लोग गरीब तबके के लोग हैं जिनके बच्चों सहित पिता की मौत हो चुकी है और बगैर एनओसी के पीडब्ल्यूडी के रोड पर एमसीडी के द्वारा पार्किंग माफियाओं को अलॉट किया जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा समाज को चलने वाले लोगों को हानि होती है। ट्रैफिक विभाग द्वारा लिखित में दिये जाने के बाद भी एमसीडी उसको और उस पार्किंग को डिलीट नहीं करती है किन्तु इनके बावजूद अधिकारियों के द्वारा इसे निरस्त करने के बजाय पुनः नवीनिकरण किया जाता है यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पार्किंग माफिया और कुछ अधिकारियों के बीच गहरी सांठगांठ है जिसके कारण जनहित की अनदेखी की जाती है और लोगों की जान जोखिम में डाला जाता है। अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब-जब मैं अधिकारियों से मिला तब-तब उस माफिया का फोन मेरे पास आया और जब मैंने एमसीडी के और बीएसईएस के अधिकारियों को थ्रैट करके मीटर उखड़वाया तो वो जो पार्किंग माफिया है अपने बाउंसर को लेकर के मेरे

ऑफिस पर धमकाने के लिये पहुंच गया, दुर्भाग्य रहा उस व्यक्ति का की मैं वैस्ट बंगाल चुनाव प्रचार में था जिसकी वजह से वो सही सलामत मेरे ऑफिस से चले गये ये दुर्भाग्य है। अध्यक्ष जी कि एमसीडी में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हम सरकार में हैं और हमारे फंड के द्वारा एमसीडी चलाई जाती है हम कहते हैं ट्रिपल इंजिन की सरकार है लेकिन एमसीडी हमारे अधीन नहीं आता है क्योंकि उनका अधिकारियों की मिलीभगत से डकैती की जाती है। अब ये सोचिये कि 65 गाड़ी का पार्किंग एलॉट किया जाता है अध्यक्ष जी और लगभग 300 से 350 गाडियां वहां लगाई जाती हैं। उस रोड की चौड़ाई मुश्किल से 50 से 60 फुट की होगी या 100 फुट की होगी। 80% रोड इनक्रोच्ड रहता है, जिसकी वजह से ये ऐक्सीडेंटल केस आते रहते हैं। इसलिए मौत हो चुकी है, लेकिन सैकड़ों उस रोड पर ऐक्सिडेंट हो करके घायल हो चुके हैं तो आप से अध्यक्ष जी विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र इस पर संज्ञान लिया जाए और उस पार्किंग को डिलीट करवाया जाए और उस माफिया को जेल भिजवाने का काम किया जाए। एक छोटा सा वाक्या और बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष जी जब मीटर लगाया गया तो बगैर किसी ऐप्लिकेशन का लगा दिया जाता है। मंत्री जी अभी है नहीं, नहीं तो उनके संज्ञान में भी ये बातें आ जाती। जब घर में मीटर लगवाने के लिए हम लोग बोलते है तो कहते है हाइट है, एमसीडी बुक है वो भी खत्म हो गया। लेकिन पार्किंग माफियाओं को मीटर दे दिया जाता है। जब मेरे द्वारा कंप्लेन किया जाता है, बीएसईएस अधिकारियों को तो वो मीटर उखाड़ लिया जाता है। लेकिन दूसरे दिन ही वहीं अधिकारी उस मीटर को लगाने के लिए आतुर हो जाता है। जैसे ही मेरे संज्ञान में बातें आती है, मैं अधिकारियों से पूछता हूँ कि ये कैसे तुम लगा रहे हो तो वो कहते है कि हमारे पास एमसीडी से परमिशन है। तो मैंने उनसे परमिशन मांगा कि ये कहां का परमिशन है, बताओ तो अध्यक्ष जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष :बोलिए आप बोलिए।

श्री चन्दन कुमार चौधर :अध्यक्ष जी, वो जब परमिशन मैं मांगता हूँ तो जिस एसी का उस पर साइन होता है, वो एसी 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और जब मैं अधिकारियों से कहता हूँ की ये एनओसी कैसे मिल गया मीटर लगाने के लिए तब जाकर के उनका ध्यान खुलता है और कहते हैं नहीं ये फेक लेटर है, हमने लेटर इश्यू नहीं किया। उसके बाद जब मैं अधिकारियों को कहता हूँ कि ये फेक लेटर है, इसको इमीडिएट लेटर लिख करके सत्यापित करो तो वो कहते है की बीएसईएस के बड़े अधिकारी का कॉल आया था, जिसकी वजह से मुझे लगाना पड़ रहा है। फिर मैं उस विशेष अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी से जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं, हमारे पास अधिकारियों का फ़ोन आया था तो हमने कहा कौन से अधिकारी का फ़ोन आया था। तो बीएससीएस उर्जा मंत्रालय के द्वारा फ़ोन आया था, जब मैं वहाँ मंत्रालय में पता करता हूँ तो उनका कहना होता है कि ये मेरे संज्ञान में आया था लेकिन मेरा कोई

सत्यापित किया हुआ नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ मंत्री जी भी आ गए हैं, आप के माध्यम से मंत्रीजी से भी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि किसी पार्किंग माफियाओं को मीटर ना दिया जाए और अवैध तरीके से चार्जिंग पॉइंट जो ई -रिक्शा का बनाया जाता है उसको रोका जाए और अविलंब उस पार्किंग को डिलीट किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट,माननीय उपाध्यक्ष : श्रीमती शिखा राय जी।

श्रीमती शिखा राय: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ ये विषय मैंने पहले भी लिया था ये इसलिए दोबारा से लेने के लिए मैं बाध्य हुई हूँ कि ये इसी समय का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये चिराग दिल्ली मेरे यहाँ फ्लाइओवर एक है जी जिसके नीचे कि इंटरसेक्शन पर जो जैम लगता है उसके विषय में मैं यहाँ अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारी जो रोड बीआरटी कॉरिडोर कहलाती है, उसके ऊपर से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर जाता है, जिसके नीचे का लाइट का पॉइंट ऐसा है कि उसकी पीक ऑवर्स में वहाँ से शुरू हुआ जैम पीछे मूलचंद तक जाता है। अध्यक्ष जी, वहाँ उसी रोड पर अब मेट्रो भी अपना एक और way निकाल रही है जो साकेत तक जाएगा। तो मेट्रो ने अपनी कार्यवाही वहाँ पर ऐक्टिविटी शुरू कर दी है उस कोरिडोर पे जिसके कारण से अब आने वाले समय में और भयंकर वहाँ पर स्थिति होने वाली है। इसलिए इस दौरान में माननीय मंत्री जी के माध्यम से दो बार अधिकारियों से बातचीत भी हुई। उन्होंने अधिकारियों को बुला करके इस विषय पर संज्ञान लिया भी और अधिकारियों के साथ चर्चा भी हुई, और वहाँ पर से यह निष्कर्ष निकला था उस चर्चा से कि उस रोड के ऊपर इस इंटरसेक्शन के दोनों तरफ दो अंडरपासिज यू अंडरपासिज बनने चाहिए। ये उस मीटिंग में निष्कर्ष निकाला था लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है या हो रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है और क्या अधिकारियों ने निर्णय लिया है उसके ऊपर क्योंकि उन मीटिंग्स में ये निष्कर्ष निकाला था कि दोनों तरफ यू अंडरपासिज बनने चाहिए। अगर उनकी प्रक्रिया अभी से शुरू नहीं होगी तो एक बार मेट्रो अपना खुदाई जो शुरू करने वाली हैं अभी उनकी soil जांच हो रही है। वो शुरू कर दिया तो उसके बाद से वो उस पे बनना असंभव हो जाएगा और ये पाइंट जो है लगातार एक बहुत भयंकर स्थिति में आ करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से है कि कृपया इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हो और जो मीटिंग्ज़ में आपने निर्णय लिया था कि यू अंडरपासिज रोड के दोनों तरफ उस पॉइंट पे बनने वाले हैं। उसके लिए क्या प्रोग्रेस प्रक्रिया आपने आगे शुरू की है, इसकी जानकारी हो और अगर नहीं की है, तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कुलवंत राणा जी। ये 280 है और जिन्होंने लिख के दिया है तो निश्चित रूप से उनका अधिकार है। उन्होंने मेहनत तो की है, 280 लगाने में मेहनत की है विषय को अच्छी तरह से जांचा परखा, बोलिए कुलवंत जी।

श्री कुलवंत राणा :अध्यक्ष जी धन्यवाद और ये राजकुमार जी आपका काम कर रहे हैं आज। अध्यक्ष जी आप एक अनुभवी नेता हैं, और आपकी लीडरशिप में सदन बहुत अच्छा चल रहा है और आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि ये आले हमारा सदस्य मेंबर हैं सदन में है उपस्थित है, उसका स्वागत करें सब लोग, एक अच्छा सदस्य के नाते ये सदन अटेंड कर रहा है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: बोलिए प्लीज।

श्री कुलवंत राणा :अध्यक्ष महोदय तो मैं एक बहुत अहम विषय पर 280 में उल्लेख कर रहा हूँ विषय है, दिल्ली में जो अधिकारी है अध्यक्ष महोदय,

.....व्यवधान........

श्री कुलवंत राणा : हाउस को आर्डर में लाओ अध्यक्ष जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: बोलिए सर।

श्री कुलवंत राणा: तो मैं एक अहम विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसमें मंत्रिमंडल के साथी भी संज्ञान लेंगे और सभी हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं ये उनसे संबंधित हैं। दिल्ली में एक व्यवस्था बनाई, पॉलिटिकल भी विधानसभाएं गठित की, कॉर्पोरेशन दृष्टि से वार्ड गठित किए, लोकसभा गठित की उसकी भी एक सीमाएं हैं। इसी प्रकार से जीतने भी दिल्ली में विभाग कार्यरत हैं। इन सबके भी एक व्यवस्था डेवलप की एक hierarchy बनाई जेई, एई, एक्सईन, एससी, चीफ above चीफ,सैक्टरी। अध्यक्ष महोदय, एक विधायक बताएगा की यहाँ मेनहोल का ढक्कन गायब है, ये एक सड़क में गड्ढा है, ये पानी लिक है, ये पार्क की दीवार टूटी पड़ी है विधायक साथी सुपरवाइजर है क्या अध्यक्ष महोदय। हम लोग सुपरवाइजर है विभागों के कितना बर्डन लेंगे और प्रत्येक जेई एई एक्सईन तनख्वाह लेता है,उसका क्षेत्र बंटा हुआ है, उसके जवाबदेही बंटी हुई है, उसको बजट ऐलोकेट है, या मलबा पड़ा है यहाँ पर, ये पेड़ टेढ़ा हुआ किसी की जान ले लेगा, ये पीडब्ल्यूडी की ग्रिल है बाहर आई हुई है, किसी गाड़ी टकराकर मर जाएगा ये अहम विषय है। मेरा संदर्भ जो आज इस विशेष उल्लेख में चर्चा मैं कर रहा हूँ उसका एक उद्देश्य है कि आप रिंग रोड पर जाओ कहीं स्लैब पड़ा है, कहीं पाइप पड़ा है, कहीं मलबा पड़ा है, कहीं कूड़े का ढेर पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा सड़क के ऊपर कोई गाड़ी चली गयी तो मर गया पीछे से कोई भी एनडीपीएल वाला आया ठेकेदार काम करके चला गया वो पुराने खंबे छोड़ के चला गया। कोई पाइप छोड़ के चला गया क्या दिल्ली का कोई माँ बाप

नहीं हैं क्या, दिल्ली लावारिस है क्या, या मरने के लिए छोड़ दिया सब को और इसको कुरूप बना दो दिल्ली को व्यवस्थित दिल्ली की बजाय कुरूप दिल्ली बना दिया। इसकी व्यवस्था बिगाड़ दी, इसकी सुन्दरता बिगाड़ दी। इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है दिल्ली के साथ। तो जो व्यक्ति तनख्वाह लेता है, हमें भी जनता ने काम दिया है। हम भी उसकी जवाबदेही समझते हुए काम करते हैं कि अधिक से अधिक सुविधा कैसे आये क्षेत्र में। हमारा काम विधायी कार्य का है। हम सुपरवाइजर का कार्य हमारा है, या हम रोज़ उनके साथ मत्थापच्ची करें, छोटे-छोटे काम के लिए? तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनती कि आप जवाबदेही के साथ काम करें और जो हमारा नीती निरधारण का काम हम वो काम करें। उनका काम ना करके और दिल्ली एक बेहतर शहर तभी बनेगा, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से जब तक जवाबदेही निश्चित नहीं होगी, ये शहर सुंदर नहीं हो सकता। ये सुन्दर नहीं बन पाएगा। कोई जमीन पे कब्जे कर रहा है। कोई कुछ कर रहा है। सरकारी जमीन को घेर के कब्जे कर रहा है। कोई कहीं भी मंदिर, मस्जिद बना देता है। ये हो क्या रहा है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: अब sum-up कर लीजिए प्लीज।

श्री कुलवन्त राणा: नहीं मैं समाप्त तो करूँगा, समाप्त तो मुझे करना पड़ेगा मेरी समय सीमा है। लेकिन मुझे ये बताओ वहाँ पे ये दूर होगा कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: कुलवंत जी आप समाप्त कीजिए।

श्री कुलवन्त राणा: मैं सम्मानित सदस्यों से पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय मेरा विषय कोई गलत तो नहीं है? क्या ये नहीं होना चाहिए ऐसा? क्या दिल्ली को हम ऐसे ही बदतर बनाते रहेंगे? मैं अध्यक्ष महोदय एक बात और बोलूंगा, नहीं अध्यक्ष महोदय इतना बड़ा बजट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि आपके डिपार्ट्मेन्ट जो है सुनिए, उन्होंने जो विषय रखा, उन्होंने चिंता किया। पूरे विधानसभा के अंदर उसको वार्ड के आधार पर उसको वो किया गया है। लेकिन जो डिपार्ट्मेन्ट हैं जो आप लोगो के पास डिपार्ट्मेन्ट हैं मान लिया पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेन्ट है, उससे संबंधित roads हैं, उसको कौन देखेगा, कौन उसकी व्यवस्था को करेगा? मेरा इसमें एक सजेशन है। मैं ये चाहता हूँ कि अधिकारी ऐसे roads को जिनको विधायक जी ने कहा है उनको चिन्हित करें और तुरंत उसका समस्या का समाधान होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता।

श्री कुलवन्त राणा: अध्यक्ष महोदय में एक और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: हो गया सर।

श्री कुलवन्त राणाः दिल्ली में दिल्ली में सड़कें छोटी पड़ गई, लोग बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया। एनडीपीएल हो, बीसईएस हो, वो जायेगा खंबा गाडना है ये नहीं देखेगा सड़क की परिधि में छोटी कर रहा हूँ वो खंबा जहां मर्ज़ी गाड रहा है। मतलब कोई गाइडलाइन्स नहीं है। हर विभागों की गाइडलाइन्स जारी करनी चाहिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः सर मैंने बोल दिया ना। मैंने बोला है चेयर की ओर से

श्री कुलवन्त राणाः आपका काम करने का पैमाना ये होगा। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय विभागों को पैसा हम खर्च करते हैं, कितना बजट खर्च होता है साल में। वो कार्य गुणवत्तापूर्वक हो, सही दिशा में हो, सही तरीके से हो। अभी आप आउटर रिंग रोड पे जाओ आप। आउटर रिंग रोड के ऊपर एक जगह है, बहुत बड़ा ऊंचा बना रखा है। किसी गाड़ी चढ़ गई और पलट गई रात को तो मर जायेगा वो। दुर्घटना के लिए ऐसी जगह क्यों छोड़ते है आप?

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः कुलवंत जी ।

श्री कुलवन्त राणाः तो मेरा इतना आग्रह है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः नहीं अब sum-up कीजिए प्लीज़।

श्री कुलवन्त राणाः तो मैं इतना आग्रह करूँगा किसी भी विभाग की लापरवाही के कारण कोई मृत्यु होती ह,। तो उसकी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होनी चाहिए, उसके खिलाफ़ एफ.आइ.आर. होनी चाहिए और साथ साथ उसके खिलाफ़ अपराध वाला केस चलना चाहिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः जी, sum-up कीजिए प्लीज़ ।

श्री कुलवन्त राणाः ऐसा मेरा आग्रह है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए हार्दिक रूप से आपका बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः हरीश खुराना जी,

.....व्यवधान........

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः बाद में लेना पहले 280 पूरी हो जाये।

श्री अजय महावरः अच्छा 280 ।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः हरीश खुराना जी ।

श्री हरीश खुरानाः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान और मंत्री जी का ध्यान मेरी मोती नगर विधानसभा की गंभीर समस्या, मेरे को लगता है कि वो पूरी दिल्ली की भी आज गंभीर

समस्या बन गई है कि जिस प्रकार से ओपन में मीट शॉप की दुकानें चल रही हैं। उसकी तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का। ये ध्यान ये जो समस्या है ओपन मीट शॉप जो हैं। बिना किसी लाइसेंस के बिना किसी नाम के चल रही हैं और ना कोई FSSAI लाइसेंस है, ना फूड सेफ्टी है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से ना सिर्फ प्रदूषण हो रहा है। बल्कि गंभीर समस्याएं भी पैदा हो रही हैं स्वास्थ्य संबंधी और ना सिर्फ। इसकी वजह से साफ सफाई। वो जो कचरा होता है वो नालियों में। वो कचरा पीने की पाइप में कई बार पीने की पाइप लाइन में चला जाता है। उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है की वो वक्त आ गया है कि जो फूड सिक्योरिटी जो फूड सेफ्टी है, उसपे एक गंभीर लॉज बनने चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चालान भेजना, सिर्फ एक नोटिस भेज के अब काम चलने वाला नहीं है क्योंकि वो सिर्फ नोटिस सर्व हो जाता है और भ्रष्टाचार की वजह से। avoid हो जाता है और दुकानें निरन्तर चलती रहती है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या आ रही हैं। एक गंभीर लॉ बनना चाहिए जिसमें दुकानों की सीलिंग तक का प्रावधान होना चाहिए। और मैं निवेदन करूँगा माननीय मंत्री जी से कि इसका संज्ञान लेते हुए इस फूड सेफ्टी के ऊपर इनका तुरंत से तुरंत इनके ऊपर गंभीर ऐक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमती नीलम पहलवान जी।

श्रीमती नीलम पहलवानः माननीय अध्यक्ष जी। मैं आप के माध्यम से नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों से जुडे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। दिल्ली देहात के विभिन्न गांव के निवासी एवं किसान लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी कृषि भूमि का सर्कल रेट पिछले लगभग 18 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान में कृषि भूमि का सर्कल रेट लगभग 53 लाख प्रति एकड़ निर्धारित है जो कि वर्तमान बाजार मूल्य तथा पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इस कारण किसानों को अपनी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि कृषि भूमि का सर्कल रेट यथार्थ के अनुरूप बढाया जाए। विकास कार्यों को लेकर यदि भूमि का अधिग्रहण वर्तमान सर्कल रेट पर किया गया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली देहात की कृषि भूमि के सर्कल रेट का शीघ्र पुन:र्निर्धारण किया जाए। जब तक नए सर्कल रेट निर्धारित नहीं होते तब तक किसी भी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस विषय पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए। अध्यक्ष जी यह विषय दिल्ली के हजारों किसानों की आजीविका और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अंतः इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी अत्यंत आवश्यक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण

बात है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के सदस्य जनहित के मुद्दों को छोड़कर केवल अपनी जेबें बढ़ने और भ्रष्ट नीतियों से उलझे रहे। एक के साथ एक फ्री जैसी शराब बिक्री की योजना को बढ़ावा देने में वह इतने व्यस्त रहे कि दिल्ली के अन्नदाता किसानों के हितों की ओर ध्यान देने तक का भी समय नहीं मिला। यह खेदजनक है की जिस किसान के परिश्रम से समाज का पेट भरता है, उसी किसान के अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा की लगातार अनदेखी की गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से दिल्ली की जनता को बहुत आशायें हैं। जनता को विश्वास है कि हमारी सरकार पारदर्शी और जनहित कार्य निर्णयों माध्यम से इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी तथा किसान को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करेगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी विधानसभा का मुद्दा रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः गजेंद्र दराल जी।

श्री गजेन्द्र दरालः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप की अध्यक्षता में मुझे अपनी मुंडका विधान सभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित समस्या से जुड़ा हुआ एक मुद्दा रखने का मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ के मुंडका विधान सभा लगभग जिसका 30 किलोमीटर का एरिया है। जो टटेसर गांव से शुरू होकर और विकासपुरी से टच होती हुई लास्ट जो मेरा वार्ड वो चंद्रविहार है और मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल ना होने के कारण जहाँ व्यक्ति इमर्जेन्सी में अपना इलाज करा सके उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और साथ में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के, कि कंझावला गांव में लगभग छे एकड़ जमीन के अंदर एक 100 बैड का हॉस्पिटल आज से लगभग 10-15 साल पहले बनकर तैयार हुआ था, जिसमें लगभग एक या 2 साल तक इमर्जेन्सी के तौर पर वो हॉस्पिटल चालु रहा। लेकिन आज उस 6 एकड जमीन के अंदर वो 100 बेड की बिल्डिंग भी तैयार है और वहाँ पर जैसे ही दिल्ली के अंदर जो बदलाव और जो विकास की सरकार चुनी गईं, तो उसी बिल्डिंग के अंदर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन कर हर उस व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाने की वो सारी सुविधाएं तो मिल गईं, लेकिन एक इमर्जेन्सी हॉस्पिटल ना होने के कारण मेरे क्षेत्र के लोगों को या तो संजय गाँधी हॉस्पिटल या बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है और कई बार तो जाम को देखते हुए, क्योंकि रोड बड़ी तंग है और कई बार उसके परिणाम बड़े गंभीर हो जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री से ये आग्रह है कि जो वहाँ पर एक100 बेड की बिल्डिंग तैयार है, सिर्फ उसके अंदर जो यूनिट लगनी है, जो स्टाफ लगना है, उस स्टाफ को वहाँ पर भेजकर दोबारा से उस इमर्जेन्सी वार्ड को लोगों के हितों के लिए, उनकी स्वास्थ्य संबंधित

समस्याओं को हम भली भाँति वहीं पूरा कर सकें, उसको चालू करने की जरूरत है। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: अध्यक्ष जी मेरा एक प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है, मेरी विधानसभा से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे बस क्योंकि.....

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: सुनिये प्वाईंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं होता है जब क्वेश्चन सुनिए सुनिए सुनिए आप मुझे मत बताए, प्वाईंट आफ ऑर्डर कहाँ होता है? ये प्वाईंट आफ ऑर्डर नहीं है, ये 280 है उसमें बिल्कुल किसी भी हिसाब से ही ये अलाउ नहीं किया जाएगा, 280 चल रहा है 280 के बाद आपने यदि कोई सब्जेक्ट लिख करके सदन।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: अध्यक्ष जी बहुत अहम है कि आज जो हमारे इलाकों में, क्षेत्र में जो सिलेंडर को लेके काला बाजारी कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: अरे भैया ये 280 पर चर्चा हो रही है इसके बाद बात करिए आप।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: अध्यक्ष जी ऐसे तो आप बोलने ही नहीं देंगे।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: नहीं बोलने क्यों नहीं देंगे? हमने तो बोलना वो भी देखा हम सब का हम आपका भी सम्मान करते हैं। यदि आपने कोई 280 में कोई विषय लिख के दिया होता तो निश्चित रूप से उस में चर्चा करवाते। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना प्लीज़ बैठ जाएं, बैठ जाएं, हाउस को डिस्टर्ब ना करें आप बैठ जाइए प्लीज़, हाउस को डिस्टर्ब ना करें। राजकुमार भाटिया जी।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: 280 में बोलने दीजिये।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: 280 आपने लिख के दिया हाउस को?

श्री आले मोहम्मद इकबाल: नहीं वो प्वाइंट आफ आर्डर में।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: नहीं प्वाईंट ऑफ ऑर्डर इसमें अलाउ है ही नहीं, 280 में आज तक यह इतिहास दर्शाता है कभी भी उसमें कभी प्वाईंट ऑफ ऑर्डर होता ही नहीं है। लेकिन अब सब्जेक्ट पे बोलिये और यदि आपको इतना ही आप उसके प्रति इतना सोच रहे है साहब मैं इतना गंभीर हूँ तो लिख के देना चाहिए। राजकुमार भाटिया जी प्लीज़ बोलिये।

श्री राजकुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आप इस पीठिका पर विराजित हैं हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। मैं आपको आपके नेतृत्व में विधानसभा के इस सत्र परिचालन

में 280 के अंतर्गत आपने बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस विषय पर पिछले वर्ष 280 के तहत ही मैंने इस विषय को उठाया था। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 1984 के सिख दंगों के पीड़ित और पंजाब से आए हुए विस्थापित परिवारों को ड्यूसिब के छोटे क्वार्टर्स में शिफ्टेड किया गया था। उन क्वाटर्स की हालत बहुत खराब है लेकिन किन्हीं वजहों से पिछली सरकारों की गैर संवेदनशीलता के कारण उन पंजाबी फ्लैट जिसको बोलते हैं एक्सवाईजैड, उनके जो निवासी है, आज भी अलॉटमेंट से वंचित हैं। आदरणीय आशीष सूद, मंत्री जी ने इस विषय पर संज्ञान लिया और अध्यक्ष जी मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा।

....व्यवधान.....

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: प्लीज, हाउस को, बोलने दीजिए उनको।

श्री राजकुमार भाटिया: बहुत संवेदनशील विषय है जहाँ एक और श्री नरेंद्र मोदी जी ने।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: सीरियस ही होना चाहिए हाउस को सीरियसली ही चलाना चाहिए।

श्री राजकुमार भाटिया: श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी का गठन करके उन दंगा पीड़ित परिवारों के हितों की रक्षा की है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब से विस्थापित और दिल्ली के सिख पीड़ित दंगा पीड़ित परिवारों के फ्लैटों की चिंता हमें करनी चाहिए। आदरणीय आशीष सूद जी ने यूडी मिनिस्ट्री के माध्यम से एनओसी तो दे दिया है लेकिन आज भी ड्यूसिब उनकी अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है यह विषय मैंने पिछले वर्ष उठाया था, फाइल अभी तक मूवमेंट में है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूँगा कि उन परिवारों को तुरंत अलॉटमेंट लेटर दिया जाए, जो भी उनका फीस बनती है, जो भी उनका है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि विलंबन जो है सरकार की तरफ से हुआ है, इसके ऊपर कोई जुर्माना या पेनल्टी ना लगाई जाए,आदरणीय आशीष सूद जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और जो खाली पड़े फ्लैट्स हैं उन पर निरंतर कब्जे होते जा रहे हैं, अवैध लोग उन पर कब्जा कर रहे हैं, उन फ्लैटों को निरंतर जो है हथिया रहे हैं, कब्जा रहे हैं, बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, उनको बता दिया गया है कि ये डेंजरस है, लेकिन जो हथियाने वाले हैं उनके लिए कुछ भी डेंजरस नहीं होता उनके लिए तो उस मकान की कीमत आज जो है, कई लाखों रुपए में हो चुकी है और इसी के साथ साथ हमारे क्षेत्र में ये भी मैंने लिखित में दिया हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो रविंदर भाई ने मुद्दा उठाया है। डीडीए की अनेक जमीनें ऐसी पड़ी है जहाँ नीले और सफेद बोरे भर भर के कबाड़ रख दिया गया है, एसटीएफ के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से जब ड्राइव चलाई जाती है तो एक घंटे के अंदर अंदर वो

सामान वहीं का वहीं वापसी आ जाता है किसी भी प्रकार की उस पे कार्रवाई नहीं होती और बहुत अफसोस की बात है कि उन खाली जगहों पर बिजली विभाग ने पिछली सरकार के मिलीजुली से वहाँ पर बिजली के मीटर लगाए हुए हैं, अंदर एक एक कमरे के पोर्टा कैबिन पड़े हुए हैं, जहाँ पर अवैध कार्रवाई या चल रही है, इल्लीगल ऐक्टिविटी चल रही है, बार चल रहे हैं, सट्टा चल रहा है, ये सब चीजें वहाँ पर चलती है, लेकिन सरकार का ध्यान, एसटीएफ का ध्यान, एमसीडी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी के माध्यम से इस दोनों विषयों पर संज्ञान चाहूंगा। खाली जमीन को कब्जामुक्त करवाया जाए और जो हमारे पंजाबी फ्लैट्स हैं एक्सवाईजैड जहांगीरपुरी में, उनको तुरंत अलॉटमेंट लैटर दिलवाने की कृपा करें, ये 280 के तहत मुद्दा है।

श्री अभय वर्मा, मुख्य सचेतक: आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी लगभग 14 मिनट बचा हुआ है जिनके 280 अप्लाई हुए हैं उनको।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: बिल्कुल।

श्री अजय कुमार महावर: अध्यक्ष महोदय 114, 107 पर भी अध्यक्ष जी लगा हुआ है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: 114 वैसे लिख के देना चाहिए।

श्री अजय कुमार महावर: नहीं लिख के दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: 114 के तहत लिख के आपके पास कोई मैटर आया है क्या?

श्री अजय कुमार महावर: लिख के दिया हुआ है? दोनों विषय जो लिखकर दिये हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: किसी सब्जेक्ट को उठाने से पहले, चलो आपने दिया है अच्छी बात है, लेकिन सदन के अंदर एक परिपाटी हमको डालनी पड़ेगी, ये सदन नियम और कायदे और कानूनों से चलता है मान लिया वो नौ या साढे नौ बजे वो देना है आपने वो लेटर दिया तो ये अच्छी बात है लेकिन।

श्री अजय कुमार महावर: तीन दिन पहले दे दिया।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आज के बाद हम एक ऐसी व्यवस्था जरूर करें ताकि मंत्री भी जवाब दे सकें, उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके, इस प्रकार का होना चाहिए, बिलकुल आपको बोलने का समय देंगे। नेक्स्ट, राज करण खत्री जी।

श्री राजकरण खत्री: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान यमुना नदी में होने वाले अवैध खनन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरी नरेला विधानसभा के

लगभग 10 किलोमीटर के हिस्से से यमुना नदी गुजरती हैं जिसके प्रमुख गांव में पल्ला, सुंगरपुर, झिंगोला, रमजानपुर, मोहम्मदपुर, हिरनकी और अन्य गांव आते हैं, जिनसे रेत माफिया भारी मात्रा में अवैध तरीके से रेत निकालते हैं और यह बहुत बड़ी मात्रा में होता है यमुना के बांध पर लगी स्ट्रीट लाइटों की वायर तक को ये लोग चुरा लेते हैं और वहाँ बिल्कुल रात को चोरी के लिए अंधेरा करते हैं।

(11.49 बजे माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता पीठासीन हुए)

श्री राजकरण खत्री: लेकिन इसमें कई बार सरकार का ध्यान दिलाया गया है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से रेत माफिया चोरी करते हैं बड़ी मात्रा में। आपका मैं ध्यान इस तरफ दिलाता हूँ कि यह अवैध खनन दिल्ली का जो एरिया पड़ता है उसमें ना होए। आपका ध्यान पहले भी कई बार दिलाया गया है और मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में दिन और रात 24 घंटे ये काम चलता है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अभी।

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: अध्यक्ष जी, इसमें तय यह हुआ था कि समय बच गया है तो जिनके 280 आये हुए हैं, उनको आज बोलने का मौका मिल जाये तो अब शायद संजय गोयल जी का रहता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: संजय गोयल जी, नहीं, 280 जो है।

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: 15 हो गए हैं, 15 के बाद भी जिनके आए हुए हैं उनको आप opportunity दे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र महाजन जी।

श्री जितेन्द्र महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का ध्यान आईजीएल के द्वारा किये जा रहे हैं काम की ओर दिलाना चाहता हूँ। रोहतास नगर विधानसभा में पिछले तीन सालों से आईजीएल की लाइन डालने का काम चल रहा है, यह काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। दस बीस दिन काम किया जाता है और दो तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है। वहाँ के लोगों ने एक ही मोहल्ले के अंदर कुछ लोगों को आईजीएल का कनेक्शन दिया जा रहा है और कुछ लोगों को आईजीएल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जबकि आईजीएल के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया वो पूरी रोहतास नगर विधानसभा में सभी लगभग सभी लोगों ने करवाया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस काम को गति दी जाए और जिन लोगों को आईजीएल

के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उन लोगों को आईजीएल का कनेक्शन दिलवाया जाए, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री रविकांत जी।

श्री रविकांतः आदरणीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 280 के तहत आपने बोलने का अवसर दिया, लेकिन ये जो विषय लेकर आज मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ, ये मुझे लगता है कि स्टार्ड क्वेश्चन में लगाने का विषय था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि मैं आज आपके सामने केवल एक जन प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे समाज का प्रतिनिधि बनकर खड़ा हूँ जिसने इस देश को और इस राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए अपनी पीढ़ियां समर्पित कर दी हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह सबसे पहले उठते हैं ताकि शहर जाग सके, यह वो लोग हैं जो खुद धूल में रहते हैं ताकि दिल्ली चमक सके। हमारे सफाई कर्मचारी साथियों ने कभी अपने कर्तव्य से पीछे हट कर नहीं देखा है और चाहे सुबह हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, उन्होंने हमेशा इस शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरी सरकार से मेरा निवेदन है कि ये सिर्फ नौकरी का विषय नहीं है, यह एक विश्वास का विषय है और ये उन परिवारों के भविष्य का विषय है जो पूरी ईमानदारी से इस शहर और इस देश की सेवा कर रहे हैं। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अनेक अवसरों पर वाल्मीकि समाज के योगदान को सराहा है और कहा है कि स्वच्छता के प्रति समर्पण ही सच्ची सेवा है और सफाई कर्मचारियों की स्वच्छता, सिपाही को उन्होंने बताया है। उन्होंने समाज के सम्मान, गरिमा और उत्थान के लिए लगातार प्रयासों पर बल दिया है, लेकिन दुर्भाग्य वश जो समाज देश को स्वच्छ बना रहा है, वही आज असुरक्षा का सामना कर रहा है। अधिकांश पूरे देश भर में और पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा दिल्ली भर में वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका हमारे इस देश के अंदर रहता है। मैं ये बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि कब तक बीस पच्चीस साल सेवा देने वाला कर्मचारी दिहाड़ी मजदूर बना रहेगा, कब तक उसका भविष्य अधर में लटका रहेगा, कब तक उसके बच्चों का सपना अधूरे रहेंगे? आज भी उन्हें पक्के कर्मचारी नहीं बनाया गया है। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, यह सवाल हर उस परिवार का है जिसने अपने जीवन के साल इस शहर को दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही है। उन परिवारों का क्या जिनका सहारा भी छिन गया है? उन कर्मचारी जो डेथ केस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किये हुए हैं, जिन्हें 10-15 वर्ष सेवा करते हो चुके हैं, वे आज भी पक्के कर्मचारी नहीं बन पाए हैं। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे को केवल एक फाइल की तरह ना देखा जाए यह सब की संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है, उन हजारों परिवारों का जिंदगी के सवालों का विषय

है, उन बच्चों के सपनों का सवाल है जो उनके माता पिता को दिन रात मेहनत करते हुए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सामाजिक समरसता के विजन को आगे बढ़ाते हुए इन कर्मचारियों को उनका उचित अधिकार और स्थायित्व दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं क्योंकि यह कोई मांग नहीं है यह उनका अधिकार है, यह कोई अहसान नहीं होगा, ये उनका न्याय होगा। हम सब मिलकर ऐसी दिल्ली बनाए जहां शहर को साफ रखने वाले हाथ खुद भी सुरक्षित, सम्मानित जीवन जी सकें। यह मेरा निवेदन है कि सरकार इस चीज़ में अवश्य ध्यान देगी और मेरी सरकार जो दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर एक व्यक्ति को सामाजिक समरसता के भाव से जोड़ रही है, मुझे लगता है कि वाल्मीक समाज को भी इस तरीके का सम्मान देकर सरकार जो सामाजिक समरसता का भाव जो चला रही है वो हर जन तक पहुंचेगा, इन्हीं सब कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय उपाध्यक्ष, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी सरकार द्वारा कल 2026 और 27 का बजट प्रस्तुत किया गया। उस बजट के अंतर्गत जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भूमिगत केबल डालने के लिए जो ₹200 करोड़ बजट का प्रावधान रखा उसके लिए मैं अपनी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूँ कि जहाँ ग्रामीण उनके नाम से सिर्फ दो गांव है, बाकी 50 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में 99.9% लोग वो लोग रहते हैं कि वास्तव में जिनको ये मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना दी गयी है, उसका सीधा सीधा लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ और अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसी कॉलोनियां जहां पानी की निकासी ना हो, बंद गलियां हो, 15-15 फिट या 10 या 12 फिट हों, यदि मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद के अंतर्गत इन सारी कॉलोनियों में वायरलैस कार्य हो जाए तो मैं यह बात कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी क्षेत्र की जनता क्या, दिल्ली की जनता भी जो भी अनऑथराईज कॉलोनी में रहते हैं, आथोराइज़ कॉलोनीज़ में रहते हैं एक ट्रैक सिस्टम बना करके उन लाइनों को नीचे डाल दिया जाए, पोल हटा दिए जाएं, लाइट की एक्स्ट्रा व्यवस्था की जाए वास्तव में यह दिल्ली बहुत ही सुंदर दिल्ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी विधानसभा की वैसे तो बहुत सी बातें हैं क्योंकि और मित्रों को भी बोलना है, आपने बोलने का समय दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहो इतनी देर आपने सेशन कराया है बोलो आप।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: सर, मैं एक केबल की जो समस्या है ये सबसे खतरनाक है। एक अभी हमारा मेंबर है जिस प्रकार से अनऑथॉराइज़ कॉलोनी जो अथोराइज्ड कॉलोनी जो ये केबिल वाला आता है, केबिल खोद देता है, पूरी लाइनें खोद देने के बाद क्या करता है गड्ढों पे ध्यान नहीं करता, देता, लोग उस समय में विधायको के घरों पर जाते हैं भगवान ना करे कहीं 19-21 हो गया तो विधायक के खिलाफ़ एक पूरा माहौल बना दिया जाता है। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आप अपनी सरकार है, हमारी सरकार का एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए अधिकारियों को भी डर लगना चाहिए, वो विधायक जहां जिस इस एरिया का है, उसका पूरा काम करें, फिर उससे वो सर्टिफिकेट ले। यही सदन था अध्यक्ष महोदय मैंने जिस सदन में देखा है 1998 से लेकर सर हमने देखा है यदि वहाँ केबल डाली जाती थी यहाँ पर यदि पानी की पाइप लाइन डाल दी जाती थी, जब तक विधायक एनओसी लेटर नहीं देता था, उसकी पेमेंट नहीं होती थी। आज मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ एनओसी कंपलसरी यहाँ से किया जाए जिससे सदन के अंदर बैठे हुए मेंबरान इनको लगे कि वास्तव में अपनी सरकार आयी है, हमें सम्मान मिल रहा है, अपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री :आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मुझे आपने आज मुझे आपने नियम 280के तहत बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के पटल पर, अध्यक्ष जी हमारे मंत्री जी तो हैं नहीं...

माननीय अध्यक्ष: कोई नहीं।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री श्री आशीष सूद जी का ध्यान तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के अंदर एक तिमारपुर वार्ड है और उसमें एक बहुत बड़ा एरिया वजीराबाद और संगम विहार आता है और उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी सरकारी इमारत चाहे अस्पताल के रूप में हो, चाहे पुलिस स्टेशन के रूप में हो, चाहे समुदाय भवन के रूप में हो कोई सरकारी जमीन पर कोई भी सुविधा उस पूरे क्षेत्र में नहीं है। और उसकी जनसंख्या near about आज 50हजार से भी ऊपर हो चुकी है। वजीराबाद क्षेत्र में किसी स्वतंत्र एवं स्थाई पुलिस थाना भवन का अभाव है। क्योकि वहां पर कोई भी अगर परेशानी होती है तो उनको पूरा रिंग रोड क्रास करके तिमारपुर थाने के अंदर आना पडता है। क्योंकि वजीराबाद का संचालन थाने का जो हमारे यहां पर तिमारपुर पुलिस स्टेशन है उसके अंदर एक छोटे-छोटे पोर्टा केबिन के अंदर हमारा पूरा एक वजीराबाद का थाना चल रहा है। ना वहां कोई चौकी है और रात का अंधेरा हो जाता है और उसको क्रास करना बड़ा मुश्किल होता

है। तो सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी भी है पुलिस को भी देखते हैं तो इनसे मेरा आग्रह है कि वहां पर एक पुलिस थाने की व्यवस्था कराई जाये ताकि वहां के लोग को न्याय और सुरक्षा मिल सके। दूसरा मेरा मंत्री जी से ये भी आग्रह है वर्तमान समय में सरकारी विद्वालय सिर्फ मेरे यहां पर 8वीं क्लास तक है और वो स्कूल भी अभाव है बंद पडा है। क्योंकि वो दोबारा से टूट कर बन रहा है। तो मैं क्योंकि वो शिक्षा मंत्री जी भी हैं उनसे ये नम्र प्रार्थना करता हूं कि तिमारपुर एवं नेहरू विहार के अंदर हमारे बच्चे पढने जाते हैं इस लिए हमारी बालिकाएं छोटी बेटियां उनको जाने में बडी दिक्कत होती है तो एक हमारे यहां पर माध्यमिक स्कूल का बारहवीं स्कूल तक का निर्माण कराया जाये। तीसरा हमारे पूरे क्षेत्र में अध्यक्ष जी आज पता है कि सब लोग बडे-बडे बैकेंट हॉल में या बडे-बडे रिजोर्ट में जाकर शादी नहीं कर सकते। मेरे क्षेत्र में हर गरीब किस्म का भी आदमी है, मध्यम किस्म का आदमी भी है। उनके लिए दूर जाकर शादियां करना दूर जाकर मतलब कि मेरे यहां स्थिति ये है कि किसी के घर के सुख हो, दूख हो किसी को अपने यहां पर शोक सभा करनी हो उसके लिए भी कोई भवन, कोई जगह नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी वजीराबाद क्षेत्र में, संगम विहार क्षेत्र में एक जो है समुदाय भवन का निर्माण कराया जाये जिससे कि वहां की जनता को सभी सुविधाएं मिल सकें। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उक्त विषयों में किसी परियोजना पर कार्य का प्रस्ताव है यदि है तो कृपया उसकी वर्तमान स्थिति एवं सम्भावित समय सीमा से सदन को अवगत कराया जाए। साथ ही क्षेत्र में बढती आवश्यकताओं को देखते हुए इन बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः पहले एक मिनट आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हॉ बिल्कुल-बिल्कुल अब अगला नम्बर इन्ही का है। अभी मैं एक मिनट, चार नाम पढ रहा हूं। पूनम शर्मा जी, संजय गोयल जी, माननीय सदस्य प्रद्वयूम्न सिंह राजपूत जी, माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, माननीय सदस्य श्री अजय महावर जी। ये पांच लोगों को अब बुलवाया जायेगा।

.....व्यवधान.....

श्री आले मोहम्मद इकबालः अध्यक्ष जी हमें भी बुलवाा दीजिए, अकेला आदमी बैठा हूं।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः नहीं तो आपने पेपर तो सब्मिट नहीं करे 280के।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः चलो आपको बुलवा देंगे।

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी मैंने ये कहा था 280 पहले पूरा हो जाए उसके बाद..

माननीय अध्यक्ष हॉ आपको भी बुलवा देंगे। एक मिनट आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर है आपका कोई।

श्री तरविन्दर सिंह: मारवाह मामला बहुत गम्भीर है जी। क्योंकि कल से आपको मैने कहा आपने कहा बाद में। अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर आपने एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं धन्यवाद भी करता हूं कि जो एक ई-मेल आई थी आपने बताया ग-मेल के बारे में। हमें सुबह मैसेज भी आ गया था। उसको ग्यारह बजे शुरू किया विधान सभा को। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुझबूझ से ये किया और विपक्ष की बात जो अध्यक्ष महोदय कि आपने पिछली बार भी ...

माननीय अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ बार्डर बताईये ना।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: हॉ ये भी है। ये भी बहुत बड़ा प्वांईट ऑफ आर्डर है। विपक्ष आ नहीं रहा अध्यक्ष जी। विपक्ष आ नहीं रहा। ये भी चिंता जनक है। उनके लिए शर्म की बात है अध्यक्ष जी कि दिल्ली की समस्या कौन उठायेगा यहां पर उनकी। तो अध्यक्ष जी वो भी मैं कहना चाहता हूं तीसरी जो गम्भीर हमारे सब MLAs के लिए है। वो कोई छोटी-मोटी बात नहीं अध्यक्ष जी। अगर कल हादसा यहां हो जाता। ये भी हो सकता था जब किसी ने ई-मेल की है तो इसमें क्या है। लेकिन दूसरी बात ये है अध्यक्ष जी आपसे भी कई बार हम दरख्वास्त कर चुके हैं और मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी से भी हम दरख्वास्त कर चुके हैं विधायक दल की बैठक में। अब मजबूरी में विधान सभा में बोलना पड रहा है। हमारे भी बच्चे भी, हमारा भी परिवार है। अगर विधान सभा में बोलना पड रहा है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। आज देखो आप कहां पर एक दम चार पांच सौ लोग इकटठे हो जाते हैं। चलो एमएलए के घर। गाली देना शुरू कर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय क्या है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : प्वाइंट ये है। अध्यक्ष जी पहले बताऊंगा तभी प्वाईंट का मतलब निकलेगा।

माननीय अध्यक्ष : कोई मैं आपको बाद में बुलवाऊंगा।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह :नहीं देखो अध्यक्ष जी आपने...

माननीय अध्यक्ष : एक बारी ये 280 पूरा हो जाये मैं आपको बुलवाऊंगा।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह :अध्यक्ष जी, ये हमारी जान का खतरा है। पांच सौ लोग आ गए घर में रात को फिर क्या करेंगे हम। नहीं-नहीं क्या करेंगे, ये बताओ आप?

माननीय अध्यक्ष : अभी आप बैठिये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : प्रवेश वर्मा जी को भी हमने दरख्वास्त की है। इसके लिए हमारी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाये। ये ही कहना है।

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्रीमती पूनम शर्मा जी।

श्रीमती पूनम शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित सभी भाईयों को चैत्र नवरात्री की शुभकामनायें। आज इस सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान उन लौहार समाज की ओर दिलाना चाहती हूं जो सदियों से अपने हाथों का हुनर से समाज की सेवा करता है और भी सडकों के किनारे खुले आसमान तले बिना किसी स्थायी छत के असम्मान जनक जीवन जीने को मजबूर है। जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री साहिब वर्मा जी ने जब सत्ता में थे तब इस समुदाय के लिए उन्होंने दूरदर्शी योजना प्रस्तावित की थी कि इस योजना को परिकल्पना यह थी कि लौहार समुदाय सहकारियां समितियां बनाई जाये जिसमें नीचे दुकान और ऊपर उनके लिए रहने का घर उनको दिया जाए ताकि उनकी रोज़ी और रिहाइश दोनों एक ही छत के नीचे मिल सके। इस योजना के तहत मंगोलपुरी और रोहिणी सेक्टर-2 में मकान भी बनाए गए थे। लेकिन दुखद ये है की आज भी वे मकान ऐसे के ऐसे खाली पड़े हैं और जिनके लिए बने थे वो आज भी सड़कों के किनारे रह रहे हैं। बल्कि एक मानवीय संकट है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मंगोलपुरी और रोहिणी सेक्टर-2 की जो इकाइयों की स्थिति है, तत्काल उसका सर्वे कर-कर उन जो बेचारे जो लोहार परिवार हैं, उनके लिए उनकी पहली प्राथमिकता को देखते हुए उनको आधार पे वहाँ पे बसाया जाए और इस समुदाय के लिए एक नई व्यापक, आवास और एक आजीविका योजना बनाई जाए। जो समुदाय सदियों से समाज के लिए अपनी मेहनत से थामे रहा है, उसे सम्मान से जीने का हक मिलना चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बिना और देरी के इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। आप देखोगे की रात के समय मैं भी जब वहाँ से ट्रैफिक निकलता है तो वो रोड पे रहते हैं और रोड पे ही खाना बनाते हैं। उनके बच्चो के जब स्कूल में ऐडमिशन के लिए जाते हैं तो उनके पास कोई स्थाई, उनका कोई भी आवास, उनका कोई पहचान पत्र नहीं होता क्योंकि उनका कोई पता तो है नहीं, कोई उनका आवास नहीं है, कोई घर नहीं है तो मेरा आज इस सदन से आग्रह है और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमारे जीतने भी लोहार भाई हैं और वो जो रोड किनारे रह रहे हैं, उनको भी एक स्थायी आवास प्रदान किया जाए। जयहिंद जय भारत।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल, माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष जी आपका विशेष धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से परिवहन मंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में अवैध रूप से संचालित हो रहे ई रिक्शा और वाहनों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न गम्भीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह समस्या केवल यातायात अव्यवस्था तक सीमित नहीं रही बल्कि यह नागरिको की सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा और शहरी अनुशासन से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय बन चुकी है। मेरी विधानसभा में विशेष रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है और वर्तमान में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना वैध लाइसेंस के और परमिट के संचालित हो रहे हैं। अनेक ई-रिक्शाओं के परमिट समाप्त हो चूके हैं, फिर भी सड़क पर बेरोकटोक चल रहे हैं। ये वाहन मुख्य चौराहों, गली के नुक्कड़ों, मेट्रो स्टेशन के बाहर अव्यवस्थित ढ़ंग से खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी रोड पर और आम नागरिको को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह कई स्थानों पर ये ई-रिक्शा जाम का प्रमुख कारण बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई चालक यातायात नियमों की खुली अवहेलना करते हैं और wrong side में वाहन चलाते हैं, अचानक मोड़ लेते हैं, बीच में सड़क पे वाहन खड़ा, अपनी ई-रिक्शा खड़ी कर देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और कई मामलों में तो ये फुटपाथ पर भी ई-रिक्शा चलते हैं जिससे कि फुटपाथ पे चलने वाले हमारे पैदल चलने वाले जो हमारे नागरिक हैं, उनको गंभीर ऐक्सिडेंट भी होता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय मंत्री जी से की विशेष रूप से मेट्रो स्टेशन के 50 मीटर दूर और विशेष रूप से चौराहे से 50 मीटर दूर इन ई-रिक्शा को व्यवस्थित ढ़ंग से और वैध ई-रिक्शा को ही संचालित किया जाए और विद यूनिफॉर्म के साथ मैं उस पर ई-रिक्शा पर उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका लाइसेंस नंबर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हो, जिससे की यात्री भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। दूसरा, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात और कहूंगा कि पीडब्ल्यूडी रोड पर आजकल बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं और बड़े-बड़े शोरूम साथ में आपके नर्सिंग होमस या हमारे कार सेलर्स हैं, टू व्हीलर सेलर्स है और थ्री व्हीलर सेलर्स हैं, उनकी वजह से वो रोड पर जीतने वाहन चल रहे हैं, उनसे ज्यादा वाहन रोड पर खड़े होते हैं और उनकी संख्या नियंत्रित नहीं होती, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है और जाम भी, मैं आज यदि पहले मैं हम आईटीओ 30 मिनट में पहुंचते थे विवेक विहार से अब आज की डेट में 50 मिनट का समय लगने लगा है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें सबसे बाधक है हमारे जो पुराने ओल्ड व्हिकल्स हैं, इसलिए एक व्हिकल्स पर एक नई पॉलिसी बनाई जाए। जिस तरह से सिंगापुर के अंदर है कि आप वही गाड़ी ले सकते हैं जिनके पास में आपके जीतने सरकार के पास में जो रजिस्ट्रेशन कैंसल होंगे वेहिकल्स के, क्योंकि ये यदि नहीं बनाया तो ये गंभीर समस्या पैदा होती है। पोल्युशन भी एक बड़ा

विशेष कारण है इसका और उन्हीं को वेहिकल खरीदने की इजाजत दी जाए जिनके आपके पास में परमिट कैंसिल होते हैं और वो भी वो जो की ई-व्हिकल्स हों ना की कोई डीजल या पेट्रोल से संचालित व्हिकल्स हो क्योंकि यदि आज हमने सोचेंगे इसपर आज कार्य करेंगे तो अगले 5 साल के अंदर हम दिल्ली को एक सुव्यवस्थित दिल्ली की मॉडल दे पाएंगे और विशेष रूप से मेरा ये कहना है और जो जिम है। जिसतरह से मैंने बताया जिम है, रेस्टोरेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी रोड पे जिनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं या कार सेलर्स से टू वीलर्स है, आज संख्या चलने वाले वाहनों से ज्यादा संख्या रोड पे खड़ी है जिसकी वजह से जाम रहता है और लोग नागरिक लोग बड़े वहाँ परेशान रहते हैं। समय-समय पर डेली हमारे पास आते हैं। टीआई से जब हम कहते हैं टीआई कहता है जी मैं क्या कर सकता हूँ मैंने तो एक बार हटा दिया। फिर हमने अन्य उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर है इस पॉलिसी आप इसपे बनवाई जाए, जिससे कि इस वाहनों की संख्या आप देखिये मैं आज गुजरात सरकार का विशेष धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यूसीसी लेकर आया यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए और दिल्ली में भी इस तरह की व्यवस्था के साथ में वाहनों की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ये व्यवस्थित तरीके से दिल्ली को दे पाएंगे। धन्यवाद जय हिंद, जय भारत।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य है श्री प्रद्यूमन सिंह राजपूत।

श्री प्रद्यूमन सिंह राजपूत, माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद आपका। आज मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और सड़कों पर लगातार होने वाले अतिक्रमण और जाम की जो समस्या है उससे आज दिल्ली जूझ रही है। अध्यक्षजी दिल्ली देश की राजधानी है, लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतरती है, बड़ी सड़कें हैं, सब छोटी पड़ती जा रही है और जगह-जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई है। अभी अध्यक्ष जी हमारे साथियों कुलवंत राणा जी ने भी और संजय गोयल जी ने भी और हमारे डिप्टी स्पीकर ने भी मिलती जुलती यही बातें कही हैं। अधिकारी अपने काम सही नहीं करते, लापरवाही करते है, कोई जिम्मेवारी नहीं समझते, कहीं गड्ढा खोद दिया, कहीं पोल गलत लगा दिया, कहीं मलबा डाल दिया और एक एमएलए का काम इस तरह का हो गया जैसे वो सुपरवाइजर बनके रह गया हो। ऐसी अतिक्रमण के बारे में अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों के अंदर ये समस्या और बढ़ गई है। पिछले जो सालों में सरकार रही है वो बिना विजन की सरकार रही और दिल्ली की सड़कों पर गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण रहा और उससे लोग परेशान भी बहुत हैं। जगह जगह रेहड़ी पटरी, पटरी, खोमचा और ई-रिक्शा लगा लेते हैं और उनको किसी का भी डर नहीं है। प्रशासन का डर नहीं है और किसी भी एजेंसी का उनको डर नहीं है।

अध्यक्षजी दिल्ली के अंदर हालत बद से बदतर हुए हैं और जाम और एनक्रोचमेन्ट के कारण गाड़ियों द्वारा हो रहे प्रदूषण का जहर लोगों की जिंदगी को लील रहा है और दूसरी तरफ मिलावट का जो कहर है वो भी जहर बनकर लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। अध्यक्ष जी सड़कों पर रेंगने जैसी पोजिशन होती है और हम आने वाले समय में हम कौन सी दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को कैसे दिल्ली का निर्माण करके हम देंगे। अध्यक्ष जी इसके लिए एक सख्त मैकेनिजम बनाया जाए। आज हम एन्क्रोचमेंट हटवाते हैं, एमसीडी वाले हटाके चले जाते हैं। उसके बाद फिर दुबारा से वो बैठ जाते हैं। बार-बार हटवाते हैं, बार-बार बैठते है, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है और किसी भी एजेंसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। एमसीडी अगर हटाती है तो उसके बाद वीडियो बनवाई जाए और पुलिस का जो एसएचओ है उसकी जवाबदेही तय की जाए ताकि ये बार-बार का बैठना हटना और ये हटाना ये खत्म हो और जो नो वेंडर ज़ोन में सड़कें आती है वहाँ भी जाम लगता है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यही कहना है कि कोई टास्क फोर्स बनाई जाए, कोई नोडल अधिकारी तय किया जाए जिसकी जिम्मेवारी हो और एक बार हटाने के बाद वहाँ कोई दुबारा बैठने की हिमाकत ना कर सके और जो अधिकारियों की मिलीभगत होती है उन अधिकारियों को भी डर हो ताकि हमारी दिल्ली साफ सुथरी रहे। लोगों को चलने का, आने का जाने में दिक्कत ना हो, परेशानी न हो और जाम न लगे। आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो ये मुद्दा पहले भी आ चुका है लेकिन मेरी विधानसभा विश्वास नगर में कुछ दिनों पहले 2005 में ट्रांस यमुना के लिए एक सपना देखा था और दिल्ली में इंडिया हैबिटाट सेंटर की तर्ज पर ट्रांस यमुना जो कि दिल्ली की वन थर्ड आबादी वहां निवास करती है उनके लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र पीएसके की स्थापना की गई थी और उसका उद्देश्य ये था कि वहां आर्ट गैलरी, योगा, अनेकों अनेक सब्जेक्टों पर सेमिनार, डांस, डिबेट, देश के बड़े- बड़े स्कॉलर्स के वर्कशॉप, साइंटिस्ट, क्रिएटिव आर्ट के वर्कशॉप, फुड फेस्टिवल, Rooftop restaurant और लोकल टेलेंट को प्रमोट करने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। 15हजार के करीब लोगों से, 15 हजार रूपये महीना करीब 3 हजार लोगों से आजीवन सदस्यता शुल्क भी लिया गया, लेकिन जो हमारी हमसे पूर्व सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, जिसने भ्रष्टाचार के नए-नए आयाम पूरी दिल्ली में स्थापित किए और बिना किसी शर्म के उन सबको अपने पर्सनल फायदे के लिए अपने लोगों को लगाकर जो शादी और अन्य समारोह, लाइब्रेरी आदि की सुविधा ट्रांस यमुना क्षेत्र के और पूर्वा सांस्कृतिक

केंद्र के जो सदस्य थे उनको दी जा रही थी और उक्त गतिविधियों को प्रदान करने का संकल्प लेकर बनाया था लेकिन आम पार्टी की भ्रष्ट नीति, भाई-भतीजावाद की भेंट चढ़ गया। पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र बिना किसी एसओपी के पीएसके के उद्देश्य के विपरीत इसमें 2-2, 3-3 बारातघर, शराबघर बन गए हैं और ये आम पार्टी की सरकार ने जो लोग आज इसका संचालन कर रहे हैं उस समय की दी हुई, न तो उनको जो अलॉटमेंट की है उसके अंदर पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है, नियमों को तोड़ा गया है और रेवेन्यू जो आता है उसमें जो शेयर होना चाहिए दिल्ली सरकार का क्योंकि वो लोग वहां जो गतिविधि हो रही हैं उनमें पैसा नकद पैसा ले रहे हैं और नकद पैसा लेने की वजह से उसका कोई रिकॉर्ड दिल्ली सरकार को मिल नहीं रहा। दिल्ली सरकार के भ्रष्ट लोग भी उन भ्रष्ट लोगों के साथ मिले हुए हैं और जो नकद पैसे में जो दिल्ली सरकार का जो भी अपना हिस्सा है उसको भी वो भ्रष्टाचारी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि डिपार्टमेंट को एक समयसीमा में इसकी जांच की जाए, पीएसके का कब्जा दिल्ली सरकार तुरंत प्रभाव से ले और उसे सुचारू रूप से जो उपरोक्त उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति का निर्वहन सरकार करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष) : माननीय सदस्य -श्री अजय महावर जी, उसके बाद माननीय सदस्य -सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं और आले मोहम्मद जी भी, दोनों को टाइम देंगे।

श्री अजय महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से मैं ये बात माननीय जल मंत्री जी से रखना चाहता हूँ कि जो सीवर की गाद निकाली जाती है वो गाद, पहले भी ये बात उठाई थी हमने एक बार वो गाद निकालने के बाद वो सड़क पर पड़ी रहती है, पड़ी रहने के बाद फिर कुछ दिन तक अधिकारी कहते हैं कि ये सूखे का तब उठाया जाएगा। तो 3 दिन, 5 दिन तक रहती है लेकिन उसके बाद भी अधिकारी उसको उठाते नहीं है और वो धीरे-धीरे सड़क को, में फैलता रहता है, कुछ वापस चला जाता है और इससे भारी मात्रा में प्रदूषण भी होता है और लोगो में बहुत नाराजगी होती है। अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जल बोर्ड के अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास इसके निस्तारण की जगह नहीं है। और हम एमसीडी से आग्रह करते हैं वो अपने ढलावघर पे डालने नहीं देते, तो आखिरकार हम उसको कहां डालें? तो कई बार हमें भी एमसीडी से बात करनी पड़ती है, एकाध गाडी होती है वो भी डलवा लेते हैं। लेकिन लगातार ये इसकी कोई प्रक्रिया नहीं बनी, इसके लिए कोई साधन या टेंडर के लिए प्रक्रिया नहीं बनी है। तो उठाने के लिए गाड़ी और डालने के लिए जगह दोनों को ही दिक्कत है क्योंकि एमसीडी उसमें डालने के लिए मना करती है अपने ढलावघर में। तो मैं आपके माध्यम से जल मंत्री जी

से आग्रह करता हूँ कि इसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें सीवर की गाद निकाल करके उसके निस्तारण की पूरी व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन और रखने की और उसको समाप्त करने के लिए भी हो।

दूसरा आपके माध्यम से अधिक जी पिंकसिटी मेट्रो लाइन हमारे यहाँ आई, उसमें यमुना विहार, खजुरी, भजनपुरा और नानकसर चार स्टेशन मेरी विधानसभा में भी आए, मैं इसके लिए यूडी मंत्रालय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत- बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और एक सुझाव भी देना चाहता हूँ। अभी उसमें बहुत कम लोग आवागमन कर रहे हैं क्योंकि वो सीधे बुराड़ी की ओर जाती है। तो यदि सूर घाट स्टेशन को दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जोड़ दिया जाए या बस अड्डे की तरफ जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। हमारे क्षेत्र की जनता की यह मांग है कि इस मेट्रो लाइन में सूर घाट के बाद एक या दो स्टेशन बनेंगे, सीधा दिल्ली विश्वविद्यालय से इसको जोड़ा जा सकता है तिमारपुर होते हुए, अगर ट्रांसपोर्ट मंत्री इस पर ध्यान देंगे, यूडी मंत्रालय इस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र पर ये बड़ा उपकार होगा और हमारे क्षेत्र की जनता सदैव इसके लिए आभारी रहेंगी। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया मैं आपका हृदय से बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष) :माननीय सदस्य- श्री सतीश उपाध्याय जी।

निंदा प्रस्ताव(नियम-114)

श्री सतीश उपाध्याय: धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कल हमारी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार दिल्ली की प्रगति का बजट प्रस्तुत किया था। और कल उस पर हमारे सदन के दो सदस्य साथ में बैठे थे, विपक्ष की पार्टी के मुखिया ने जिस प्रकार के अमर्यादित बयान दिए उन बयानों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सवाल यह है कि केवल ये मुद्दा बयान का नहीं है, ये मुद्दा है महिला सशक्तिकरण के प्रति सोच का, नकारात्मक मानसिकता का और किस तरीके से महिलाओं का सम्मान ये पार्टी नहीं करती है उसके, उसका ये मुद्दा है। चाहे वो स्वाति मालीवाल का मामला हो, उनको मुख्यमंत्री निवास में ला करके पीटा गया, महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ़ अभद्र टिप्पणियां की गई, पोस्टर निकाले गए और कल जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों को लेकरके हमारे शिक्षा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने जिस तरह का एक लाख तीस हजार बच्चियों के लिए साइकिल देने का, एक उनकी उड़ान में पंख लगाने का काम किया और इस पार्टी ने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की, उस टिप्पणी में कहा गया कि ये बच्चियां अब जा करके दिल्ली की जो युवा शक्ति है, ये बच्चियां जा करके उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रचार करेंगी, ये साइकल के माध्यम से चुनाव का प्रचार करेंगी। मैं

उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आपकी मानसिकता, आपकी सोच कितनी नकारात्मक है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिको का भी सम्मान नहीं कर रहें, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और आप साथ में दिल्ली की जो युवतियां हैं, दिल्ली के जो युवा हैं और साथ में उन्होंने लैपटॉप का नाम भी लिया। जो लैपटॉप आप दसवीं की छात्राओं को दे रहे हैं उनके जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। जिस तरह की मानसिकता आप दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि ये इस पार्टी की जो नकारात्मक सोच है। जिस तरीके से हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ वो लेकर के जाते है, संज्ञान में इस विषय को मैं आपके लाना चाहता था। और जब दिल्ली सरकार एक तरफ बेटियों को बढ़ाने का काम कर रही है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके नए पंख लगा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता के साथ हमारी इस सदन के दो सदस्य उस प्रेस कॉन्फ्रेन्स में बैठे हुए थे, जिस तरह का मजाक उड़ा रहे थे, उस तरह का मजाक उन्होंने सभापति जी आपके संदर्भ में भी उड़ाया क्योंकि एक टिप्पणी आयी थी कि यहाँ पर बम की धमकी दी गयी है, आप अगर उस बयान को देखें तो उस बयान में दिखाई दे रहा है कि वो मजाक कर रहे हैं कि अच्छा, अध्यक्ष को उड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जो सदस्य इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ़ भी आपको सोचना चाहिए। बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक : अध्यक्ष जी,

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष) :जी।

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक : इसी पर मैं भी जोड़ना चाहता हूं। जिस प्रकार से कल दिल्ली की बेटियों को एक सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, उसी प्रकार से हमारे विपक्ष के साथियों ने दिल्ली की बेटियों को प्रचार का तंत्र बनाया है कि वो यूपी में जाकर प्रचार करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं इस वक्त दो बातें और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे ही इस पार्टी के मुखिया ने एक बार कहा था कि 500 रुपये का टिकट कटाकर बिहार के लोग आते हैं और इलाज करके चले जाते हैं। चुनाव के वक्त भी इन्होंने कहा था कि बिहार से लोग आते हैं, यहाँ वोट बनाते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं। अध्यक्ष जी, इस पर कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर बिहार और यूपी के लोगों को तिरस्कार करेंगे तो ये ठीक नहीं है। दिल्ली में एक बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं और दिल्ली के लोगों के स्वाभिमान से इस प्रकार से खेलना कहीं ना कहीं हम सबको दुख देता है इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अभी जो मुद्दा माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय जी ने उठाया वो बहुत गम्भीर मुद्दा है। जो बच्चियां, युवतियां जिनको सरकार ने बजट के प्रावधानों में साईकिल देने की बात की है वो एक तरह से उन बच्चियों को, उन छात्राओं को एक तरह

का लॉन्चिंग पैड है वो। उनके जीवन में एक आत्म-विश्वास भरने का। लेकिन जिस तरह का वक्तव्य दिया गया कि यूपी में जाकर के चुनाव प्रचार करें वो किसी पार्टी विशेष की छात्राएं नहीं हैं वो दिल्ली की नागरिक हैं और दिल्ली के परिवारों की बच्चियां हैं वो और वो किसी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं हैं वो कार्यक्रम जो जोड़ा गया है। और इसी बात को आगे जो है वो अभय जी ने भी बढ़ाया है। तो मुझे लगता है यह एक गंभीर मामला है और इस तरह की टिप्पणियां युवतियों के लिए, बच्चियों के लिए विपक्ष के जो पार्टी के जो नेता हैं और वो बार-बार इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। ये सदन का जो सेन्स है जो मैं समझ पाया हूँ उस सेन्स के अनुसार ये सदन इस तरह के वक्तव्य की, दिल्ली की युवा शक्ति का एक माखौल बनाना, उसको मजाक के रूप में लेना, उस पर, आप भी कुछ कहना चाहते है क्या, इस पर, एक मिनट।

श्री सतीश उपाध्याय: इसमें अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन किया है इसमें वो यहीं नहीं रुके थे, उन्होंने कहा साइकिल तो देंगे, लैपटॉप का मजाक उड़ाया। साथ में उन्होंने कहा कि उनके हाथ में झाड़ू और पकड़ा दीजियेगा। यानी दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की युवतियों को, महिलाओं को इस तरीके से तिरस्कार करना, उनका असम्मान करना, उनके हाथ में झाड़ू पकड़ाना। एक तरफ तो हम लैपटॉप पकड़ा रहे हैं, एक तरफ हम साइकिल दे रहे हैं, उनके जीवन के पंखों में उड़ान भर रहे हैं और वो कह रहे है कि इनके हाथ में झाड़ू पकड़ाईये। इस तरह का असम्मान दिल्ली की बच्चियों के साथ सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

श्री विजेन्द्रगुप्ता,माननीयअध्यक्ष: इसमें माननीय मंत्री।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री: अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दुखदायी विषय है। बच्चियों के प्रति इस तरह की भावना रखनी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल की जो घटना सामने आई, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जैसे अभी बहुत अच्छा उपाध्याय जी ने कहा, एक तरफ हमारी सरकार रेखा गुप्ता जी उन बच्चियों को उड़ान भरने के लिए उनके हाथों में शिक्षा देने के लिए लैपटॉप दे रही हैं, उनको स्कूल जाने के लिए साईकिल दे रही हैं और दूसरी तरफ ये कहा जाए की हम इन बच्चियों को प्रति इतनी गन्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाये हम इनको यूपी लेके जाएंगे। ये तो हम जाकर अखिलेश जी के प्रचार के लिए इनको लेके जाएंगे। इससे बड़ी घटिया मानसिकता क्या हो सकती है। आप बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री का भी रोज तिरस्कार करते हैं एक औरत का लेकिन आप आज बच्चियों का भी तिरस्कार कर रहे हैं और उन बच्चियों के प्रति जो की 18 साल की बालिका भी नहीं है आप उनके प्रति इस तरह की गंदी भावना रखते हैं, उनकी साइकिलों के साथ उनको यूपी ले जाएंगे। मैं मानता हूँ कि इस हाउस को इसकी कड़े रूप में जहाँ निंदा करनी चाहिए, इसमें रेजोल्यूशन पास करके इसका एक

कड़ी निंदा का रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं इसके संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी की करप्शन की लोभ-लालच की सीमा इतनी बढ़ गई। दिल्ली तो उन्होंने 11 सालों में बर्बाद किया पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक बार ये वाला विषय फिर उसके बाद आपका।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री: ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम सभी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं ये जो विषय पहले ये पूरा कर लेते हैं बच्चियों वाला उस पर बोलना है क्या।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: मैं उसी पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अभी उसको कंन्कलूड कर लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: उसी पर आ गया..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हां उसी पर आइये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: यह बहुत निंदनीय कार्य है कि विपक्ष जो एक ईश्वरीय कार्य है हमारे EWS और उसके अलावा सब बालिकाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा है और पूरा देश और पूरा सनातन आज कन्या पूजन कर रहा है ऐसे इस माहौल में विपक्ष की जो मति भ्रष्ट हो गई है वो अपनी अंदर की हीन भावना और जो भ्रष्टाचारी सोच है उसको आज उजागर कर रहे हैं इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय तरविंदर सिंह जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आपने इस पर बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। सतीश उपाध्याय जी ने बहुत ही अच्छा और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी ने जो इन्होंने नहीं किया वो मुख्यमंत्री जी कर रही है और नौवीं क्लास की बच्चियों को साइकिल का जो 1,20,000 के करीब है और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है अभी उनकी उम्र भी 14-15 साल के करीब हुई होगी। तो उनकी बच्चियों के लिए यह बात कहना कि उनको प्रचार के लिए, अखिलेश यादव के प्रचार के लिए उनके हाथ में लैपटॉप दे देना और उनको प्रचार कराना कितनी निंदा की बात है अध्यक्ष जी। मेरे को तो लगता है कि अबकी विपक्ष की लीडर आये

ना उसको किसी हॉस्पिटल आपने पहले हमारा भी चेक अप करा दिया, अब उसका भी मेहरबानी करके चेक अप कराना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः ठीक रहा न वो कार्यक्रम।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः नहीं-नहीं कभी गुरुओं के बारे में क्या-क्या शब्द कहे उसने उस दिन गुरुतेग बहादुर महाराज जी के लिए। कल का देखो कितना बड़ा बयान है। हम तो मुख्यमंत्री जी एक तरफ ऐसे बजट लेकर आए जिससे कि सबका उपचार हो, सबको आगे बढ़ना। नई बच्चियों को मौका दे रहे हैं। साइकिल लेकर उन्होंने ये बड़ा अच्छा कहा था कल वक्तव्य की बच्चियां पैदल जाती है, उनको साइकिल दी गई है। लैपटॉप 10 क्लास के लड़कों को लड़कियों को लैपटॉप दे रहे हैं उसके बारे में कहें । आप और सुझाव दो, आप कोई और बात कहो कि ये कम दिया है आप इसको बढ़ाओ फिर तो मानेंगे। आप सुझाव दो, आपका क्या चल रहा है पिछली बार भी विपक्ष की लीडर हाउस में नहीं आयी, इस बार भी नहीं आयी। अध्यक्ष जी क्या चल रहा है। इसका मतलब उसको दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री तरविंदर सिंह मारवाहः और अध्यक्ष जी मैं ये भी कहता हूँ कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त-से-सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिरसा जी ने अभी जो कहा है सख्त-से-सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः यह सदन इस तरह के वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है और सदन यह अपेक्षा करता है कि वो अपने शब्द वापस लें। इसमें न सिर्फ दिल्ली की युवतियों के जो की टीनेजर बच्चियां हैं और उनके बारे में इस तरह की भावना व्यक्त करना, अपशब्द बोलना और इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के निवासियों का भी इसमें एक प्रकार से तिरस्कार किया गया है कि यूपी ले जाओ। यह जो भाषा है यह पूरी तरह से इसका इस भाषा का ये सदन निंदा करता है। इस निंदा प्रस्ताव से जो सहमत हैं, जो सतीश उपाध्याय जी द्वारा यहां मुद्दा उठाया गया तो सदन इसपर अपनी सहमति दे। मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव रख रहा हूँ

जो उसके पक्ष में हैं वो हां कहें।

जो इसके विपक्ष में वो ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

और सतीश उपाध्याय जी का यह प्रस्ताव सदन में पारित हुआ।

अब मैं माननीय सदस्य आले मोहम्मद जी को एक मिनट दे रहा हूँ और उसके बाद हमारे मंत्री श्री सिरसा जी अपनी बात कहेंगे।

ध्यानाकर्षण

श्री आले मोहम्मद इकबाल: बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर आपका। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ जिससे पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश आज बहुत गंभीर सोच में गया हुआ है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: भई अफवाह मत फैलाओ इधर।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: और नहीं, नहीं, सर नहीं, नहीं, मैं अफवाह नहीं फैला रहा, बस मैं 2 मिनट की परसों भी देश के सबसे बड़े सदन में प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा में इस देश की जनता को अवगत कराया है की एक नई आपदा, एक नई पैन्डेमिक जैसी शक्ल ना बने। बस मेरा ये कहना है कि अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी दिल्ली के अंदर जितनी गैस एजेंसीज़ हैं जो आज सिलेंडर की महामारी को एक ब्लैकमेल करके और एक बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर पेट्रोल को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी दहशत बनी हुई है और उस दहशत को लेकर मेरी आप के माध्यम से और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि What plan of action we have? हमारे पास plan of action क्या है कि कल को खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति एनर्जी वाली पैन्डेमिक आती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की तरफ पूरी दुनिया देखती है एक कैपिटल की तरफ मेरी, मेरी अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है।

माननीय अध्यक्ष: आप, आप कहना सही है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: सुन तो लीजिये, सुन तो लीजिये, मैं अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: जो मैं महसूस कर रहा हूँ। वैस आप जो कहना है आप कहिये।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: अब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है मेरा।

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर आपको बुलाता हूं।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: मेरा माननीय मंत्री जी मेरा बस ये।

माननीय अध्यक्ष: हाँ हाँ मैं एक बार इनकी बात पूरी हो जाये, फिर आप।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: मैं मंत्री जी से, सरकार से, देखिये, हम 70 लोग पूरी दिल्ली को यहाँ सदन से चला रहे हैं और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को रख दे कि हम लोगों में एक दहशत है।

माननीय अध्यक्ष: वो रिप्लाई कर रहे हैं।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: क्योंकि हाँ मैं चाहूंगा क्योंकि देखिये अध्यक्ष जी। आज हमने कल न्यूज़ में पढ़ा कि एक चोर आया घर में गया, उसने ज्वेलरी चोरी नहीं करी वो सिलेंडर चोरी करके गया।

माननीय अध्यक्ष: कोई नहीं ...

श्री आले मोहम्मद इकबाल: ये बात एक दहशत बनी हुई है। दहशत का माहौल है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, अब इस पर रिप्लाई सरकार की तरफ से आप करेंगे। एक मिनट आप बैठ जाईये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष जी ये मेरा मंत्रालय से संबंधित है।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: आपका मंत्रालय से बस ठीक है।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: हो गया हो गया आप हो गई बात अब ये बात।

श्री आले मोहम्मद इकबाल: अध्यक्ष जी गोल्ड का व्यापारी पहले कल तक परेशान था आज गैस सिलेंडर लेने वाला जो मजदूर है वो गैस एजेंसी, गैस, गैस एजेंसीज की जो कालाबाजारी है, जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लोगों के घरों तक आज मैं ऑनलाइन मैं कोई गैस बुक करूं तो वो हमारे घरों तक नहीं पहुँच रही है।

माननीय अध्यक्ष: अभी पूरी स्थिति को मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): मैं आपको अध्यक्ष जी मैं एक सदस्य, अपने भाई को इस पर।

माननीय अध्यक्ष: कोई नहीं आपकी बात आ गई अब।

....व्यवधान.....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): इस पर आपको।

माननीय अध्यक्षः सिर्फ आपकी ही बात पर रिप्लाई करवा रहे हैं बाकी तो सब सदस्यों ने अपनी बात कही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): मैं आपको इस पे पूरे जानकारी देना चाहता हूँ और सारे सदन को देना चाहता हूँ अननेसेसरीली किसी भी तरीके का पैनिक ना क्रिएट किया जाए। दिल्ली के अंदर जो हमारा डेटा है उसके अंदर अध्यक्ष जी कोई पैनिक भी नहीं है जो हमारे सिलिंडर की सेल थी। उस सेल के अंदर कोई अननेसेसरी किसी की पैनिक भी नहीं आया अभी तक, इस घटनाक्रम को चलते हुए 22-25 दिन हो गए दिल्ली के अंदर, कोई भी हमारे डेटा के अंदर ऐसी पैनिक नहीं दिखाई दिया, कोई ओवर बुकिंग नहीं दिखाई दी किसी ने ओवर बुकिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया, बिल्कुल स्मूथ रूटीन में चल रहा है डोमेस्टिक सिलेंडर जहाँ तक है। जो कमर्शियल सिलेंडर है वो केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत सबको प्रायोरिटी पर मिल रहा है हॉस्पिटल्स हों सबको। ऐसा कहीं पर भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी में कोई विषय है तो आप मेरे को जरूर बताएं। अभी हमारा रामनवमीं का त्यौहार भी चल रहा है।

माननीय अध्यक्षः कोई स्पेसेफिक आपको लगता है तो आप जरूर बतायें सदन को मंत्री जी उस पर जरूर हल निकालेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): रामनवमीं का त्यौहार है जगह-जगह इस त्यौहार के लिए सिलिंडरों की जरूरत है और मैं सारे सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कहीं भी इस त्यौहार में भी एक भी दिन एक भी घंटे के लिए किसी की कोई कमी नहीं आयी हम इस बात की चिंता कर रहे हैं और आपके ध्यान में आये तो बताना।

माननीय अध्यक्षः चलिये, अब आपका जो दूसरा विषय है ये तो हो गया हो गया आपका।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): दूसरा विषय बड़ा जरूरी है आप सुन लीजिये।

माननीय अध्यक्षः अब।

श्री मोहन सिंह बिष्टः हो गया मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): चलिये कोई नहीं, बैठिये-बैठिये। धन्यवाद।

-----व्यवधान-----

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): कोई नहीं आप मेरे को बता दें।

माननीय अध्यक्षः आप ऐसा करिए कुछ आप के पास उदाहरण हो, आप जरूर दीजिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): कोई मुझे देना मैं करके दूंगा।

-----व्यवधान-----

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्धोग मंत्री): मैं दूंगा आपको अगर कोई कमी रह रही हो तो मुझे बताना। हां हमें बताना करेंगे हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: अब आप बताईये जी आगे।

निंदा प्रस्ताव(नियम-114)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्धोग मंत्री): अध्यक्ष जी दूसरा विषय में बड़ा संगीन विषय है मैं सारे सदन के जानकारी में भी लाना चाहता हूँ और आप के माध्यम से दिल्ली और देश के लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की सत्ता की लालसा लोभ और पैसा इकट्ठा करने की इस हद तक लालच हो चुका है की इसकी भेंट अब, लोग पहले तो लूटे जाते थे, पैसे लूटे जाते थे, करप्शन की जाती थी, अब लोगों की जान भी जाने लगी है। मैं ये विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ। पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा का। गगनदीप सिंह रंधावा एक जनरल मैनेजर हैं और वहाँ के एक मंत्री चाहते थे कि टेंडर उनके परिवार को मिले, उन्होंने गगनदीप सिंह रंधावा के ऊपर जबरन मारपीट करना और उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। कैसे शुरुआत होती है, ये एक टेक्निकल टेंडर था जिसके अंदर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को काम देना था लेकिन वहाँ के मंत्री जो हैं उन्होंने दबाव बनाया और कहा कि यह टेंडर मेरे पिता जी के नाम से दिया जाए। उन्होंने 13 मार्च को जब गगनदीप रंधावा का बस नहीं चला तो गगनदीप रंधावा ने 13 मार्च, 2026 को इस दुर्व्यवहार और धमकियों की जानकारी अपने ऊपर दी। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो 14 मार्च को फिर से उन्होंने MD वेयर हाउसिंग गौतम जैन को इसकी जानकारी भेजी कि किस तरह से मंत्री मेरे पर दबाव बना रहा है और मेरे को मारपीट करने की धमकियां दे रहा है। इस पर भी नहीं हुई तो उन्होंने 14 तारीख को फिर से एक चिट्ठी वहाँ की इम्प्लॉई यूनियन विनीत शर्मा को भेजकर कहा की मेरे को बचाया जाए। इसके बावजूद भी नहीं कोई बचाव हुआ तो 16 मार्च, 2026 को उन्होंने चौथा पत्र डी.सी.तरनतारन को भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जीवन और उनके परिवार के जीवन को खतरा है और उनको बचाने की कृपा की जाए। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते गगनदीप सिंह रंधावा ने सल्फास खाकर सुसाइड कर ली। क्यों करी, लालजीत सिंह जो मंत्री हैं वहाँ के, ने उसको अपने घर पर बंधक बनाया, उसको बंधक बनाकर उसके कनपटी पर बंदूक लगाई गई और उसको कहा गया एक वीडियो बनाओ जिसमें कहो कि मैंने 10 लाख रिश्वत मांगी है। बताइये इससे पहले कभी होता है कि मांगने वाला कह रहा हो, उसके कनपटी पे पिस्तोल लगाकर बंदूक लगाकर उससे वीडियो बनवाई गई और फिर उस को कहा गया कि अगर तुम मेरे पिता जी के नाम से ये नहीं देगा

ये एफसीआई का काम तो तो मैं ये विडियो.... करूँगा। लालजी सिंह भुल्लर वहाँ का मंत्री, उस डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने सल्फर खाकर सुसाइड कर ली । अब बताइए कि एक आदमी सूसाइट करने को मजबूर किया, विषय क्या है करप्शन का और भगवंत मान की सरकार अरविंद केजरीवाल जिसके सुपर सीएम है उन्होंने ना मंत्री पर कार्रवाई की, ना मुकदमा दर्ज किया, ना परिवार पर की, ना पीए पे किया। उसके बाद जब ऑपोजिशन ने बहुत सारा वहाँ पर शोर मचाना शुरू किया तो लालजीत भुल्लर का रिजाइन लेकर उसको छोड़ दिया गया, कहा गया की देखिये जी हमने मंत्री से रिजाइन ले लिया और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। उनकी लालजीत भुल्लर जी की धर्मपत्नी श्रीमती उपेंदर कौर जब उन्होंने ये कहा कि हम मृतक शरीर का पोस्टमॉर्टम नहीं होने देंगे, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो फिर जाकर एफआईआर लॉज की गई और एफआईआर फिर से लालजी सिंह भुल्लर पे नहीं की गई, उनके पिताजी पे पर और उनके पीए पर दर्ज नहीं की गई, unknown लोगों पर दर्ज की गई। इसके बाद यह मसला लोकसभा में उठा और लोकसभा में उठने के तब तक 48 घंटे मतलब 2 दिन निकल चुके थे। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के एमपीओं ने मुददे को उठा के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आग्रह किया कि आप इसके ऊपर सीबीआई की जांच कीजिये। On the Floor Of House माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस के एमपी मुझे लिख कर देते हैं तो मैं तुरंत इसकी सीबीआई की इन्क्वाइरी जांच कराऊंगा। जैसे ही ये खबर लोकसभा की टीवीओं पर चलनी शुरू हुई तुरंत लालजी सिंह भुल्लर को लगभग 48 घंटे बाद गोविंदगढ़ से गिरफ्तार किया गया और अभी भी उसके पिता को और उसके उस पीए पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बताता है कि किस हद तक अरविन्द केजरीवाल जी ने पंजाब के सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया, वहाँ की अफसरशाही और ये एक विषय नहीं है मैं इसके आगे भी बताना चाहता हूँ। इसी तरह पूरा प्रशासन को वहाँ पर भ्रष्ट कर रखा है। वहाँ के एक विधायक अमृत पाल सिंह सुखाना जिसने एसडीएम बबनदीप सिंह वालिया पर भी इसी तरह से दबाव बनाया और कहा कि पंचायत समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया जाए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कैसे जीतते हैं, ये चुनाव नहीं कभी जीत पाते। ये केवल और केवल फ्रॉड से जीतने की कोशिशें करते हैं। पंचायती चुनाव इन्होंने फ्रॉड से वहाँ पर जीतने की कोशिशें कीं। अब कहा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उसको नियुक्त किया जाए, जब एसडीएम ने इससे इनकार किया तो एसडीएम को कहा क्या बोला आप सुनिए ध्यान से। तो कहा कि मैं तेरे को गैंगस्टरों से मरवा डालूंगा। एक एमएलए कह रहा है एक एसडीएम को, ये लालू प्रसाद यादव के सुनते थे तब बिहार में जो अब पंजाब में सुनने को मिल रहा है कि मैं तेरे को गैंगस्टरों से मरवा दूंगा, ये मैं नहीं कह रहा ये बकायदा एसडीएम ने डेप्युटी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे को मरवाने की धमकी दे रहे हैं कि गैंगस्टर से मरवा देंगे। धमकी कौन दे रहा है, एमएलए, ये अरविंद केजरीवाल की वहाँ देन हैं। इसके बाद जब

सारी ओपोजीशन पार्टियों ने इस पर दरवाजा पहुंचाया और ये मसला उच्च न्यायालय गया अध्यक्ष जी अब सोचिए एमएलए धमकियां दे रहा है गैंगस्टर्स से मरवाने की, किसको? एसडीएम को, वही सुरक्षित नहीं है पंजाब के अंदर और फिर उच्च न्यायालय ने कहा और इसके ऊपर दोबारा से चुनाव किया जाएगा और 28 तारीख को फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए। हाईकोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने हाल कर रखा है और आगे देखिये। इसी तरह उनके एक और एमपी हैं मीत एयर। उन्होंने भी यही काम किया है एसएचओ लखवीर सिंह के माध्यम से सादे कपड़ों में गए और मनजिंदर सिंह नामक एक व्यक्ति के घर पर गए और महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उसको मानसिक तौर पर इतना पीड़ित किया कि मंजिंदर सिंह ने भी एक सल्फास की गोली खा के अपनी जान देनी ठीक समझी। आप बताइए एमपीज के चलते, एमएलएज के चलते, मंत्री के चलते लोग सल्फास की गोलियां खा के मर रहे हैं ऐसा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हाल बना के रख दिये हैं। एक में आगे बताना चाहता हूँ, पंजाब को इतना बर्बाद किया है आज, पंजाब के दो भाई मैं बड़ा दु:ख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब के दो भाई जिन लोगों को 50 लाख कर्जा हो गया और वो अपने कर्जा देने की स्थिति में नहीं रहे, आम आदमी पार्टी ने फसलों का इतना बर्बादी कर दी और उन्होंने दोनों भाइयों ने फरीदकोट में हाथ में एक दूसरे भाई ने हाथ में हाथ पकड़कर देखिये कितना पीड़ाजनक है, दोनों भाइयों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खुदकुशी कर गये ट्रेन के नीचे आकर। ट्रेन के नीचे आकर, ये पंजाब को देन है आम आदमी पार्टी की। भाई आप सोचिए कितना पीड़ाजनक होगा एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है अब अपने पास विकल्प नहीं बचा, आम आदमी पार्टी की बेईमान सरकार आ गई है। हमारे सिर पर पचास लाख रूपये कर्जा चढ़ चुका है, लाखों रूपये का कर्जा चढ़ चुका है भाई अब हमारे पास बचा कुछ नहीं है एक भाई ने दूसरे भाई की बाजू पकड़ी और दोनों ने जाकर खुदखुशी कर ली। अध्यक्ष जी, जहां मैं आज दोनों परिवारों के साथ गगनदीप रंधावा के परिवार के साथ और जो फरीदकोट में ये घटना घटी उन परिवारों के साथ मैं अपने दु:ख उनके साथ सांझा करता हूं, संवेदना उनके साथ सांझी करता हूं। ऐसे मैं में चाहता हूं कि जो पंजाब के हालात बन गये हैं इसके ऊपर भी हमारे हाउस को, क्योंकि ये बेईमान लोग यहीं से गये हैं ये पहले यहीं लूटते रहे, इसी विधान सभा में लूट-खसोट की बातें करते रहे मेरा मानना है इस मसले को भी पंजाब हमारे परिवार हैं, पंजाब हमारी जान है, हमारा अन्नदाता है, उनकी पीड़ा के अंदर हमारे इस विधानसभा को शामिल होना चाहिए और इसके चलते भी दोनों तीनों विषयों के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: क्या?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उदयोग एवं पर्यावरण मंत्री: एक निंदा प्रस्ताव।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आप पेश कर रहे हैं?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उदयोग एवं पर्यावरण मंत्रीः हां,मैं तो इस इसके ऊपर मैं निंदा प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ कि जो वेयरहाउज़िंग के जनरल मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के साथ घटना घटी। जो घटना उनको सुइसाइड करनी पड़ी। अमृतपाल सुखाना ने जो बेईमानी करके बबनदीप सिंह वालिया के ऊपर अत्याचार किए और गैंगस्टरों से उसको मरवाने की धमकी दी, जो मीत ऐयर, एमपी लोकसभा में इन्होंने एसएचओ लखवीर के माध्यम से अत्याचार किया और मनजिन्दर सिंह ने सल्फास की गोलियां खा के अपना जीवन खत्म करने की कोशिश की और इसी तरह दो परिवार के लोग जो फरीदकोट से आते हैं और दोनों की जान इसलिए चली गई देनी पड़ी, उनको खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी के चलते उन पर 50,00,000 रूपये कर्जे के अंदर डूब चुके थे। मैं इन सब के लिए एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सदन जो है मिलकर इस निंदा प्रस्ताव को पास करेगा जो पाप आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों के ऊपर अत्याचार और पाप कर रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। बड़ी बहुत ही भयंकर जिसको कहा जा सकता है ऐसी घटना है कि रोंगटे खड़ी कर रही है कि एक मंत्री ने इतना प्रताड़ित किया और यह एक फितरत है यहाँ दिल्ली में भी जब चीफ सैक्रटरी थे अंशु प्रकाश जी, उनको भी इसी तरह प्रताड़ित किया गया। इस पर आप तरविंदर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं। इस पर कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं तो।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष महोदय, मैं सिरसा जी की बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छा ये विचार लेकर आए हैं यहाँ पर और इसके लिए निंदा प्रस्ताव भी ला रहे हैं। हम इनके साथ है। अध्यक्ष जी, क्या हो रहा है पंजाब में, आज पंजाब में सबसे पहले तो नशा जो आम कहीं-कहीं जो फिरोजपुर है संगरूर है बॉर्डर के एरिए सब जगह।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः शॉर्ट में।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः छोटा सा बोलूँगा उसके बाद अध्यक्षजी क्या हो रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः टाइम दें। अभी तो पूरा एजेंडा पड़ा हुआ है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी आप तो देते ही है टाइम तो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः चलिए बोलिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः कोई नहीं तो आज जो पंजाब में मैं तो यहाँ पर।

....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः कौन। नहीं, नहीं आप अपनी सीट पर आइये नीरज जी ये कंप्यूटर टूटू कर रहा है, मेरा जो है ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये आवाज क्यों आ रही है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी किस तरह लोगों को, जो अफसर काम नहीं कर रहे, उनको जबरदस्त धमकियां दी जा रही है और वो तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब में शासन नहीं चल रहा है अध्यक्ष जी, सब यहाँ पर कोई दिल्ली में नजर ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है आज 1 साल हो गया जब से हम आए दिल्ली में कोई नजर ही नहीं आ रहा। क्या वजह है, क्या वजह है, वजह ये है वहाँ पर ये चल रहा है अध्यक्ष जी इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे पंजाब में किसी से पूछ लो क्योंकि हमारी तो रोज़ ही बातें होती है, रिश्तेदारी है । ये तो मैंने पहले भी अध्यक्षजी बताया था केजरीवाल के बारे में ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः ये वर्बटिम में थोड़े ही जुड़ पाएगा समझ में नहीं आएगा।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः बोल दो आप लिख लेंगे।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः मैंने तो पहले भी वो राज़ की बात मुझे पता है जहाँ पर उसका पैसा पड़ा है, पहले भी कहा था कि नहीं, वो मैं बताऊँगा अभी समय आएगा। मेरे को सब पता है अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः इसको अपनी बात को कंक्लूड करो कुछ इसको शेप दो।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः ये इसी में आ रहा है ना अध्यक्ष जी ये माल के चक्कर में ही तो ये हत्या हो रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः आपका कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार शामिल है जो सिरसा जी ने उठाया है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः 2000% शामिल है अध्यक्ष जी, 2000 परसेंट शामिल है। ये भ्रष्टाचार से ही वो अफसरों ने क्यों अपने आपको सुसाइड किया, उसको क्यों धमकी दी, अब क्यों एफआइआर हुई, अभी सिरसा जी ने बताया। सारा एकदम जो दिल्ली का शुगल वहाँ पर पहुँच गया है और पंजाब का सत्यनाश हो रहा है। आज मैं आपको ये कहूंगा कि इसके लिए

प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव लाओ और मैं ये भी एक बात आगे होकर कहना चाहता हूँ मैं होम मिनिस्टर साहब को भी अपील करूँगा, वहाँ पर गवर्नर राज़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए नहीं तो इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गयी है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर अब 1 मिनट में खत्म करना।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सिरसा जी ने पंजाब की हालात हमने टीवी में, अखबार में भी देखा। किस प्रकार आम पार्टी की भ्रष्टाचारी मानसिकता की वजह से वहाँ लोगों का जीवन दूभर हो गया है और देश और दिल्ली का जो अन्नदाता प्रदेश है पंजाब, आज केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी के भ्रष्टाचार से त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है। इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात और कहनी है कि दिल्ली में 11-12 साल केजरीवाल और केजरीवाल जी की पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किये हैं अभी उन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का आमूलचूल...

...व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: उनका निराकरण नहीं हुआ है मेरे अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे जगह है जहां नियम कायदे-कानूनों को तोड़कर बिना किसी एसओपी के ठेके उस सरकार ने अपने लोगों को, अपनी जाति के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को दे दिए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यह कहना है पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके परिणाम तो बाद में आएँगे लेकिन दिल्ली में जो कुत्सित कार्य इन्होंने किये हुए हैं और वहाँ अभी उनके लोग जमे हुए हैं, चाहे वो हमारे यहाँ ट्रांसयमुना में पीएसके के जो चलाने वाले हो, चाहे वहाँ पर कॉफी हाउस हो, चाहे गाजीपुर मंडी के अंदर जो काम करने वाले लोग उनका गैंग माफिया काम करने वाला हो, चाहे वहाँ पर और जो दूसरा टूरिज़म के जो जगह अच्छी-अच्छी चीज़े बननी थी, उसमें उन्होंने बारातघर बनाकर अपने लोगों को दे दी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: उन सब लोगों का ध्यान करके दिल्ली की जनता को उनसे निजात दिलाया जाये। जय हिंद, जय भारत।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब जो माननीय मंत्री श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा द्वारा रूल 114 में जो निंदा प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया गया और उन्होंने जो एक बहुत विशेष बात यहां रखी जो महत्त्व की है कि अगर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका कॉग्निजेंस पार्लियामेंट में न लेते तो ये एक जो निर्मम हत्या मैं कहूंगा इसको, ये आत्महत्या नहीं है

किसी व्यक्ति को और वो भी एक ऑफिसर को। इस स्थिति में ला देना, मानसिक पीड़ा के साथ कि उसको सूसाइड करना पड़े और जिसके पीछे भ्रष्टाचार मुख्य कारण हो। तो हम देश के गृह मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने न्याय के मार्ग पर उस परिवार को न्याय मिले इस ओर इस मामले को आगे बढ़ाया है। तो जो प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है-

जो उसके पक्ष में हैं, वो हां करें।

और जो इसके विरोध में है वो ना करे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

निंदा प्रस्ताव पारित हुआ।

अब सदन की कार्यवाही।अच्छा।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, ये लास्ट पाइंट है पंजाब में जितने हालत खराब है। पंजाब केसरी जो अखबार है उसके यहाँ पर भी छापा डलवाया, उसके मालिक को थ्रेट किया। उसको कहा की हमारी खबरे छापों जब।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये जो तरविंदर सिंह मारवाह जी ने बात कही है इसको भी इसी प्रस्ताव में।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उदयोग एवं पर्यावरण मंत्री: ये बड़ा जरूरी है। जिस तरह से यह बहुत है ये डेमोक्रेसी के और।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये इसी प्रस्ताव में पार्ट-2 के रूप में।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय उदयोग एवं पर्यावरण मंत्री: उनका घर उनके होटल के ऊपर बुलडोजर लेके गए, हाई कोर्ट उनके घर पे जाके रेड करी और उनका कसूर क्या था? उन्होंने पंजाब के लोगों की आवाज को उठाया और मंत्री के खिलाफ़ कार्रवाई करी और बुलडोजर लेके जाके उसका बुलडोजर खड़े करके उसका होटल गिराना शुरू कर दिया। मतलब ये गुंडागर्दी की कोई इंतेहा हो सकती कि अगर कोई आपके खिलाफ बोलेगा और मैं आज आपके मंच से ये भी एक बार कहना चाहता हूँ कि पंजाब में जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है हमारी विधानसभा को इसको टाइम टाइम पे संज्ञान लेना चाहिए। हम उनको संरक्षण दे पाए ताकि वो अपना काम भी ईमानदारी से कर पाएं। धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः जो माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह जी ने एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ इसी प्रस्ताव से जोड़ते हुए, जो मीडिया पर जिस प्रकार का कुठाराघात हुआ है और उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है क्योंकि जगवाणी और पंजाब केसरी, जो पंजाब का लीडिंग अखबार है।जो एक तरह से घर घर में पहुंचता है। अगर उस मीडिया हाउस के साथ इस तरह की नाइंसाफी, दरिंदगी की गई है तो ये सदन कड़े शब्दों में ऐसी मानसिकता, ऐसी पार्टी ऐसे लोगों की निंदा करता है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो प्रहार किया गया। उसको दिल्ली की विधानसभा लोकतंत्र पर एक प्रहार के रूप में देखती हैं और इसलिए इस प्रस्ताव का जो एक एक्सटेंशन के रूप में इसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। जगवाणी।

श्री हरीश खुराना: पिछले दो महीने के अंदर पंजाब केसरी के बाद तीन बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें उनके ऊपर, उनके मालिको के ऊपर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उनको दबाने की कोशिश की गई है। ये इसमें और ऐड किया जाए ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः अखबार के जो मालिक हैं। उनको जो व्यक्तिगत मानसिक पीड़ा उस परिवार को और उनकी जान एक प्रकार से खतरे में है, ये सदन उस पर भी चिंता करता है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं वो कल को उनके ऊपर किसी प्रकार का व्यक्तिगत हमला भी कर सकते हैं, शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं तो ये दोनों विषय इसमें जोड़ करके और इस प्रस्ताव को हम पारित करते हैं। अब सदन पटल पर अब श्री आशीष सूद जी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक दो में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

श्री आशीष सूद, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक दो में दर्शाए गए दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

2. इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईआईटीडी) के वित्त वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लेखे, पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) एवं कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तथा वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)[1]

---

[1] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23571 पर उपलब्ध।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इस पर अब सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री: क्योंकि आज का भी बिज़नेस काफी है और हम को बजट पे अपना चर्चा भी करनी है। इसलिए मेरा सरकार की तरफ से प्रस्ताव है की हम ये अपने सत्र को 1 दिन के लिए और बढ़ा दें। कल हमारा राम नवमीं का अवकाश रहेगा तो परसों 1 दिन के लिए सत्र को बढ़ा दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्रवाई 1 दिन के लिए बढ़ाई जाती है और सभी सदस्य इसमें सहमत हैं तो 27 तारीख को कल छुट्टी रहेगी। 27 तारीख को भी सदन की बैठक 11:00 बजे से और अभी सदन की बैठक 2:00 बजे फिर से प्रारंभ होगी और लंच के लिए सदन की बैठक को स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन पुन: अपराह्न 02:03 बजे समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा जम्मू कश्मीर के 110 छात्र, छात्राओं का स्वागत

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज मैं सदन में 110 प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो कश्मीर युवा आदानप्रदान कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा, 'माई भारत' के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर ये 110 बच्चे आज हमारी कार्यवाही देखने के लिए, परिसर में आए हुए है। ये छात्र जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों, अनंतनाग, बड़गाम, बारामूला, कूपवाड़ा, बांदीपोरा, श्रीनगर और पुलवामा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस गरिमामयी सदन की कार्यवाही को देखने तथा हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की कार्यप्रणाली को निकट से समझने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनकी उपस्थिति न केवल प्रेरणादायक है और सार्थक है, बल्कि ये सहभागिता सीखने और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी प्रतिबिंबित करती है। साथ ही यह हमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का स्मरण कराती है कि हम सदन की गरिमा, अनुशासन और संसदीय आचरण के उच्चतम मानको को बनाए रखें। आए हुए सभी युवा साथियों का, छात्र, छात्राओं का हम अभिनंदन करते हैं उनको बैच में यहाँ पर कार्यवाही के लिए यहाँ पर बैच में लाया जाए।

अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 23 मार्च 2026 को सदन पटल पर प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक के प्रतिवेदनों पर चर्चा होगी। उसके लिए मेरे पास जो मुझे नाम प्राप्त हुए हैं और कल जो सीएजी रिपोर्ट्स पेश की गई थी उसमें जो रिपोर्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2025, (24 का प्रतिवेदन संख्या-05) पर श्री प्रवेश वर्मा, माननीय मंत्री जो है इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे।

सी.ए.जी. रिपोर्ट पर चर्चा

श्री प्रवेश वर्मा, माननीय लोक निमार्ण विभाग मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। कल जो कैग रिपोर्ट पेश हुई। उसमें जो बहुत ही भयंकर खामियां, इस रिपोर्ट में आई हैं। मैं उसमें शीश महल के ऊपर में जो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर में बोलना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर से आए हुए सारे हमारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ सरकार की तरफ से। आज जम्मू कश्मीर भी पूरे देश का अभिन्न अंग, हम जानते हैं कि आजादी के बाद में कैसे उस समय की जो हुकूमत थी उन्होंने हमारे देश के ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को देश से अलग रखा। पहले देश में दो कानून चलते थे, दो संविधान चलते थे, दो निशान चलते थे, दो प्रधान चलते थे। मगर मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके दूरदर्शी सोच से आज वहाँ पे जम्मू कश्मीर में सुकून का शांति का माहौल है और उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है हमारे सामने हमारे बैठे बच्चे, हमारे देश की युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है। आज पूरे देश में घूम रहे हैं, देश के संविधान को जान रहे हैं और आज वो दिल्ली विधानसभा में आए हैं, उनका एक बार में फिर से स्वागत करता हूं। शीशमहल के ऊपर में हम सभी ने बहुत बार इसको सुना है शीश महल, शीश महल दो लाइन से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि:

''मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना,

मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना

और चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली को खा गए।''

हमें याद है कि जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ये शपथ खाई थी कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी घर नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, ना ही कोई सिक्योरिटी लूँगा। मगर उनके शपथ लेते ही 20 दिन के अंदर उन्होंने दिल्ली की जनता को टोपी पहना दी। 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 4 मार्च, 2015 को छह फ्लैग स्टाफ रोड में जो बंगला था उसको खुद ही

अपने आप को अलॉट किया और साढे चार साल के बाद में 2020 के दौरान दिल्ली में दो आपदा आई। पहली आपदा कोविड की और दूसरी आपदा, आम आदमी पार्टी की। जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना शीश महल बनाने का काम शुरू किया। अध्यक्ष जी, अभी दिल्ली में एक देश में नई पिक्चर रिलीज हुई है धुरंधर, बहुत ही चर्चा में है। उसमें एक किरदार की बहुत चर्चा है रहमान डकैत। ये दिल्ली के डकैत थे अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने दिल्ली के पैसों पर डाका डाला। मगर हमारे मतदाता धुरंधरों ने ये दिल्ली के डकैतों को एक साल पहले हरा दिया क्योंकि वो समझ गए थे। जो 11 साल से ये लोग झूठ बोलते थे आज ये हाल हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कहते हैं तो ना केवल दिल्ली के, बल्कि देश का हर व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति झूठ ही बोल रहा होगा। आज वो जो भी बात बोलते हैं, उनके नेता कोई भी बात बोलते हैं तो हर बच्चा ये जानता है कि अब केजरीवाल जी कुछ भी बोलेंगे, वो केवल झूठ ही बोलेंगे, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। शीशमहल जो बना, वो शीश महल, अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोच के बनाया था कि जीवन में मुझे कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। जो उन्होंने लोकेशन का चयन किया वहाँ पे तीन टाइप फाइव के बंगले थे, हेरिटेज बंगले थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पे छह गैराज थे, 10 टाईप वन, टाइप टू के क्वार्टर थे। बिना परमिशन के, सारे पेड़ों को कटवा कर, सारे घरों को बिना परमिशन के तुड़वा कर उसके बाद में कहानी शुरू होती है शीशमहल बनाने की। सीएजी ने जो इसमें अपने प्वाइंट्स को रेज किए, अपने कन्सर्न को रेज किए हैं। मैं एक फोटो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सभी सदस्यों को कि ये पहली पिक्चर है जब शीशमहल नहीं बना था और इसमें कितनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक भी पेड़ की परमिशन नहीं ली गई थी। और उसके बाद में जब शीशमहल बना तो ये पिक्चर देखिए। ये जो खाली खाली जगह है ये सारे पेड़ों को कटवा दिया गया। एक भी पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी। सारे घरों को तुड़वा दिया गया, तीन वहाँ पे ऑफिसर रहते थे, तीनों का घर खाली कराया गया, तीन वहाँ पे सेक्रेटरी रहते थे, तीनों का घर खाली कराया गया, सारे गैराज को तुड़वाया सर्वेंट क्वार्टर तोड़ दिए, 8-10 क्वार्टर तोड़ दिए। मैं यहाँ पे हमारे सारे साथियों को ये भी बात कहना चाहता हूँ कि हमने केवल शीश महल देखा था शीशमहल। मगर शीशमहल पार्ट टू भी बन रहा था शीशमहल के जस्ट साथ में। एक अरविंद केजरीवाल जी जब शीशमहल हो गया बन गया, उसके साथ में एक और 4000 गज की जगह थी उसके साथ में भी उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर शीश महल टू का उन्होंने वहाँ पर बनाने का काम शुरू कर दिया था ₹25 करोड़ उसके ऊपर खर्च भी कर दिए थे, वो खाली ढांचा खड़ा हुआ है। वो तो सरकार बदल गई वरना उसके ऊपर में भी ये ₹60 करोड़ खर्च होना था। तो शीशमहल एक नहीं है, शीशमहल दो हैं। केवल आपने शीश महल की पिक्चर देखी जो शीशमहल के साथ में एक और बहुत बड़ी इमारत बन रही थी वो शीश महल का पार्ट टू था। अब ये सारा जो शीशमहल बनने का समय था वो क्या था

समय? ये हैरानी की बात है कि शायद कोई इंसान तो छोड़िए, जिसके अंदर 1% भी दया की भावना है, जिसके अंदर 1% भी इंसानियत की भावना है वो ये फैसला नहीं ले सकता कभी भी कि जब दिल्ली में कोविड का समय चल रहा था उस समय शीशमहल बनने के आदेश दिए गए थे। दिल्ली में एक भी कोविड हॉस्पिटल बनाने के आदेश नहीं दिए। आदेश दिए जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का घर बनाना है और उस फाईल के ऊपर में मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है, मोस्ट अर्जेंट। इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, उनके सारे मंत्रियों ने दिल्ली में सीवर लाइन चेंज करनी हो, एक भी फाईल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। दिल्ली में पानी की लाइन, एक भी फाईल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा, एयर पाल्यूशन पर एक भी फाईल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा, दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल बनाने हैं, ऑक्सीजन लानी है, हमको आइसीयू बेड लेके आने हैं एक भी फाईल के ऊपर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। केवल 11 साल में एक फाईल के ऊपर में मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है और वो फाईल होती है शीशमहल बनाने की। क्योंकि ये सोचते थे कि मुझे कौन हराएगा, मैं ऐसा बंगला बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा, उसमें इतना पैसा खर्च करूँगा कि मेरे को तो जीवन भर यही रहना है, मेरे को कौन निकाल पाएगा? मैं सारी दिल्ली को ऐसे गुमराह कर रहा हूँ कि आपको पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। मीडिया का ऐड बजट पहली मीटिंग में कैबिनेट मीटिंग में ₹500 करोड़ कर देना और सारे सिस्टम को खरीद लेना। उसके बाद में बनता है शीश महल। शीशमहल जो मैंने आपको बताया कोविड चल रहा था। भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 787.91करोड़ की सहायता दी कोविड में, हम ये आपको पैसा दे रहे हैं, आप दिल्ली में लोगों की जान बचा लीजिए। वो पैसा अरविंद केजरीवाल से खर्च नहीं हुआ। 787.91करोड़ में से केजरीवाल जी ने केवल ₹582 करोड़ खर्च किया। भारत सरकार का पैसा था, दिल्ली सरकार का एक भी रुपया नहीं था। भारत सरकार ने पैसा दिया था। मगर जान बचाने का पैसा खर्च नहीं हो रहा, वो पैसा बचा रहे हैं मगर शीश महल का जो पहला टेंडर एस्टीमेट बना था वो बना था ₹7.5 करोड़ का। उस एक ही टेंडर को पहली बार देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली घटना होगी कि ₹7.5 करोड़ के टेंडर को सीधा ₹55 करोड़ लेकर जाना। वही ठेकेदार, जो ठेकेदार की कैपेसिटी ₹7.5 करोड़ थी, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। वहीं कोविड के समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित कुमार ने दिल्ली में बीमार लोगों की अस्पताल में जान बचाते हुए अपनी जान उसने गंवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अमित कुमार को ₹1करोड़ दूंगा मगर क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं था इसलिए 1करोड़ नहीं मिला। वो कॉन्स्टेबल की वाइफ को हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा कि मेरे हसबैंड ने दिल्ली के लोगों की जान बचाई। वहाँ से ऑर्डर मिला तब उनको पैसा मिला। खजाने खाली महल ऊंचे, राजा के बस अपने कूचे। अगर ये ₹58 करोड़ जो शीश महल पे खर्च हुआ अध्यक्ष जी, अगर वही समय में भारत सरकार ने एक आइसीयू बेड की कॉस्ट

को फिक्स कर दिया था ₹15 हजार रूपये। अगर ये ₹58 करोड़ को आइसीयू वेंटिलेटर बनाने में खर्च किया होता तो हम दिल्ली में 2300 नए आइसीयू वेंटिलेटर बेड बनाकर 2300 लोगों की जान बचा पाते, 26 हजार लोगों की मृत्यु हुई 26 हजार दिल्ली के अकेले लोग मरे। अगर ये ₹58 करोड़ उसी समय में शीशमहल में खर्च नहीं होते तो 2300 लोगों की जान बच जाती दिल्ली में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शीशमहल बन रहा था और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या बोलता था? सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2020 को बोला कि दिल्ली की कोविड स्थिति खतरनाक हो गई है, हॉरिफिक हो गई है, पैथेटिक हो गई है, पेशेंट्स को जानवरों से बदतर ट्रीट किया जा रहा है। और उसी समय एक तरफ में टेंडर हो रहा है। 11 नवंबर 2020 को हाई कोर्ट कहता है कि कोई भी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रही है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र में केवल केरल से ज्यादा, दिल्ली में अकेले इतने सारे केसिज आ रहे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है मगर दिल्ली में उससे ज्यादा केसिज हो रहे थे क्योंकि सरकार सोई हुई थी। फिर उसके बाद 27 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट ने फिर से डांट मारी। 'इनफ इज़ इनफ'। 25 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डांट मारी कि दिल्ली भारत सरकार से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है। जितनी दिल्ली को जरूरत है, उससे ज्यादा मांगते थे, क्यों मांगते थे क्योंकि उनको पता था पूरे देश में भारत सरकार आक्सीजन दे रही है। अगर मैं अपनी आवश्यकता से चार गुना ज्यादा मांगूंगा तो भारत सरकार मना करेगी कि इतनी आपकी आवश्यकता नहीं है और जब वो कहेंगे कि आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो मैं कहूंगा मोदी जी हमको आक्सीजन नहीं दे रहे। मतलब कोविड में भी उनको राजनीति सूझ रही थी। तो एक तरफ जहां पर दिल्ली में लोग मर रहे थे उसी समय में शीश महल बनाया जा रहा था। इससे खराब स्थिति और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीश महल की जो पहली सैंक्शन आती है एक सितम्बर 2020 को 7.91 करोड, क्योंकि चीफ इन्जीनियर की पावर फाईनानशियल पावर आठ करोड से कम होती आठ करोड तक होती है। वो चाहते थे कि चीफ इन्जीनियर से ऊपर कोई फाईल ही नहीं जाये और चीफ इन्जीनियर अपनी पावर में ये सारी सैंक्शन कर दे। इसलिए उन्होंने 7.91 करोड का पहला टेंडर किया। फिर उसके बाद में आठ जून डेढ करोड रूपये बढा दिया। फिर 22 अक्तूबर को 9 करोड रूपये बढा दिया। 30 दिसम्बर को 6 करोड रूपये बढा दिया। 29 जून को फिर से साढे नौ करोड रूपये बढा दिया। इसी समय में दिल्ली में 26 हजार मौत हो रही है और बार-बार उस फाईल के ऊपर में लिखा जा रहा है मोस्ट अरजेंट है काम करयिे। जब 2021 में देश में बार-बार कर्फ्यू लगता है। जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है देश में कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई ऑफिस नहीं चल रहा। सारे लोग वर्क फरोम होम कर रहे हैं। घर के अंदर बैठे हैं। कोई एक गाडी नहीं दिखाई दे रही है। मगर शीश महल की कन्सट्रक्शन का काम एक भी दिन नहीं रूका। एक भी दिन। 24 घंटा 365 दिन क्योंकि मोस्ट अरजेंट केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा है। राजा का महल बन रहा

है। इसलिए उसको हमें बनाना है। मैं क्या-क्या उसमें आईटम लगाई गई। ये मैं उसका एक बहुत ही छोटा पर्चा लेकर आया हूं, क्या-क्या आईटम लगाई गई। तो वहां पर फर्नीचर लगाया गया, सोफा लगाया गया। दो उसके टेंडर हुए पहला 35 लाख का हुआ, दूसरा डेढ लाख का हुआ। फिर वो टेबल लगाई गई 76 टेबल। एक करोड पांच लाख रूपये की टेबल। बैड लगाये आठ, चालीस लाख रूपये के बैड। फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रूपये की। फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रूपये की चेयर। फिर वो रिक्लाईनर चेयर। केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते-देखते, जिम करते-करते थक जाते थे वो रिक्लाईनर चेयर जो पूरा बैड बन जाती है वो भी अलग से ली गई। पांच चेयर ली गई पांच लाख रूपये की, साढे पांच लाख रूपये की। फिर उसके बाद में बुक सेल्फ लिये गए पांच लाख रूपये के। फिर कारपेट लिये गए, कारपेट लिये गए 60 लाख रूपये के। फिर उसके बाद में पफ्फी, पफ्फी मतलब कोई ये डॉग का नाम नहीं है। जो सोफे के साथ में छोटे-छोटे से होते है, वो उन्होंने लिया 70 हजार रूपये के दो पफ्फी लिये। फिर कन्सोल आठ लिये गए। पचास लाख रूपये के कन्सोल लिये गए। फिर कर्टन खरीदे डेढ करोड के कर्टन खरीदे। फिर blinds खरीदे। पंद्रह लाख के blinds खरीदे फिर वास खरीद, वास भी 6 लाख रूपये के खरीदे। ये खत्म नहीं होयेगी रात तक। ये लिस्ट आयेगी जकूजी भी आयेगी, जकूजी भी आने वाली है। गोल्डन सीट्स सब आने वाली है। डायनिंग टेबल अब घर में पांच लोग थे, डायनिंग टेबल 28 लोगों की डायनिंग टेबल है 14 लाख रूपये की टेबल, उसकी चेयर अलग से। फिर स्माल साईज स्टोरेज ये लिया गया। ट्रोली टोटल मतलब अमाउंट सोच-सोच के चक्कर आ रहे थे। जिम, जिम में ट्रेड मिल, एक ट्रेड मिल 14 लाख रूपये की। फिर ट्रेनर, ट्रेनर कोई था । अच्छा ट्रेनर को भी वो दिया पैसा। स्पीन बाईक वो एक लाख रूपये की, trainer fusion crest ये तीन लाख रूपये का जिम बॉडी सोलिड ये 6 लाख रूपये का, डम्बल केजरीवाल जी को देखकर लगता नहीं डम्बल उठाते होंगे। अब डम्बल भी ले रहे तीन लाख रूपये के। फिर राउंड डम्बल, राउंड डम्बल अलग है ढाई केजी के, पांच केजी के साढे सात केजी के, पन्द्रह केजी का भी। फिर ये एक लाख रूपये के डम्बल हैं। कैटल बेल है, अदर जिम है, फिर इलैक्ट्रिकल आईटम्स हैं, 12 लाख रूपये की सीलिंग डैकोरेटिव फिटिंग ये है 14 लाख रूपये का। डैकोरेटिव वॉल लैम्प, ground burial light फुट लाईट, chandelier , आप देखिये डेढ करोड रूपये के chandelier हैं। दिल्ली के लोग रो रहे है कि कोविड में बैड दे दो, वेन्टीलेटर दे दो, आईसीयू दे दो, दवाई दे दो, आक्सीजन दे दो और ये chandelier खरीद रहे है। गोल्ड प्लेटिड chandelier खरीदे जा रहे है। hanging decorative light फिर फ्लोर standing लाईट मतलब एक-एक करोड रूपये के, टेबल लैम्प, कैमरा, फिर कैमरा लगाये गए। सब वुफर लगाये गए। टीवी के साथ में, टीवी के awaz kam hai sub-woofer लगाए गए। अम्प्लीफायर लगाये। फिर pre- amplifier लगाये। टोटल 11 टीवी लगाये गए, डेढ करोड रूपये के। barbeque unit जहां पर चिकन टिक्का बनाया जाता है। barbeque unit वो लगाया गया।

हैंगिंग लाईट, हैगिंग लाईट अलग से। AP router, सीलिंग स्पीकर, बॉस कंपनी के ये कितने के चालीस लाख रूपये के। फिर एसी टोटल 50 एसी लगाए 50, 50 एसी लगाये टोटल। फिर एनवीआर लगाया पांच लाख का रेफ्रिजरेटर।

माननीय अध्यक्षः ये सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य है मतलब माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह (माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री) : रेफ्रिजरेटर लगाएं।

माननीय अध्यक्षः कि ये जो सीएजी रिपोर्ट है उसमें ये सब फैक्ट है।

श्री प्रवेश साहिब सिंह (माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री) : फार्मा ड्रायर एस ओह बी स्टीम ओवन। मतलब नौ लाख रूपये का स्टीम ओवन, माइक्रोवेव दो लाख का, dumb waiter lift, वाशिंग मशीन, अदर आइटम्स, टॉयलेट आइटम्स, टॉयलेट सीट, पांच लाख रूपये की टॉयलेट सीट। फिर शावर टोटल 09 शावर है 6 लाख रूपये के साढे छः लाख रूपये के। शावर मिक्सचर, वॉल हुंग, वाटर क्लोज़र, ग्लास शावर, बाथ टब, डिजाइनर चेयर, डिजाइनर स्टेयर केस। चालीस लाख रूपये के जकूजी, ये आ गयी जकूजी।

माननीय अध्यक्षः नीरज जी । माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे। माननीय

सदस्य नीरज जी, आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह (माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री) : 6लाख रूपये का जकूजी। फोल्डेबल ग्लास, 6 लाख रूपये का steam generator bath spa, शावर्स स्टिम, सोना बाथ, स्टडी चेयर। lutyens chair. छः लाख रूपये का lutyens chair अलग से क्या होता है पता नहीं। आम चेयर फिर आम चेयर टाइप टू, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, बेड साइड। फिर आपका जॉर्जियन कंसोल, इम्पोर्टेड कंसोल, डिस्प्ले, सेल्फ, मिनी बार। डबल बेड, मिनी बार भी है जी 6 लाख रूपये का मिनी बार है। डबल बेड,

माननीय अध्यक्षः आपस आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री प्रवेश साहिब सिंह (माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री) : सात लाख रूपये का राउंड बेड, दस लाख रूपये का टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी, एक टीवी देखो आप। एक सिंगल टीवी वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा 88 इंच का 88 इंच का एक टीवी है 28,91,587/- रूपये एक टीवी। फिर चिमनी है, सोफा 08 सीटर सोफा, फ्री स्टैंडिंग यूनि। फ्री स्टैंडिंग। अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए। लुमिनरी, एंट्रेंस लाइट। फिर एक और आया टीवी सुनो। फिर तीन टीवी और आए वो वाले नौ टीवी अलग थे एक टीवी अलग था। फिर एक और टीवी आता है, तीन टीवी आते हैं। ये है 27 लाख रूपये के तीन टीवी। फिर है वेनिशियन ब्लाइंड। फिर है टीवी

कंसोल। तो अध्यक्ष जी ये है आम आदमी पार्टी। ये है शीश महल, देखिये लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है। वहाँ तक पहुँच गई सामने वालों की टेबल तक। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस देश में सारी चीजें उपलब्ध है। सारी चीजें जैम पोर्टबल पर वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पे रेट जो है वो उपलब्ध है मगर आप सारे टेंडर को सीएजी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने उठाई है कि टेंडर को अपने हिसाब से बनाया। टेंडर को कैसे बनाना है। कौन से चार कॉंट्रैक्टर उसमें बिड डालेंगे और तीन कॉंट्रैक्टर को निकाल देंगे। केवल एक कॉंट्रैक्टर जो पहले से डिसाइड है, उसी को काम देना है और उससे ये सारे काम को कराते रहना है। दो कैसलटेंट रखते हैं। पहले कैसलटेंट रखते हैं उससे पूरा घर ये सब कर लेते है। एक अलग से कैसलटेंट रखते हैं, केवल जो है एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए एंटीक और डिजाइनर चीजों के वो अलग से कैसलटेंट रखते हैं। क्योंकि वो आदमी सोचता था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जीवन भर ये मैं कोई सरकारी बंगला नहीं बना रहा हूँ और ये जो आम आदमी पार्टी के सारे लोग बोलते रहते हैं, ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, मुख्यमंत्री के लिए बनाया था तो ये अतिशी को क्यों नहीं घुसने दिया उस बंगले में। जो हमारी विपक्ष की नेता है वो भी तो मुख्यमंत्री बनी थी। ना उनको हमारे secretariat में सीएम की कुर्सी पर बैठने दिया, ना यहाँ पर शीशमहल में घुसने दिया। क्योंकि मेरी कुर्सी पर मैं राजा हूँ इसी स्थान पर खड़ा हो के कहता था, मैं हूँ दिल्ली का राजा, मैं हूँ दिल्ली का मालिक। तो मेरे बेड पर क्या अतिशी सोएगी, मेरी डाइनिंग टेबल जो मैंने 20 लाख की खरीदी आतिशी वहाँ पर खाना खाएगी। जो मैं मेड इन स्पेन से लाऊं क्रॉकरी क्या वो उसमें चाय पीएगी, जो मेरी रिक्लाइनर चेयर है वो उसपे बैठेगी। उसको घुसने नहीं दिया। आप नहीं घुसेगी वहाँ पर। मैं दोबारा आऊंगा, फिर मैं वहाँ पर रहूंगा, फिर मैं बाद में फिर आऊंगा, फिर मैं रहूँगा, ये उसकी मानसिकता थी। मगर मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस झूठे, मक्कार, ड्रामेबाज आदमी को पहचाना और उसको अपनी औकात दिखाई। ये सारी सैंक्शन बहुत ही हैरानी की बात है कि सारी सैंक्शन ए टु जैड यानी एस्टीमेट पास होना, सारे इंजीनियर के साइन होना, शीशमहल का जो पूरा कांट्रैक्ट था। आपको हैरानी होगी 1 दिन में पास होता है, 1 दिन में। सारे इंजीनियर सारे लोग एक ही दिन में साइन कर देते हैं, एक ही दिन में एस्टीमेट बन जाता है। यहाँ पर कोविड में हम देख रहे हैं फाइलें भाग रही है इधर उधर। यहाँ पे हॉस्पिटल में फाइलें भागती थी, इधर उधर यहाँ पे आरोप लगाया जाता था एल जी साहब के ऊपर में, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में। मगर शीशमहल की फाइल 24 घंटे में अप्रूव होती है। बहुत सारी बातें अध्यक्ष जी। कैसे जैसे रामायण की सुरसा का मुँह बड़ा होता रहता था, वैसी एस्टीमेट बड़े हो गए। *7* करोड़ से सीधा हर महीने दो महीने में आठ 8-8 करोड़ बढ़ा दिया जाता था। बहुत सारी गंभीर बातें अध्यक्ष जी तो मैं यही पर अपनी बात को खत्म करूँगा पहले भी हमने बहुत बोला है शीशमहल के ऊपर में। हमारी सरकार बनी हम तो सब ने बोला था, मुख्यमंत्री जी को आप चले जाइए,

शीशमहल में मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ पर सिल्क के कारपेट, वहाँ पर 40-40 लाख के सोफे हैं, 30-30 लाख का टीवी है, वहाँ पे जकूजी है, स्टीमसोना है। वहाँ पे 2-2 करोड़ रूपया, वहाँ पर वियतनाम का मार्बल है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर मैं प्रवेश, वहाँ चली गई फिर मेरा जहांगीरपुरी जाने का मन कैसे करेगा। सिल्क कारपेट के ऊपर पैर कदम रखने के बाद में किराड़ी जैसे, फिर मैं किराड़ी जाने का मन कैसे करेगा, फिर मैं मुंडका कैसे जाऊंगी, नजफगढ़ कैसे जाऊंगी, ईस्ट दिल्ली के गांव में, कॉलोनी में झुग्गियों में कैसे घूमूँगी। ये बात ठीक है, जब एक आदमी को शीशमहल में रहने की आदत पड़ जाएगी। जब सिल्क के कारपेट उसको दिखाई देंगे, बड़े-बड़े वहाँ पे जकूजी का बेड दिखाई देगा जहाँ पे 60 नलके लगे हुए। तो वो गांव के कॉलोनियों में, झुग्गी-झोपड़ियों में कैसे जाएगा, उसका जाने का मन ही नहीं करेगा और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ना वो secretariat जाते थे, ना वो अपने ऑफिस जाते थे, ना वो किसी फाइल पर साइन करते थे। क्योंकि उनको पता था अगर फंसेगा तो उनके मंत्री फंसेंगे मैं थोड़े ही ना फंसूंगा। तो ये अध्यक्ष जी दिल्ली की जनता के ऊपर में रहमान डकैत ने बहुत बड़ी डकैती करी। मगर दिल्ली की जनता ने धुरंधर मतदाताओं ने उनको पहचाना, उनको उनका रास्ता दिखाया और आज दिल्ली की सरकार 24 घंटे सड़कों पर दिखती है हमारी मुख्यमंत्री जी। और ये भी मैं आपको अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, ज़रा इस बात के ऊपर में भी ध्यान दीजिएगा। कल जैसे ही पता लगता है। ये कोई कोइंसीडेंस नहीं है, जैसे ही पता लगता है की 1 लाख करोड़ का बजट लाने के बाद आज मुख्यमंत्री जी एक लाख तीन करोड़ का बजट लेके आ रही है, दिल्ली के हर विभाग को पैसा दे रही है, दिल्ली की बच्चियों को साइकिल दे रही है, बच्चों को लैपटॉप दे रही हैं, उसी समय कोई देश का आतंकवादी देश का दुश्मन आपको ईमेल करके धमकी देता है कि ये बजट ना चले टेलीविजन पर। ये बजट दिल्ली की जनता तक देश की जनता तक ना पहुंचे। ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे भी षड्यंत्र हो सकता है। जो लोग अभी जैसे सिरसा जी, मारवाह जी कह रहे थे। जब वो एक पुलिस वाले का घर तोड़ सकते हैं, जब वो एक आदमी को आत्महत्या के ऊपर में मजबूर कर सकते हैं, जब वो पूरे पंजाब को ड्रग्स से भर सकते हैं तो वो दिल्ली में भी अशांति फैलाने के लिए, ये तरह तरह की बातें करके और ये जो स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेटस आती हैं अध्यक्ष जी ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वही लोग करा रहे हैं जो दिल्ली के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। तो मैं शीशमहल की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सदस्यों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः इससे पहले की मैं अगले सदस्य को बोलने का अवसर दूँ। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 27 मार्च, 2026 को भी आयोजित की जाएगी जैसा अभी हम लोगों ने तय किया है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है सूचित किया जाता है सभी सदस्यों, क्योंकि नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के नोटिस। कल शाम 5:00 बजे

तक, नियमानुसार नेवा के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है और कल छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप नेवा पर कल शाम के 5:00 बजे तक अपना 280 का नोटिस दे सकते हैं। वैसे तो आज शाम तक ही 5:00 बजे तक था, लेकिन क्योंकि नेवा की फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है तो लेकिन आपको ये 280 का नोटिस देना अवश्य है। जो भी सदस्य अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। अब हमारे एक सदस्य हैं जो अभी आज सदन में उपस्थित नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका जन्मदिन है और वो मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी कल, श्री अनिल कुमार शर्मा जी और उनको आज सदन में आना था लंच के बाद। हो सकता है फ्लाइट वगैरह उनकी लेट हो गई हो, 3:00 बजे तक आएँगे, लेकिन चलिए मैं अब उनकी गैरहाजरी में ही उनको जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। जब आएँगे तो फिर से एक बार। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार शर्मा जी का जन्मदिन है मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि वे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। अब सीएजी की रिपोर्ट पर माननीय सदस्य श्री राजकुमार भाटिया जी।

श्री राजकुमार भाटिया, माननीय सदस्य: धन्यवाद, अध्यक्ष जी। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आपने मुझे कुछ तर्कसंगत टिप्पणियां जो कैग में की गई है उस पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमारे माननीय मंत्री श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने उस शीशमहल का पूरा ईसीजी इस सदन में घुमाया है। एक एक वस्तु की सिलसिलेवार ईसीजी रिपोर्ट और ईसीजी रिपोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट है। शायद अगर यहाँ पर आज विपक्ष होता जो उस समय पक्ष में था तो उनको भी कुछ जानकारियां नहीं मिलती क्योंकि ये जानकारियां उन तक भी नहीं थी। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को बाद में पदभार ग्रहण करने के बाद भी उस शीशमहल में जाने का अवसर नहीं मिला आज भी वो इस सौभाग्य से वंचित रह गई थी उस शीशमहल के बारे में जान सके। यह रिपोर्ट मात्र एक फाइनैंशल रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष जी, यह रिपोर्ट दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के रुपए के साथ, टैक्सपेयर के रुपए के साथ किया गया एक व्यवस्थित साजिश और खिलवाड़ है। जिसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक ऐसा भवन बनाया जो पिछली राजशाही का हमें याद दिलाता है। मुगल सल्तनत के उन शहंशाहों की याद दिलाता है जो अपनी ऐशोअय्याश और रहने की जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतों के साथ पूरा सामान जुटाते थे और उस समय की राजशाही क्या करती होगी ये तो पता नहीं चला लेकिन श्री केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को उस समय उसके साथ उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जब सबसे ज्यादा एक प्रदेश के मुखिया की जरूरत जनता को होती है वो कोविड काल था। माताएं भी बिलख रही थी, बहनें रो रही थी, पिता दवाई के लिए तड़प रहा था। आप में से कोई भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हाथ उठाकर ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे थे और मुझे इलाज मिल रहा था। पैसा गौण हो गया था, पद गौण हो गए

थे, प्रतिष्ठा गौण हो गई थी। हर आदमी हॉस्पिटल्स की लाइन में लगा हुआ था। एक अनजाना सा भय था उस समय में, इस प्रदेश का मुखिया आपने भवन के निर्माण की बात करता है और ये एक पूरी साजिश थी जिसमें विभाग के ठेकेदार भी जुड़े थे, मंत्री भी जुड़े थे और एक त्रिकोणीय रूप से पब्लिक के रुपए को खर्च करने की बात उस समय चली थी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड, इसका नाम था 6फ्लैग स्टाफ रोड, लेकिन जब भवन निर्माण हुआ ना 6रहे, ना फ्लैग की मर्यादा का ध्यान रखा गया और ना स्टाफ की मर्यादा का ध्यान रखा गया, उन्हें भी वहाँ से विस्थापित करके, अभी तो ये जितनी रकम कैग ने गिनी है, उन बंगलों की कीमत इसमें नहीं लगाई है। 21 करोड़ रुपए एक बंगले की कीमत अगर आंकी जाए तो 167करोड़ रुपए उन 6बंगलो की कीमत थी जो उस समय वहाँ से विस्थापित कर दिए गए। और जिन प्रकार की अनियमितताएं बरती गई, उसमें स्पष्ट पता चलता है, कैग की रिपोर्ट बता रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री -अरविंद केजरीवाल के अधिकारिक आवास, अधिकारिक वो कभी नहीं हुआ। उनको तो जैसे ही वो बनना शुरू हुआ उसके साथ दिल्ली की जनता की बद्दुआएं साथ -साथ चलने लगी। और जब बद्दुआ लगती है तो वो आदमी उस चीज़ का प्रयोग कभी नहीं कर पाता है। उस अधिकारिक फ्लैग स्टाफ रोड मे नवीनीकरण के मूल अनुमानित राशि जो है प्रथम बारी, अभी मंत्री जी ने बताया कि 8 करोड़ से ज्यादा की लिमिट नहीं होती, 7.91 करोड़ रुपए की थी और जो अंतिम वास्तविक खर्च हुआ है वो 33.66 करोड़ रुपए हुआ, यानी अनुमान से 342% ज्यादा। फाइनैंशल जगत में इससे ज्यादा वृद्धि कभी नहीं हुई होगी। इतना बड़ा डेविएशन कभी नहीं किया गया। और 18.88 करोड़ रुपए की उन वस्तुओं पर खर्च हुए जिसमें रिपोर्ट में सुपीरियर स्पेसिफिकेशन यानी की कलात्मक, एंटीक, पुरानी और सजावटी वस्तुओं के नाम पर उसको इंगित किया गया है। पेज वाइज इसका जब हम ब्यौरा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता उस समय जो एक छोटी सी दवाई के लिए, एक छोटे से इन्जेक्शन के लिए, 5 हजार का इन्जेक्शन जो है उस समय 50-50 हजार रुपए में लोग खरीद रहे थे। रोटी के लिए लोग रो रहे थे। एसओएस सर्विसेज चल रही थी। ब्रांडिंग, तार बंदी कर दी गई थी, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। ऐसे समय में कोई मुख्यमंत्री कैसे अपने आवास के निर्माण के लिए लेबर को बुला सकता हैं? ऐसे में कोई एक कैसे दवाई के बदले में अपनी सुपीरियर वस्तुओं के लिए कर सकता हैं? क्या ये खर्च सामान्य था? ये सामान्य नहीं था, ये असामान्य से भी असामान्यता और जिस गद्दी पर आज हमारी मुख्यमंत्री दीदी विराजित हैं, कल उन्होंने एक संवेदनशील बजट प्रस्तुत किया। मैं दीदी आपको बधाई दूंगा, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे कभी-कभी डर भी लगता है कि इस सीट पर कभी-कभी उनका प्रेत भी आ सकता है, मुझे डर लगता है लेकिन आपकी संवेदनशीलता, उनकी और गैर संवेदनशीलता के बीच में इतना बड़ा गैप है। आपने कल दिल्ली के हर वर्ग को छुआ और उन्होंने उस समय अपने गैर संवेदनशील रवैये से दिल्ली के हर वर्ग को नकार दिया था। जब दवाई की जरूरत

थी, जब पानी की जरूरत थी, जब रोटी की जरूरत थी, जब उस समय हॉस्पिटल्स की जरूरत थी तब वो अपना घर बनवा रहे थे।

घर के भीतर के विस्तृत आंकड़े अगर हम देखते हैं तो मंत्री महोदय जी ने आइटम में दिया लेकिन 40 लाख रुपए की किचन कैबिनेट। उस किचन कैबिनेट में क्या रखा जाएगा, ये सामान बाद का है। टीवी का कंसोल, उसकी लागत 20 से 21 लाख रुपए है और यह एक साधारण दीवार या टीवी स्टैंड से कहीं ज्यादा है। 88 इंच का जो टीवी उन्होंने कहा 28- 29 लाख रुपए का, 10 सोनी के टीवी लगाए गए। 43 लाख रुपए के अलग से टीवी थे।

सिल्क का कारपेट, ऐसा तो सुना था की कारपेट पानीपत में मिलता है, कारपेट वाराणसी में मिलता है, अच्छा मिलता है। कुछ -कुछ लोग ईरान के कारपेट की बात करते हैं, लेकिन सिल्क का कारपेट और फर्नीचर पहली बारी सुना, यानी की उसकी जो गद्दियां थी उसको सिल्क का बनाया गया जी।

बैड और बाथरूम पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ थी। हालांकि ये सदन है, मैं इसकी गरिमा का ध्यान रखता हूँ, मर्यादा का ध्यान रखता हूँ। लेकिन बताया गया, मैं वियतनाम गया एक दौरे पर, मैंने वहाँ पर एक पत्थर की दुकान में पूछा। तो भई यहाँ पे ये जो टॉयलेट सीट पड़ी है, किस प्रकार की है तो उन्होंने बताया की ये 2 लाख की, ये 3 लाख की है। तो मुझे लगा की ये तो वही है जो शीश महल में लगी हुई है। मैं बाद में ही गया था। तो वहाँ उन्होंने बताया कि इसमें से गर्म और ठंडा पानी निकलता है यानी की कंट्रोल टेम्परेचर से ये चलती है। मान्यवर, दिल्ली की एक हजार झुग्गी बस्तियों में लोग आज शौचालय के बिना रह रहे हैं। ये तो भला हो मुख्यमंत्री जी का और आशीष सूद जी का जिन्होंने पिछले साल दिल्ली की झुग्गियों के सभी शौचालयों के पुनर्निर्माण की बात की है, नहीं तो पिछले 10 साल में दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को कभी भी व्यवस्थित शौचालय नसीब नहीं हुआ। और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में 8 लाख रुपए की एक कंट्रोल्ड एटमोस्फीयर वाटर की शीट लगाता है, जिसपर गोल्डन प्लेटेड भी कहा गया। जो कर्टन लगाए गए, जो पर्दे लगाए गए, उसकी कीमत भी, जिन फ्लैटों का दीदी ने अवलोकन किया भलस्वा में, हमारी कॉन्स्टिट्यून्सी के बिलकुल नजदीक पड़ता है, दीपक जी की कॉन्स्टिट्यून्सी में, उस फ्लैट की कीमत और उस एक पर्दे की कीमत लगभग बराबर है, यानी की एक पर्दे के माध्यम से अगर उस पर्दे की कीमत को किसी फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया जाता तो एक क्लासरूम बन जाता और वो भी घोटाले वाला क्लासरूम भी बन सकता था जितने पैसे उन्होंने खर्चे, अगर नॉर्मल अगर दे तो कई फ्लैट बन सकते थे। डॉक्टर पंकज सिंह यहाँ पर बैठे हैं।

(समय की घंटी)

श्री राज कुमार भाटिया :पंकज जी जितनी दवाइयां आप लोगों को दे रहे हैं अगर उस फ्लैट की उसकी पूरी कीमत की दवाइयां दी जाती, सर अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है जी सर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): नहीं-नहीं, समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो बजट पे भी चर्चा होनी है।

श्री राज कुमार भाटिया :मैं जरूर रखूँगा जी। उसके गार्डन की बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अभी वो पूरा नहीं हुआ था। इसके साथ जो बन रहा था उसपे गार्डन बनाया, अगर गार्डन के नीचे एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई थी जी। ये वही लोग हैं जो इस प्रतिष्ठित विधानसभा में फांसी घर की बात करते थे, लेकिन अपने घर के नीचे जो अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया क्योंकि ये बिना नक्शे के बन रहा था। कभी इसकी अप्रूवल नहीं ली गई और पांच बारी इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको बदला गया, पांच बारी और कभी भी फाइनैंशल और अडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स नहीं लिए गए। जिन एजेंसियों को काम पे बुलाया गया था वो पांच एजेंसी हैं, उसमें से केवल एक एजेंसी ऐसी थी जो उस काम को कर सकती थी लेकिन उन पांचों को बुलाके रेस्ट्रिक्टेड बिडिंग, रेस्ट्रिक्टिंग टेंडरिंग का एक नाम दिया गया, ये टर्म इसमें स्पष्ट लिखी हुई है कि टेंडर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, टेंडर की कोई जरूरत नहीं है। जो सामान कोई ला रहा है,.. बिलकुल इसके साथ-साथ ये धोखाधड़ी है। असल में जब परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया फाइनैंशल अनियमितताएं करता हैं तो ये धोखाधड़ी है क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि किसी भी प्रकार से किसी भी नियम को ना तोड़े। प्रारंभिक अनुमान जो था 7 करोड़ 91 लाख का था और बाद में जो लागत वृद्धि हुई 25.75 की वृद्धि हुई है इसमें। ये सब चीजें ध्यान रखने की है और अनेक ऐसी वस्तुएं, इसमें पूरे पेज वाइज जो क्रम दिया हुआ है, मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूँगा आपकी जो कमिटीस जिस पर संज्ञान लेंगी कैग पे सदन के माध्यम से। ये सामान्य मामला नहीं है। इसके साथ-साथ उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, जो उस समय काल के गर्त में समा गए। इस रुपए की एवज में जितनी मृत्यु हुई हैं, जीतने का इलाज हो सकता था, जीतने की जान बचाई जा सकती थी, उन सब की हत्या का मुकदमा भी केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर चलना चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है। दोष लगा है, उनको श्राप लगा है दिल्ली का। ऐसे समय में जब वो दवाई देने की जरूरत थी, जब इलाज देने की जरूरत थी, जब खाना देने की जरूरत, तब उनको ये श्राप लगा। उन्होंने जनता का श्राप लिया और आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, होते तो वो भी बहुत आराम से सुनते कि उनके साथ क्या हुआ है जी। और मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूँगा कि इस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये मात्र एक भवन नहीं है और उस भवन के बारे में आप क्या सोचेंगे

मुझे नहीं मालूम है। लेकिन दिल्ली की झुग्गी की जनता को एक -एक बारी उस भवन का अवलोकन जरूर करवाना चाहिए,

(समय की घंटी)

श्री राज कुमार भाटिया: उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ था। उनको पता चलना चाहिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, सड़क की सफाई ये सब उस शीश महल की भेंट चढ़ गए थे। धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): धन्यवाद। माननीय सदस्य -श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट पांच है और पेज नंबर 122 पर शीश महल के बारे में इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है। ये रिपोर्ट सिर्फ नवीनीकरण और भव्यता पे खर्च का मुद्दा नहीं है, अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री -अरविंद केजरीवाल की कट्टर बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेशर्मी और संवेदनहीनता का जीता जागता नमूना है माननीय अध्यक्ष जी। इस सीएजी की रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस अपने निवास को लेकर उन्होंने जिस तरीके से इसकी नवीनीकरण के ऊपर काम किया। शुरुआत की 7 करोड़ 90 लाख से, फिर 8 करोड़ 62 लाख का एक टेंडर हुआ और ये बढ़कर 33 करोड़ 66 लाख तक पहुँच गया। चार गुना से भी ज्यादा और इस टेंडर की प्रक्रिया रेस्ट्रिक्टेड टेंडर किए गए। पांच लोगों को क्वालीफाई किया और बाद में सिर्फ एक ही को क्वालीफाई किया कि यही पूरा कर सकता है और उसके बाद उसको एक एक करके एडीशनल चार टेंडर दे दिए गए। सभी नियमों को धत्ता बताते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी को समझते थे की मैं तो राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और जिंदगी भर मुझे यही रहना है। 1397 स्क्वायर मीटर के निर्माण को प्रपोज किया और 1905 स्क्वायर मीटर का निर्माण हुआ। 36 परसेंट बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी परमीशन के माननीय मुख्यमंत्री जी और लक्जरी आइटम। अगर उसमें अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरी लिस्ट बताई है कि कैसे एक आदमी जो की 100 रुपये की शर्ट, 200 रुपये की पैंट और 5 रुपये का रेनॉल्ड का पैन पहन कर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाकर आम आदमी का चोला पहन कर जो आया और उसकी आपने लिस्ट देखी के करोड़ों रुपए के पर्दे, जिम उपकरण, टीवी और सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्ष जी, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट शीट अभी भाटिया जी बता रहे थे। वो 10 लाख रुपये की लवली जी 10 लाख रुपये की गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट शीट मैं कई बार, कई बार माननीय अध्यक्ष जी सिविल लाइन जाता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे, मैंने पूछा की ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट शीट 10 लाख रुपये की क्या खास बात है क्योंकि अमीर लोग लगाते होंगे। उन्होंने कहा, गोयल साहब सर्दी में कभी-कभी टॉयलेट जाते हो आप, मैंने कहा जाता तो

हूँ। तो सर्दी में जब टॉयलेट में बैठते हो तो ठंड लगती है। मैंने कहा ठंड लगती है। कह रहा भाई साहब इसके अंदर केजरीवाल ने ऐसा सिस्टम लगाया है कि जब आप बैठोगे टॉयलेट पर तो ठंड नहीं लगेंगी मामला बड़ा जबरदस्त रहेगा। हालत देखो आप, कैसा मुख्यमंत्री है ये, कट्टर बेईमान, कट्टर निर्दयी के सिर्फ टॉयलेट के ऊपर बैठने के वक्त उस एक सेकंड ठंड ना लगे 10 लाख रुपये उसने खर्च कर दिए।

(अपराह्न 2.51 बजे श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री अजय महावर: भाई साहब उसमें मसाज भी थी।

श्री अशोक गोयल: हाँ, अजय महावर जी कह रहे हैं मसाज भी थी और और भी कई चीजें थीं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार दौरा कराएंगे तो हम भी टैस्ट करके आएँगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम उस पीरियड को देखें कैसा पीरियड था वो कोरोना का काल था, दहशत का मंजर था, लोग मर रहे थे, हाहाकार हो रहा था और लोग बदहवास हालत में थे और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दो चीजों में मस्त थे एक तो अपना शीशमहल और दूसरा शराब पॉलिसी। उन्होंने इस कोरोना काल के अंदर ये बताता है कि आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया का चरित्र क्या था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सेवा ही पार्टी का काम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी इंतजाम कर रहे थे की ऑक्सीजन मिल जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंतजाम कर रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर बेड की सीट बढ़ जाए। वो इंतजाम कर रहे थे की remdesivir के इन्जेक्शन मिल जाएं। वो इंतजाम कर रहे थे की किसी तरह से लोगों को जो जरूरत की दवाइयां हैं वो टाइम पर मिल जाए और दूसरी तरफ ये जो कट्टर बेईमान लोग थे, कट्टर संवेदनहीन लोग थे वो क्या कर रहे थे

(समय की घंटी)

श्री अशोक गोयल: कि घर का महल कैसा बने मेरा। लोगों को एक्साइज पॉलिसी ऐसी बना दें की करोड़ों का घोटाला हो जाए। इस चीज़ में लगे थे माननीय अध्यक्ष जी और दिल्ली के लोगों ने, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। दिल्ली के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, इनके हालात को समझा और लोगों ने सोचा था कि जब इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, बुरी तरह से हराया है शायद सुधर गए होंगे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आज पंजाब में शीशमहल बना रहे हैं। पंजाब को भी खोखला कर रहे हैं, पंजाब की हालत भी दिल्ली के जैसे ही कर दी है। आने वाले दिनों में पंजाब के लोग दिल्ली से भी बुरा हाल करके भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस सीएजी की रिपोर्ट पर जो सदन के सामने रखी है इनके ऊपर

उचित कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, गजेंद्र यादव जी।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। कैग रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं। शीशमहल का भ्रष्टाचार, शराब की दुकानें और अय्याशी के लिए इतने ज्यादा सुविधाएं शीशमहल में रखी गईं तो मुझे ध्यान आया की भ्रष्टाचार और अय्याशी में डूबे रहने वाले बहुत सारे शासक, वो बाबर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो या अवध के नवाब वाजिद अली शाह हो उनके बाद अगर भ्रष्टाचार और अय्याशी में और सुविधाभोगी में अगर किसी और का नाम भविष्य में आएगा तो वो कोई और नहीं वो खुद को दिल्ली का मालिक कहने वाले और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का नाम इस सूची में शामिल होगा। हालांकि मैं ये साथ के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का शासन रहा उसमें भी कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टाचार हमने देखा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों ही चोर-चोर मौसेरे भाई हैं जब भी शासन में आए तो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ जो पैसा जनता टैक्स के रूप में सरकार को देती है वो भ्रष्टाचार में लगाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, साज सज्जा के नाम पर 18, लगभग 19 करोड़ रुपये, ठेकेदार का चयन मनमाने तरीके से करना ये सब बातें कैग रिपोर्ट में प्रदर्शित करते हैं कि जमकर भ्रष्टाचार और अपने प्रकार से एक नए तरह का भ्रष्टाचार। जो वो कहते थे कि हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं, वो राजनीति करने नहीं आए थे, वो नवीन तरीके से नए-नए तरीकों से भ्रष्टाचार करने आए थे। आज दिल्ली की जनता अपने मुख से ये कहती है और दिल्ली की जनता ही नहीं यहाँ जब नाश्ता और खाना खाने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर इनके भी साथी दबे मुंह ये कहते हैं की हम हो सकता है सरकार में आ जाते लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार था, घमंड था, उसका जो अय्याशियां थी, उनकी वजह से हम लोग डूब गए और सरकार में नहीं आए। वो गलत बात नहीं कहते, वो सही बात कहते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता भी ये बात कहती है कि जो बच्चों की कसम खा कर उनके सर पे हाथ रख कर ईमानदारी की राजनीति के नाम पर सरकार में आए थे वो सरकार में आते ही मालिक बन बैठे और उन्होंने भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके निकाले। उपराज्यपाल जी से छिपाकर सारा काम किया गया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी रेखा दीदी वे हरित दिल्ली की बात करते हैं और प्रवेश वर्मा जी ने नक्शा दिखाया की उन्होंने सारी हरियाली वहाँ से तहस-नहस कर दी, सारे पेड़ो को काट दिया। ये जो पेड़ काटे वो केवल और केवल पेड़ नहीं काटे थे उस पेड़ पर जो रहने वाले पक्षी थे उनके भी घोंसलों को उन्होंने बर्बाद किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये तो अच्छा हुआ की वो चुनाव हार गए और बाहर हो गए। पंजाब में वहाँ की सरकार में खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और खूब स्वस्थ हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर वो इस बार

5 साल के लिए सरकार में आ जाते तो यकीनी तौर पर अगर उनको 5 साल में सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए रहते हुए कोई गडबड हो जाती तो वो अपना शरीर भी उसी शीशमहल में दफन करवा लेते और वहाँ पर अपनी मजार बना लेते क्योंकि विशेष वर्ग के लोगों के साथ उनका कुछ ज्यादा ही प्रेम है। उस शीशमहल को अपनी अंतिम कब्रगाह भी वो बना लेते। आदरणीय अध्यक्ष जी, 33 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2020 में 7.91 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया था और इस कार्य को इससे अधिक, 13 फीसदी अधिक यानि की 8.62 करोड़ में आवंटित किया गया बाद में इस कार्य को इससे 342.31 फीसदी अधिक यानि 33.66 करोड़ रूपये खर्च करके इसको पूरा किया गया। केजरीवाल सरकार ने कोई ध्यान नहीं रखा। रिपोर्ट के अनुसार ऑडिटर को यह भी नहीं बताया गया कि पीडब्ल्यूडी ने किस आधार पर इस काम के लिये तीन कन्स्नटेन्सी एजेंसियों का चयन किया और कन्सन्टेन्सी एजेंसी को अधिक पैसे भी दिये गये। ठेकेदारों को काम आवंटित करते समय उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधन और अनुभवों का भी ध्यान नहीं रखा गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़े-बड़े एलईडी टेलीविजन की बात चल रही है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे घर में आए दिन परिवार के लोग ये कहते हैं कि कभी तो मिलकर कोई एक टीवी का सीरियल या कोई दस-पांच मिनट देख लिया करो, बैठ के। हमारे घर में भी टीवी लगे हुए हैं, लेकिन जनता की सेवा के कारण समय नहीं मिल पाता लेकिन वो कितने ज्यादा फ्री थे कि पूरे के पूरी दिल्ली कोविड के कालग्रास बन रही थी और वो अपने महल में बड़े-बड़े टेलीविजन यानि के अपने शीश महल से बाहर नहीं निकलना पड़े उसके लिए एसी उसके लिए अपने और सुख-सुविधा के लिए वो लगातार चोरी कर रहे थे और ये जो चोरी का पैसा था वो कोई उनका अपना नहीं था। दिल्ली की जो जनता है दिल्ली के हर गरीब व्यक्ति का भी पैसा, हर अमीर व्यक्ति का पैसा, हर मध्यम वर्गीय का पैसा और हर सरकारी कर्मचारी का पैसा वो बजट के तौर पर सरकार के पास था जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में खर्च किया। मेरा समय पूरा हुआ, धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्षः गजेन्द्र दराल।

श्री गजेन्द्र दरालः धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शीशमहल के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट रखी और उसके अंदर किस तरीके से उन भ्रष्टाचारियों ने जो दिल्ली की जनता के साथ एक आम आदमी का रूप दिखाकर और किस तरीके से वो खास आदमी बने, ये दिल्ली की जनता ने देखा। जो व्यक्ति अपने आप को जनता का सेवक दिल्ली के विकास की बात करता था वो व्यक्ति कब कितना खास हो गया ये दिल्ली की जनता ने भली- भांति देखा। जो व्यक्ति स्वराज की बात करता था, जल लोकपाल की बात करता था और किस तरीके से फिर उसने दिल्ली की उस जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे को अपने

ऐशो आराम के लिए और उसके साथ आज अगर हमारे सामने उनके सहयोगी बैठे होते क्योंकि वो भी उस भ्रष्टाचार में बड़ी मात्रा में लिप्त हैं, आज उनको शर्म आती है हमारे सामने बैठते हुए। हम भले ही नए हैं लेकिन हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, मोदी जी के सेवा परमो धर्म को मानने वाले और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। उन लोगों ने दिल्ली को उस समय ऐसा ठगा, जब पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जब दिल्ली की जनता का सेवक बनकर उनको दिल्ली की जनता के बीच में रहना था लेकिन उस समय दुर्भाग्य की बात कि वो अपने ऐशो आराम के लिए एक बहुत ही बड़ा शीश महल, एक ऐसा शीश महल, जिसकी अभी सूचीबद्ध तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी ने एक-एक चीज़ का वैल्यू यहाँ सबके सामने रखी और बड़े दुःख की बात होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिजली के खंभों पर चढ़ कर एक बहुत लंबी सी शर्ट पहनकर पैंट पहन कर कभी बिजली की तार को जोड़ता है, कभी काटता है, जो लोगों का एक सच्चा सिपाही बनकर अपने आप को दिखाता है लेकिन जब उसका उद्देश्य पूरा होता है तो वो जनता को बताता है के मैंने आपको ठगा है, आपकी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, मैं दिल्ली का मुखिया और सरदार बनने के लिए राजनीति में आया हूँ मैं दिल्ली की सेवा करने के लिए और दिल्ली का विकास करने के लिए नहीं आया और ये दिल्ली की जनता ने देखा कि किस तरीके से 11 साल तक उसके एक-एक चुने हुए प्रतिनिधि ने या उसके विधायक साथी ने किस तरीके से इस दिल्ली के टैक्स के पैसे को अपनी तिजोरियों के अंदर भरकर सिर्फ अपनी तिजोरियों के वजन को बढ़ाया और दिल्ली को एक ऐसे भयावह स्थिति में छोड़ दिया कि दिल्ली की लोगों की सोच विकास को तो छोड़ो, सिर्फ गटर के पानी और सीवरों तक आकर सीमित हो गई। ये दुर्भाग्य की बात थी हम सब के लिए। अभी, कई बार ये लोग कह देते हैं कि मोदी जी तो चाय पे चर्चा करते हैं तो चाय की चर्चा खुले में होती है और अच्छा भी लगता है लेकिन इन लोगों की चर्चा कहाँ हुई, इन लोगों की हुई थाली पे चर्चा और वो थाली बनती थी बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स के अंदर जहाँ एक-एक थाली की कीमत होती थी कि इतने करोड़ रुपए और आपकी टिकट फाइनल। ये दिखाते हैं इन लोगों की क्षमता इन लोगों की सोच कि हमें दिल्ली के अंदर किस तरीके से आम लोगों के बीच में रहकर उनके विश्वास को जीतना है और फिर उनके साथ ठगा हुआ और हर वो काम करना है जिससे उनको लगे की हमने तो अपने वोट को एक अंधकारमय भविष्य को दे दिया। दिल्ली के अंदर पूरे 11 साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी सोच बना दी। हर किसी को अपने आप में अपने ऊपर पछतावा होने लगा की हमने किस व्यक्ति को अपने लिए चुना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने विकास के मॉडल को छोड़कर और भ्रष्टाचार के मॉडल को पूरे विश्व के अंदर पेश किया और अपने आप को पूरे विश्व में सबसे झूठा और सबसे भ्रष्टाचारी भी साबित करके दिखाया। जिस व्यक्ति ने स्वराज की बात की, वो कब शराब की नई पॉलिसी ले आया किसी को पता ही नहीं चला। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम सब ने देखा की जब दिल्ली उस कोरोना

जैसी वैश्विक महामारी से तड़प रही थी, तब इनके साथी और ये लोग कहाँ थे? ये अपने व्यापार में लिप्त थे और दिल्ली में इंसानियत के नाते हर वो व्यक्ति जिसको प्रत्येक व्यक्ति से प्यार था चाहे वो भाजपा के संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे जिसके अंदर इंसानियत हो, अपने पड़ोसी की या अपने साथी की मदद करने के लिए लगा हुआ था। हमारे एक-एक साथी, एक-एक व्यक्ति हर उस गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए उसकी मदद करने के लिए बगैर उस कोरोना की किसी भी तरह से डरने के लिए तैयार थे, लेकिन ये लोग हमें रोड़ों पर कहीं नजर नहीं आये। ये लोग व्यस्त थे तो अपनी तिजोरियों को भरने के लिए। दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य का समय था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न ने और दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के संगठन ने और मैं पूरे दिल्लीवासियों को धन्यवाद करता हूँ अपने हृदय की गहराईयों से कि उन्होंने दिल्ली के विकास के मॉडल को चुना, उन्होंने दिल्ली के बदलाव को चुना और हमारे बीच में आज एक ऐसे हमारी बड़ी बहन माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिन्होंने इस बार के बजट में पूरी दिल्ली के प्रत्येक समाज को, प्रत्येक वर्ग को समाहित करके इस दिल्ली को नया मॉडल का विकास देने का जो निश्चय लिया। मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द जय भारत।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अनिल गोयल जी।

डॉ अनिल गोयल: धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सीएजी की प्रतिवेदन संख्या-5 पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। और इसकी विषय सूची भी अगर आप देखें तो अत्यंत गंभीर है जो राजस्व प्राप्तिओं के साथ आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र की खामियों को उजागर करती हैं। विशेष रूप से मैं चार विभागों की थोड़ा शॉर्ट में बात करना चाहता हूँ स्वास्थ्य परिवार कल्याण, सूचना एवं जनसंचार, लोक निर्माण विभाग जिसमें शीश महल की बात बहुत देर से हो रही है और समाज कल्याण विभाग में जो सत्य तथ्य रखे गए हैं उसकी बात करना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड क्लास मॉडल के नाम पर ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करना चाहता हूँ। ये उपलब्ध कराई ही प्राइमरी हेल्थकेयर का ऑडिट है और ऑडिट या जांचने के लिए था कि क्या योजनाएं ठीक बनाई गईं और क्या योजनायें ठीक ढंग से लागू हुईं। किसी भी प्रदेश के लिए एक देश के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर डोर स्टेप सर्विसेज होती है। लेकिन यहाँ 35 करोड़ की प्लानिंग हुई लेकिन लगे कितने 9 करोड़ सिर्फ 28% ही खर्च किए गए और मोहल्ला क्लिनिक जो वर्ल्ड क्लास का आ गया था, ढिंढोरा पीटा गया था वहाँ पर पैसा तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं 1 हजार क्लिनिक बनाने का मार्च 2017 में कहा गया था, वो 2023 तक सिर्फ 523 बने और वो भी क्या बने वो भी जरूर बताना चाहता हूँ हमारी मुख्यमंत्री जी ने 1 साल में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं और इस वर्ष 750 और बनाने का घोषणा की है। हमको उम्मीद है कि 1000 और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जहाँ

प्राइमरी हेल्थ केयर सही क्या होती है प्राइमरी हेल्थकेयर वो मिलने वाली है जहाँ पर दवाइयां भी होंगी, जांच भी होगी, प्रिवेंटिव हैल्थ भी होगी, योगा का सिस्टम भी होगा। इस तरह का प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और इसमें डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे। ये विषय है यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक थी वहाँ 218 क्लिनिकों में आप सोचिए 15 दिन से 23 महीने तक क्लिनिक बंद रखे और इन क्लिनिक में आप सोचिए थर्मामीटर नहीं बीपी एपरेटर्स नहीं, ग्लूकोमीटर नहीं एक्स रे व्यूअर एक्सरे देखने के बुनियादी सामान नहीं, क्लिनिक में जो दवाइयां थी वो भंडारण की जगह नहीं है वो टॉयलेट ब्लॉक्स में पाई गईं। पानी पीने का शौचालय का तो भूल ही जाईये। 31 क्लिनिक और 70% से ज्यादा मरीज 10 सेकंड में, मैं एक डॉक्टर हूं मैं जानता हूँ एक मरीज को देखने के लिए 5 मिनट कम से कम लगने चाहिए, अगर ये 10 सेकंड से 1 मिनट के भीतर देख लिया गया तो ये संभव ही नहीं है इसका मतलब है सब फर्जी प्रविष्टियां की गईं, फर्जी एंट्री की गईं और उसका कारण सिर्फ एक था उनकी फॉल्टी प्लानिंग थी जिसमें 40 रूपये प्रति मरीज को देने का एक डॉक्टर को कहा गया था वो सिर्फ नंबर उनको लिस्ट में बनाने थे कि इतने मरीज हमने देखें। एक-एक मोबाइल पर 20-20 लोगों के नाम दर्ज थे। नकली दवाइयों का खेल भी इसमें देखा गया और इस सब सिस्टम को लापरवाही में निरीक्षण भी करना चाहिए। डीजीएचएस सीडीएमओ की जिम्मेदारी है इसको निरीक्षण करना। 11,191 अनिवार्य निरीक्षणों के बदले सिर्फ 175 निरीक्षण किए गए और इसके अलावा मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की भारी कमी पाई गईं, दवाइयां तो इसमें भी ऐसा ही हुआ की थी ही नहीं। 17 लाख स्कूली बच्चों को देखना था मोबाइल, स्कूल क्लिनिक के माध्यम से उसमें देखे गए कितने? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बच्चे। जी टी बी अस्पताल की मैं बात करूँ अब तो जी टी बी अस्पताल में 70.51 लाख रूपये अतिरिक्त भुगतान इसीलिए कर दिए गए कि वेंडर को टाइमली उसको वेंडर नहीं कर पाए। सेकेंडरी केयर की जब भी हम बात करते हैं तो सेकेंडरी केयर में पॉली क्लिनिक होती है और आयुष की भी बात करते हैं तो सरकारी अस्पतालों का भार कम करने के लिए की जाती है। ऐसी 150 पॉली क्लिनिक में सिर्फ 11 साल में 28 पॉली क्लिनिक बनी और स्टाफ यहाँ 23% से 100% तक कम था। दवाइयों के स्टोर, तहखाने और शौचालय में गंदगी में दवाइयां पाई गई। आयुष का यूनानी का तो और इससे ज्यादा बुरा हाल था। दिल्ली को आयुष्मान स्कीम से वंचित रखा गया। जिस प्रकार से आज दिल्ली में आयुष्मान भारत से लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के हार्ट के, घुटने कितने लोगों के बदले जा रहे हैं, ये आयुष्मान के कारण जो विशेष रूप से इसमें अब ट्रांसजेंडर भी जोड़े गए हैं और इसके पहले करीब लाखों लोगों को उसमें जोड़ा गया है, और ये सब मैं तो चाहूंगा की इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अजय महावर जी ने जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मानव संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल इस सब की रिपोर्ट दिया है, इसको भी जरूर पब्लिक किया जाए। इसमें भी जो गड़बड़ियां है वो इससे भी और ज्यादा अजय महावर जी को

मैं धन्यवाद भी इसके लिए देना चाहता हूँ। दूसरा, जो विज्ञापन की राजनीति ये भी इस सीएजी ऑडिट में है अध्यक्ष जी, सूचना और प्रसारण निदेशालय में विज्ञापन और प्रचार पर किए गए व्यय में नियमितता थी ना प्रभावशीलता थी। 12 गुना वृद्धि 2018-19 के 46.9 करोड़ के खर्च को 12 गुना बढ़ा कर 2021-22 में 612 करोड़ कर दिया गया और इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ। सरकार केवल विज्ञापन की सरकार बन कर रह गई और विज्ञापन नीति में वित्तीय अनुशासन की भी धज्जियां उड़ा दी गई। 19 मामलों में तो विज्ञापन दिल्ली के बाहर कर दिए गए, जिसका दिल्ली की जनता के लाभ से कोई संबंध नहीं था और ये सब कौन कर रहे थे। चाहे सोशल मीडिया हो या लाइव स्ट्रीमिंग हो, ऐसी निजी एजेंसियां थी जिनकी मनमानी शर्तें थी और उनके काम की निगरानी का कोई तंत्र नहीं था। मतलब सरकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही थी। ये हम लोगों ने इस सीएजी की रिपोर्ट में भी पाया। शीश महल में मैं इससे ज्यादा जितना ईसीजी पूरा दिखाया हमारे माननीय मंत्री जी ने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ की इस जगह को एक कोविड शहीद स्थल घोषित करके एक प्लॉक वहाँ लगा दिया जाए कि ये स्थान वो है जब कोविड में लोग ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, कोविड में जब लोग मर रहे थे तो ये जगह बन रही थी, मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी तो आप सब ने देखा ही बिना टेंडर के कलात्मक सजावट और ये सब लेकिन एक जरूर योजना की बात करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, समाज कल्याण और लाड़ली योजना जहाँ अपने ऐशो-आराम के लिए करोड़ लुटाए गए वहाँ बुजुर्गों के लिए संवेदनहीनता दिखाई गई। भूमि होने के बावजूद 8 साल बीत जाने पर भी तीन वृद्धाश्रमों का निर्माण नहीं हो पाया। 2.92 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और दिल्ली के निराश्रित वृद्धों को सामाजिक समर्थन से वंचित रखा। पिछली सरकार ने अध्यक्ष जी, लाड़ली योजना के लाभार्थियों के पैसों को रोक कर रखा

(समय की घंटी)

डॉ अनिल गोयल: और हमारी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आते ही

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष : गोयल साहब समाप्त कीजिए, प्लीज़।

डॉ अनिल गोयल: लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से उनका हक दिलाया। अध्यक्ष जी, बस लास्ट कुछ इस सीएजी का एक एक पन्ना चीख चीख कर कह रहा है कि वर्ल्ड क्लास होने का जो दावा था वो कागजों में था, विज्ञापन में था, असलियत में भ्रष्टाचार, कुशासन और संसाधन देखना बर्बादी देखनी है तो ये सरकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपदा सरकार की कार्य गुजारी ये बताती है आज दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री जी इन कुकर्मों को समेटने और दिल्ली को सच्चे सुशासन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर वृद्धि, कल्याण,

लाड़ली योजना जैसी सुविधाओं से जोड़ने लगी है। हम दिल्ली में वो विकास और विकास के साथ ग्रीन और डेवलप्ड दिल्ली बनाने जा रही है। अध्यक्ष जी, इन सब भ्रष्टाचारों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि ये उपलब्धि पुस्तिका जरूर।

(समय की घंटी)

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः अनिल जी समाप्त कीजिए, दूसरे लोगों का भी नंबर आने दीजिए और भी मेंबर है।

डा .अनिल गोयल : दूसरे लोगों को जरूर दिखानी चाहिए। मैं पिछले 1 साल दिल्ली सरकार ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष : आपने बहुत अच्छी बात है कही, दूसरे मेंबर को भी मौका मिले। बहन पूनम शर्मा जी।

श्रीमती पूनम शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस सदन में सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, पहले भी आई थी और आज उस पे चर्चा हो रही है। शीश महल जिसका नाम ही इतना अल्टीमेट हो, शीश महल अपने आप में भी बहुत यूनिक नाम है और जब बात आती है केजरीवाल की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते थे कि मैं दिल्ली का राजा हूँ और मैं गरीबों का मसीहा हूँ। जब गरीब आदमी कोविड के समय में परेशान था मरने को तैयार थे सब लोग हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं थे उस टाइम पे वो भी बड़े बेचैन थे कि मैं कैसे अपना महल बनाऊं। यहाँ मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हम एक सीवर लाइन डालने के लिए छोटे छोटे कामों के लिए एस्टीमेट बनाना पड़ता है। उसके लिए भी महीना डेढ़ महीना निकल जाता है, मगर केजरीवाल सरकार में इतना बड़ा शीश महल बना दिया और एक दिन भी हम हमें नहीं पता चला कि कब उन्होंने एस्टीमेट बनवाया, कब वो फाइल कहाँ से कहां घूम के आई और दिन में जब कोविड के टाइम पे लेबर भी नहीं थी, सारी जगह मैं कहूँगी वर्कर भी नहीं थे और कहीं पे भी कोई भी बिल्डिंग का कोई काम नहीं चल रहा था। मगर केजरीवाल जी के घर का काम बखूबी चल रहा था, वो एक दिन भी नहीं रुका, क्यों नहीं रुका, आज वो जनता पूछना चाह रही है कि हमारी गाढ़ी कमाई जो हम टैक्सपेयी हैं, जो हमारे किसी भी चीज़ में हम लेके जाते हैं जीएसटी का हमारा टैक्स हमसे काटा जाता है तो क्या वो केजरीवाल के महल के लिए काटा जा रहा था या हमारे बच्चों के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए थी, हमें एक विद्यालय चाहिए था, हमें एक नई रोड चाहिए थी, हमें नए हॉस्पिटल चाहिए थे, नए हमें विश्वविद्यालय चाहिए थे। मगर नहीं, उसने देखा तो ये देखा कि मेरे महल के अंदर बढ़िया से बढ़िया पर्दे कैसे लग सकते हैं। बड़े से बड़ा टीवी मैं कहाँ से इसको परचेस करूँ, अपनी वाइफ के लिए मैं अच्छा से अच्छा किचन कैसे बना सकूँ और वो भी

किचन क्या मॉडयुलर किचन उसमें। अभी प्रवेश वर्मा जी ने बहुत लंबी लिस्ट निकाली उस लिस्ट के अंदर मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने चूल्हा कौन सा लगाया था। एक जो गृहणी होती है उसको तो चूल्हा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होता है कि उसकी गैस कौन सी लगाई गई थी, एलपीजी की लगाई थी, इंडियन की लगाई थी या तो या कहीं फौरन से उसने मंगवाई थी। मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन या कोई एलपीजी की गैस लगी होगी। वो भी कहीं ना कहीं जैसे वो पत्थर वियतनाम से आया था, ऐसे ही गैस भी कहीं दुबई से आई होगी या इजराइल से आई होगी गैस। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े शौक उनके हैं तो आप समझ सकते हो कि जब एक बच्चा अपनी शिक्षा की जो बुनियाद होती है उसके लिए तरसता है। कल एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, इसके अंदर जोड़ना चाहूंगी की कल जब हमारी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया तो वो भी उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेस करी, उसमें प्रेस कांफ्रेस में सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी ने क्या कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो साइकिल दे रही है और जो लैपटॉप दे रही है। साइकिल समाजवादी पार्टी का एक चुनावी सिंबल है तो वो उनको वहाँ पे चुनाव के प्रचार में भेजेंगी। आप लोगों का पता होना चाहिए आप लोग एक लोकतंत्र के जरिए इस सदन में बैठे। आपको पता होना चाहिए की मात्र 15-16 साल का बच्चा किसी चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो साइकिल उन छात्राओं को दे रही है वो उनके भविष्य के लिए दे रही है क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को आने जाने में उनको कोई साधन नहीं होता तो उन बच्चों की पढ़ाई पे उनके शिक्षा पे कोई असर ना पड़े तो उनको एक साइकिल मुहैया करवाई जाए तो उन्होंने उसका भी एक प्रोपगंडा बना दिया। क्योंकि उन लोगों की सोच ही ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है जो सामने टेबल पे बैठती है, आतिशी जी वो भी एक महिला है, उनके घर में भी बच्चे होंगे और मैं स्पेशल कहूँगी कोई ना कोई बेटी तो जरूर होगी। जो अपनी बेटियों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि उनकी कितनी छोटी मानसिकता है और लैपटॉप जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आजकल एआई का टाइम है तो बच्चों के स्कूलों में भी आजकल सारी जगह सारी स्मार्ट क्लासेज हो रही है। सब बच्चे आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सब स्मार्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनको सुविधा मिले, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई का स्रोत उनको मिलना चाहिए। मगर मैं आज कहना चाहती हूँ कि उन लोगों की बच्चों की शिक्षा से भी परहेज है कि हमारे दिल्ली के बच्चे कुछ पढ़ के कुछ कर गुजर ना जाए। कहीं वो अच्छी किसी पोस्ट पे ना बैठ जाए। उनका तो ये है कि जो हम है हम ही रहने वाले हैं। केजरीवाल हमारा राजा था तो वो ही राजा रहेगा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरी दादी तो एक ही बात कहती हैं। जब अपनी जी में लग गए तो हमारा, दूसरे का लग गया तो भीत में। जब आज उनको ये बात पता चल रही है कि जब वो कोविड में जो भाई और जो परिवार गए थे

उनका दुख नहीं था उनको। उनको किसी का भी दुख नहीं था कि घरों में पानी है, ऑक्सीजन है, घरों में खाना जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इसकी भी किसी ने चिंता करी तो दिल्ली हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। कैसे वो दवाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे कि एक एक घर के अंदर कोविड शील्ड का इन्जेक्शन लग जाए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनके घर में राशन कैसे पहुंचाया जाए और सेवा बस्ती के अंदर कैसे उनको भोजन दिया जाए, कैसे पानी पहुंचाया जाए? कैसे उनके हाथों में दवाइयां पहुँच जाएं और एक एक परिवार को उन्होंने अपना अभिभावक के रूप में देखा कि पूरा भारतवर्ष मेरा एक परिवार है और मैं अपने परिवार को कैसे बचा लूँ? मगर केजरीवाल जी तो उस टाइम ये सोच रहे थे कि आज मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफा कौन सा लगाऊं, 50 लाख का लगाऊं कि 1 करोड का लगाऊं? वो तो इसी गुफ्तगू में थे। उनको तो समझ में नहीं आ रही थी कि मैं 40 लाख की टॉयलेट शीट लगाऊं कि 80 लाख की लगाऊं? आज मैं भाई साहब आपको ये समझ में आना चाहिए कि रोटी तो दो ही खानी थी। दाल और रोटी खानी होती है। बुराई का अंत तो हमेशा बुराई ही होता है और अगर आज वो सत्ता में होते तो उनको पता चलता कि आज आम पब्लिक कितनी परेशान है क्योंकि मैं एक एमसीडी से चुन के आई हुई पहले पार्षद थी। हमारे एमसीडी के अंदर साफ सफाई होती थी। मगर इन्होंने 10-12 साल में दिल्ली को इतना बेहाल कर दिया कि आज लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ उनकी छोटी सी सोच रह गई है कि हमारी नालियां साफ हो जाएं, हमारी गलियां साफ हो जाएं और हमारे बच्चों का एक अच्छी सी शिक्षा मिल जाए। मगर उन लोगों ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। सिर्फ सोचा तो अपनी जेबे भरने का सोचा। अपने महल और अपनी कोठियां बनाने का सोचा तो ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और बात करूँ कि आतिशी जो बोलती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती हैं। एक महिला होने के नाते वो कभी भी छात्रों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती हैं कभी और क्लासरूम घोटाले की भी बात आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि हमारा शिक्षा मॉडल। शिक्षा मॉडल 0% जीरो। क्योंकि आप किसी भी स्कूल में चले जाओ। दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रही हूँ। 1 साल पहले जब हम स्कूलों में जाते थे, सिर्फ लीपापोती कर रखी थी और जो कमरा पांच छ लाख रूपए में बनने वाला तो उन्होंने उसमें 25 से 40 लाख रूपए का अपना खर्चा दिखा दिया गया और 365 करोड से भी बढ़कर उन्होंने अपना पूरा बिल दिखाया। आज भी उन स्कूलों के अंदर कोई क्लासरूम नहीं है। जो शौचालय थे उनको भी उन्होंने शौचालय को कमरों के रूप में अपना आंकड़ा दिखा दिया। मतलब कहीं तो भ्रष्टाचार रोकना चाहिए था उनको मगर कभी उन्होंने भ्रष्टाचार सिर्फ वो भ्रष्टाचार ठीक करने के लिए आए थे और क्योंकि भ्रष्टाचारी ही पार्टी थी, उनके मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचारी थे और उनके मंत्री भी और उनके सभी

सदस्य में अध्यक्ष जी महोदय जी और अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि

(समय की घंटी)

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: सम अप कीजिए, पूनम जी।

श्रीमती पूनम शर्मा : ऐसे अधिकारियों पे और ऐसे जो मुख्यमंत्री थे उन पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल: धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी । आज मैं आपके समक्ष सीएजी जो कि कई विषयों पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी उसमें आप के माध्यम से बताना चाहता हूँ की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल मुख्यमंत्री जी के माध्यम से टैक्स के सिस्टम में किस तरह से चोरी की गई। पूरी तरह से जीएसटी सिस्टम को फैल कर दिया गया। जीएसटी सिस्टम जो कि सरकार जीएसटी के बेस पर ही चलती है, ऐसे मामले 308 मामलों में जांच नहीं हुई और आपको बताएं 308 मामलों में जो है 1702करोड रूपए की गड़बड़ी पाई गई, जो 85 मामले इसमें विशेष रूप से थे और जीएसटी यदि सरकार कलैक्ट करने में असफल होती है तो हम समझ सकते हैं की इतनी सोशल इकोनॉमिक जो हमारे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हमारे नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्थाएँ नहीं दे पाते हैं हम तो ये हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि कहते हैं वो पहले स्वयं भी आइआरएस ऑफिसर रहे हैं और वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रहे उनको तो अच्छे से समझना चाहिए जीएसटी के मैटर को, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। क्योंकि जीएसटी एक बैकबोन होती है, एक टैक्स जो है बैकबोन होती है सरकार का और टैक्स सरकार जो है टैक्स के माध्यम से ही चलती है, विकास कार्य कर पाती है और इसी तरह से टैक्स का सही समय पर भुगतान नहीं हुआ। आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें भी गड़बड़ी मिली जो की सीएजी ने अच्छे से बताया ब्याज नहीं दिया गया है। जिन्होंने टैक्स लेट दिया उनसे ब्याज कलेक्ट नहीं किया गया। रिटर्न की सही जांच नहीं हुई। यानी की पूरी जीएसटी कंट्रोल करने में हमारे आइआरएस डिप्टी कमिश्नर एक्स कमीशनर जो की चीफ मिनिस्टर भी थे, वो सब फैल हुए थे। सिर्फ और सिर्फ कहने के वायदे उन्होंने पूरे करे। इस तरह से अनेकों अनेक विभाग में टैक्स के जो कलेक्शन करना चाहिए था 1902 करोड रूपए का वो भी टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाए। तीसरा हम देखें तो लगभग अन्य जो विभाग हैं उसके अंदर ऑडिट जो है उसमें। 10,000 से ज्यादा मामलों में सरकार के अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है आपके एक मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ अन्य विषयों पर भी

सीएजी रिपोर्ट है और इसमें 124 मामलों में रिकॉर्ड नहीं दिए गए और 100% रिकॉर्ड छिपाये गए। मतलब आप ये देखिये सीएजी के अधिकारी अधिकारियों के विषय में कह रहे हैं 100%, अधिकारी जैसा उनका बॉस होता है फिर अधिकारी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बॉस ने कहीं ना कहीं इनको कहा होगा कि इस तरह की समस्या है इस तरह से यदि देखा जाए। अभी हमारे डॉक्टर अनिल गोयल जी ने बताया 1000 मोहल्ला क्लीनिक जो है 523 मोहल्ला क्लिनिक साहब बन पाए और हमारी दीदी जी ने मुख्यमंत्री महोदय ने 370 और इस वर्ष 570 से ज्यादा आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उसमें व्यवस्था उसमें आप ये देखिये मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं थी। साथ में अपने जो औषधि हैं, यूनानी हैं या आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो दवाइयां तक उपलब्ध नहीं थीं। कहीं तो शौचालय भी नहीं थे, कहीं डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर्स के समय भी बहुत कम था और साथ में देखने का जो समय पेशेंट को देखने का जो समय होता था वो भी बहुत कम था और कई केसों में से ऐसा आया की नंबर्स जो मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर एक बार रिपीट होकर उन पर देखे गए और उसकी पेमेंट क्योंकि डॉक्टर्स की फीस ये टेस्ट की फीस वो पेशेंट के वाइज दी जाती थी तो उसमें भी एक घोटाला पाया गया और साथ में विज्ञापन पर जो खर्च किया गया जो की 46 करोड से सीधा आपके 2021-22 में सीधे सीधे 612 करोड रूपए तक पहुँच गया। इस पर भी सरकार ने जो काम किया उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीधे सीधे कहा, ये नियमों का उल्लंघन है। विकास कम प्रचार ज्यादा इसका मतलब और आवाज़ घोटाला जैसे आवाज घोटाले की मैं माननीय हमारे मंत्री बड़े भाई प्रवेश जी ने बहुत विस्तृत रूप में कह दिया तो इसमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है और बुजुर्गों के लिए ये योजनाएं थीं। ओल्ड ऐज होम। वो 7-8 साल तक बन भी नहीं पाए क्योंकि आज ओल्ड ऐज होम की बहुत आवश्यकता है और जो रात्रि आश्रयसुधा आपके केंद्र होते हैं वो भी नहीं बन पाए। उसमें से यदि हम देंखे 277 आश्रय सुधार जो है रात्रि आश्रय स्थलों पर डे-केयर जो है वो 26 टीम अपॉइंट होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी टीम अपॉइंट नहीं की गई और कहाँ वहाँ पर कोई सर्विस जो मिलनी चाहिए शौचालयों की सफाई, वहाँ अटेंडेंट की रहना वो कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला? इस तरह से यदि देखें कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हाउस टैक्स समय पर ना देने पर उसका 15% का जो डिस्काउंट मिलता है एमसीडी देती है। प्री पेमेंट के लिए जून तक की पेमेंट करने पर वो भी समय पर पेमेंट ना होने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को कराया। इसी तरह से यदि हम बात करें लाडली योजना की। लाड़ली योजना के अंतर्गत यदि हम बात करें लाड़ली योजना 2009 और 10 में 1,39,773 रजिस्ट्रेशन थे, जो 2020-21 में आकर जो है सीधे सीधे 69% कम होकर 43,415 रह गए और ऐसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन जब न्यू बेबी बॉर्न होती है। तब उसमें 2009-10 में 23,871 थे, उससे कम होकर वो मात्र 3153 रह गई तो इसका मतलब है इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी

लाडली योजना लखपति बिटिया योजना जो पहले दसवीं कक्षा तक थी उसको आगे तक चलाया जाता था, उसको आगे एक्सटेंड ग्रैजुएशन तक कर दिया गया है जिससे कि उनको और डीबीटी के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए पैसा दिया गया है और इसमें लाडली योजना में 618 करोड रूपया आपके बिना उपयोग पड़ा रह गया और साथ में अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं। इस सीएजी इस रिपोर्ट में 340 पेज की ये सीएजी रिपोर्ट है। यदि इस पर समय लगे तो बहुत समय चाहिए कि इस पूर्ववर्ती सरकार का, जिसमें हर क्षेत्र में हर विभाग में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और विज्ञापन ज्यादा विकास कम विकास तो था ही नहीं। तो इसीलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी इतना ही कहूंगा की ऐसी पूर्ववर्ती सरकार की जो सीएजी रिपोर्ट आई है समक्ष हमारे, सीएम मैम ने दी है उस पर गहन जांच करके इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जिससे कि आने वाले समय में अधिकारी भी डरें कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए तो इसको कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

(अपराह्न 3.27 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन ने उन दर्दों को फिर से महसूस किया जो पिछली सरकार ने इस दिल्ली की जनता को दिए और दिल्ली की जनता के शब्द यदि मैं यूं कहूँ कि उनके मुँह से क्या निकल रहा होगा? तो शायद वो कह रहे होंगे कि :

''वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता,

वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता,

उसने यूं किया, उसने यूं किया कि दवा देना बंद कर दिया।''

और ये सदन जो सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि ये चर्चा केवल बिल्डिंग की नहीं, फर्निचर की नहीं, इंटीरियर्स की नहीं, ये चर्चा है उस सुनियोजित धोखे, उस सुनियोजित धोखे की, उसे बेनकाब करने के लिए आज यहाँ पे इस सदन में बात हो रही है जिसको केजरीवाल साहब ने वर्षों तक रोके रखा। वर्षों तक इसे रोके रखा, ये रिपोर्ट उस नैतिक पतन का, उस नैतिक पतन का दस्तावेज है जो दिल्ली की जनता को आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी बोल करके उन्होंने अपने आप को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा, नौकर थे, दास थे जो वो कहेंगे, मान लेंगे जो दिखाएंगे, देख लेंगे, जो कहेंगे वो सुन लेंगे, मैं महसूस करती हूँ ये वही सदन है, वो यही कुर्सी थी जहाँ से बैठ करके वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते थे, दिल्ली की जनता को गुमराह करते थे, आईना कुछ और दिखाते

थे, तस्वीर कुछ और होती थी, धोखा देते थे दिल्ली की जनता को। हम सबको याद होगा कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के घर के 10 एसीस के बारे में किस तरीके के वक्तव्य उनके होते थे? शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी, 10 एसी, 10 एसी हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की जनता पूछना चाहती है 50 एसी अपने घर में लगा करके, 70 पंखे लगा करके वो कौन सा महल बनाया था जो शीला दीक्षित जी के 10 एसी से कम था? किस तरीके से वो अपना पिक्चर दिखाते थे, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, पर चाहिए सब कुछ था सब कुछ चाहिए था उस व्यक्ति को। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, वो शिड्यूल लेके घूमते हैं कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें भी कहा गया कि देखिए, दिल्ली में दुर्घटना हो गई, बजट पेश किया जा रहा है, खीर बांटी जा रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए तो क्या? ये शेड्यूल बुक ले करके उन्होंने अपने समय के मुख्यमंत्री को नहीं बताया कि जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मर रहे थे, जब पूरे देश में लाखों लोग मर रहे थे और पूरी दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे तब केजरीवाल साहब अपने लिए महल बना रहे थे । तब वो अपने लिए महल बना रहे थे। ये शिड्यूल बुक तब निकाल के नहीं बोला कि भाई इस समय अपने लिए महल नहीं, लोगों के लिए अस्पताल बनाओ, बेड बनाओ, आइसीयू बनाओ ये तब नहीं उनको शिड्यूल नजर आया। आज हमें कहते हैं कि बजट मत लाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ट्वीट नहीं किया, ऐसे किया, जैसे हमारे गार्डियन वही लग रहे हैं। अरे जिनके गार्डियन हैं, वो थे उनको क्यों नहीं कहा गया? आज बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पढी गई कई चीजें तो हमें ही नहीं पता ये क्या है। वो डम वेटर लिफ्ट? कह रहे जी वो नीचे से ऊपर खाना ले जाने के लिए लिफ्ट होती है? तो इतने नौकर थे, इतना स्टाफ था वो इतनी उनकी जो स्टाफ की लिस्ट थी वो क्या करते थे? वो खाना नीचे से ऊपर ले जाने के लिए 7 लाख की लिफ्ट। वो कह रहे हैं कि जी टीवी बता रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, कॉफी की मशीन 18 लाख रूपये, 18 लाख रूपये की कॉफी, पर घर में तो कोई आता नहीं था, ना किसी को अधिकारी को आने की इजाजत थी, ना एमएलए को, ना जनता को, वो कॉफी पीता कौन था, जिस तरीके से उस पूरे घर को बनाया गया। एक दिन मैंने परवेश जी को कहा कि भैया हमें भी दिखा लाइए। हम देखे तो सही, हमने क्या छोड़ा, तो ले गए ये, तो कह रहे हैं कि देखिए, ये कमरा देखिए, ये कमरा देखिए, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए, मैंने कहा भई फिर घर आके पूछ रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है? मैने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं धर्मशाला में रह रही हूँ। वो महल के आगे बाकी सबके घर धर्मशाला जैसे हैं। अध्यक्ष जी आप भी धर्मशाला में है, हम भी धर्मशाला में है, दिल्ली की जनता भी धर्मशाला में है, दिल्ली में एक ही महल है शीश महल और अब, अब पंजाब में शीशमहल टू में जाके बस गए हैं। शीश महल टू में जाकर के रह रहे हैं और दिल्ली की जनता को वहीं से भाषण देते हैं। देखिए 1 साल में दिल्ली बिगड़ गई, दिल्ली बर्बाद हो गई। बर्बाद तो

तब हो रही थी जब वो दिल्ली में बैठ कर के दिल्ली की जनता को नोच रहे थे, उनका खून पसीने की गाढी कमाई को लूट रहे थे। जब एक काम के लिए छह छह कैसलटेंट रखे जाते थे, छह छह कंसल्टेंट, ये इंटीरियर बताएगा, ये फर्निचर बताएगा, ये लैंडस्केप बताएगा, ये सीलिंग बताएगा, छह छह कंसल्टेंट, किसी टेंडर से नहीं, किसी नोटिफिकेशन से नहीं, प्राइवेट, प्राइवेट करोड़ों रुपए कंसलटेंट को दिए गए। कहाँ क्या किया गया? कॉन्ट्रैक्टर जो बुलाए गए। वो भी सब बिना टेंडर के और पता था उसमें से एक ही व्यक्ति एलिजिबल है उसको दे दिया गया ठेका फिर कितनी चालाकी के साथ, उन्हें पता था कि भई चीफ इंजीनियर की पावर जो है 10 करोड की है। बस इससे ऊपर जाना नहीं, इसको किसी को बताना नहीं और लगाते गए लगाते गए कब, वो एक मैं रील दिखा दीजिएगा, हमारे किसी विधायक ने दिखाई उन्हीं के कोई नेता बोल रहे थे कि हमारे टाइम में 1 करोड का टेंडर 55 लाख में छूटता था तो भई ये 8 करोड का ये 62 करोड कैसे हो गया? ये 62 करोड कब हो गया, कैसे हो गया? ये भी तो तुम्हारे टाइम का था, इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान तुम्हें आज किसी को बताइए तो सही, जिस तरीके से उन्होंने और ये एक चीज़ नहीं है और ये खाली केजरीवाल साहब का नहीं है बाकियों पे तो उन्होंने निगाह आने ही नहीं दी। राखी बिरलान, इन्होंने अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए 2 करोड 33 लाख, रामनिवास जी जो विधानसभा आप अध्यक्ष जी कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, देखिये 3 करोड 23 लाख रूपये रामनिवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2 करोड 55 लाख, सत्येन्द्र जैन जी ने 2 करोड, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड और ये आतिशी जी बेचारी महिला हैं, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं है। वो तो 67 लाख में ही निपट गई। मनीष सिसोदिया बड़े मंत्री थे, बड़े मंत्री, यहाँ बैठते थे कहीं यही कहीं, तो बड़े मंत्री जी को थी उन्होंने साढे सात करोड, साढे सात करोड।

....व्यवधान......

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री :घर रेजिडेंस, रेजिडेंस, रेजिडेंस, ऑफिस जाता कौन था भई, ऑफिस की जरूरत क्या थी, घर घर खेलते थे।

....व्यवधान......

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री :हाँ, रेनोवेशन, रेनोवेशन, भई रेनोवेशन के लिए तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड, राजेंद्रपाल गौतम 3 करोड, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग और वो और सचिवालय नहीं जाते थे। बनाया वो भी था। कभी

शीश महल टू अगर देखना हो दिल्ली में एक ये बता रहे हैं, एक मैं बता रही हूँ जो सचिवालय में उनका कमरा है वो भी शीशमहल टू है। उसमें जा करके देखिए, आप कह रहे हैं इतनी डाइनिंग, वहाँ पे भी इतनी बड़ी डाइनिंग। आते नहीं थे कभी सचिवालय कभी आते नहीं थे पर

डाइनिंग पूरी थी, टेबल बहुत बड़ी थी, फाईल नहीं होती थी, काम नहीं होता था पर टेबल पूरी शानदार। मैंने तो आने के बाद इसमें से तीन बन जाएगी मैंने कहा परवेश जी, एक आप ले जाओ, सिरसा जी एक आप ले जाओ, मैं कहा ये तो बहुत बड़ी टेबल है, कह रहे नहीं मैडम सीएम की इतनी होनी चाहिए रखिए, रखिए। मैं कहा ठीक है, ऐसा ही होता होगा। अब क्या करते, काम तो करना ही था। तो आज वहाँ पे जाते हैं वो बार बार याद दिलाता है कि यहीं थे, यहीं थे। जब हमने ऑफिस चार्ज लिया तो कह रहे फोटो इधर लग गई, फोटो उधर लग गई, सारा ध्यान फोटो पे अटका रहे, ये नहीं बताने दे रहे कि भाई यहाँ पे इन फोटो के पीछे और क्या क्या चिट्ठा था, और क्या क्या कहानियों थी जो दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए थी पर कभी बताने नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहती हूँ ये सीएजी रिपोर्ट, ये सीएजी रिपोर्ट जो यहाँ पेश की गई है, ये पुलिंदा है उनकी धोखाधड़ी का, दिल्ली की जनता के साथ में जिस तरीके का गुनाह उन्होंने किया, दिल्ली की जनता का जो पैसा उन्होंने खाया और दिल्ली के साथ आम आदमी, आम आदमी बोल करके जो गबन उन्होंने यहाँ पे किया, ये पुलिंदा है। दिल्ली को फ्लाई ओवर चाहिए थे, दिल्ली को सड़कें चाहिए थी पर उन्होंने अपने लिए फाइव स्टार महल बनवाया। दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था परंतु उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। सादगी नारा था पर अंदाज शाही था, नारा सादगी था पर अंदाज शाही था, राजनीति बदल देंगे, बोलते थे राजनीति बदल देंगे, पुराना घर बदल लिया, पुराना घर बदल लिया और एक करोड़ के पर्दों में नंगी सच्चाई छिपी थी, उन एक करोड़ के पर्दो में नंगी सच्चाई छिपी थी और आटोमेटिक जो डोर थे उसमें जवाबदेही का कोई धागा नहीं था। कोई जवाबदेही का धागा नहीं था। ये हाल था कि घर शीश महल के अंदर जनाब थे और बाहर आम आदमी की लंबी कतारें लगी थी, बाहर आम आदमी की लंबी कतारें थी, किसी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कभी जन सुनवाई नाम का शब्द दिल्ली ने 11 साल में सुना नहीं, कभी किसी से उन्होंने बात की नहीं और 342% लूट की बात करते हैं, उन्होंने तो 1000% लूट करी दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई। नियमों को तोड़ा मरोड़ा नहीं, नियमों को कुचल दिया, कोई नियम था ही नहीं, कोई नियम कायदा, कानून, टेंडर प्रक्रिया, सैंक्शन कैबिनेट कोई मतलब नहीं था उनको, इन सब चीजों से वो ऊपर थे, शहंशाह थे, शहंशाहे आलम थे। बजट दिल्ली की जनता के लिए कम था, उनके कंफर्ट के लिए पूरा था। जितना मर्जी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं थी और दिल्ली की जनता दम घुटने से मर रही थी, पर अपने घर में उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा रखा था। ये दास्तां है दिल्ली की जनता की, दिल्ली की जनता की मजबूरी की। आज ये सदन इस बात पे बेहद अफसोस ज़ाहिर करता है कि वर्षों तक दिल्ली की जनता को ये दर्द सहना पड़ा। पर आज हमारी सरकार वर्तमान में एक एक दिल्ली की जनता के पैसे का उपयोग बेहतर हो, दिल्ली के हित में हो, दिल्ली के विकास के लिए हो ये सुनिश्चित कर रही है अध्यक्ष जी, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो

रिपोर्ट है, इसके ऊपर सही कार्रवाई होनी चाहिए और इन गुनहगारों को सजा होनी चाहिए और इसको पीएसी में भेजा जाए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण जो आइटम नंबर तीन का पहला भाग है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या पांच) इसको पीएसी को भेजा जा रहा है। बाकी अभी जो बाकी सीएजी रिपोर्ट्स अभी एजेंडे पे रहेंगी, जिनका निपटारन परसों किया जाएगा। अब मैं चूंकि समय की सीमा है और सदन का समय 4:00 बजे तक है तो एक आइटम नंबर पांच विधेयक की पुनः स्थापना, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल वो आज इंट्रोड्यूस करना मुख्यमंत्री जी द्वारा आवश्यक है जो राजस्व मंत्री भी हैं, तो क्योंकि आज ये इंट्रोड्यूस होगा, टेबल होगा और परसों इस पर बात होगी और फिर ये पारित किया जाएगा। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री सोसाइटी पंजीकरण, (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) को सदन में इंट्रोड्यूस करने की अनुमति मांगेंगी।

विधेयक का प्रस्तुतिकरण

श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं सोसाइटी पंजीकरण, (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ, पक्ष जीता।

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। अनुमति दी गई है पहले, अब इंट्रोड्यूस करेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से सोसाइटी पंजीकरण, (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ।[2]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :बिल अब इंट्रोड्यूस हुआ है और इसकी कॉपी सभी को हमने परसों ही उपलब्ध करा दी थी। अब इस पर चर्चा जो है वो परसों की जाएगी। अब बजट पर भी हमारी।

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: बजट पर चर्चा में 15 मिनट हाउस को बढ़ा दें कम से कम पांच लोग आज बोल लें क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :ऐसा है कि मुझे लगता है कि

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: आज कम से कम पांच लोग बोल लें बाकी 15 लोग परसों बोल लेंगे क्योंकि बहुत लंबी सूची है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :वो एक घंटा हो जाएगा, हाँ।

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: हाँ, आशीष जी करेंगे ना? हाँ हाँ, ठीक है, उसके आगे भी तो बोलना है, हाँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :इसमें आज तो इसको 4:00 बजे तक ही रखेंगे सदन को, सदस्यों का भी यही कहना है तो 15 मिनट में जितने लोग बोल पाएंगे। ठीक है ना? पांच लोग फिर जल्दी जल्दी क्यों थोड़ा सा बजट है। आप आप आज बोलेंगे क्या? तो भाई इनका करवा देते हैं आज, उसमें जो समय लेंगे लेंगे। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24 मार्च 2026 को प्रस्तुत वार्षिक बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना भाषण बजट से संबंधित विषयों तक सीमित रखें। समय का विशेष ध्यान रखें ताकि सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके और जल्दी से जल्दी ज्यादा सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर मिल सके। अब सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे श्री आशीष सूद माननीय मंत्री, दिल्ली सरकार।

वार्षिक बजट(2026-27) पर चर्चा

श्री आशीष सूद, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री: बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा दिल्ली की जनता के हितों के लिए, दिल्ली के विकास कार्यों के लिए, विकसित भारत की राजधानी, विकसित

---

[2] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23572 पर उपलब्ध।

दिल्ली बनाने के लिए वर्ष 26-27 के प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट किसी भी राज्य का, किसी भी सरकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और आज इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में विपक्ष की अनुपस्थिति अपने आप में एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की, दिल्ली के मुद्दों से विमुख, दिल्ली में अपनी जमीन खो चुके विपक्ष को स्थापित करती हैं। इस सदन में वर्तमान फॉर्मेट ऑफ जब गवर्नमेंट था। 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब विपक्ष की टेबलों पर नेता, प्रतिपक्ष के नाते जग प्रवेश चंद्र जी बैठा करते थे। अध्यक्ष जी दिल्ली ने ऐसा भी देखा है वित्त मंत्री से ज्यादा, अखबार, मीडिया, प्रबद्धजन, नेता प्रतिपक्ष के बजट और राज्य के संबंध में मत को सुनने के लिए लोग आया करते थे, अखबारों में सुना करते थे, विधानसभा में आया करते थे। उसके बाद 15 साल श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार रही। नेता, प्रतिपक्ष के रूप में श्री जगदीश मुखी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा थे तब भी दुनिया ने देखा नेता, प्रतिपक्ष की बातों को सुनने के लिए संख्या में हम कम थे, आप भी नेता, प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। क्योंकि उस समय नेता, प्रतिपक्ष दिल्ली की समस्याओं के प्रति उतना ही सरोकार रखते थे जितना कि सरकार या पक्ष के नेता रखते हैं, तैयारी करते थे, मुद्दों पर बोलते थे, स्टडी करते थे, अर्थनीति पर, आर्थिक नीति पर एक्स्पर्ट से बात करते थे, तब बोल पाते थे। हमने वो भी दौर देखा है। आज आज मामला क्या है कि हमारे चार सदस्यों को एक्सपेल किया हुआ है। ओमप्रकाश जी यहाँ बैठे हैं। डेढ़ साल तक ओमप्रकाश जी एक्सपेल रहे, उनको घुसने नहीं दिया। आप विरोध करते थे। लोगों ने देखा कि आपको अपने कंधों पे उठा के मार्शलों से बाहर फेंकवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे तीन थे या आठ थे, हम हर मुद्दे पर सदन में दिल्ली की जनता की बात कहते थे जबकि हमारे एक माननीय सदस्य को डेढ़ वर्ष तक प्रताड़ित करके, हाई कोर्ट जाना पड़ा ओमप्रकाश जी को। हमने तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाई और आज और आज केवल अपने नकारेपन को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपनी क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक एक सेक्टर के लिए एक-एक विषय के लिए पैसा का अलॉटमेंट किया है, दिल्ली के विकास कार्यों के लिए एक माला बुनी है, उस माला को उनके सामने जब वो पढती है तो उनका फेलियर दिखता है। इसलिए इसलिए हमारा विरोधी पक्ष सदन से गायब है। मुझे मालूम है मैं अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में खड़े होकर कह रहा हूँ। आज सुबह मेरे पास आम आदमी पार्टी के चार विधायकों का फ़ोन आया। दो विधायक अनोथोराइज्ड कॉलोनी से संबंध रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आशीष जी आपको मालूम है आप की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनाधिकृत कॉलोनियों में पिछली बार का सारा पैसा लगा दिया, नया पैसा दिया विधायक आम आदमी पार्टी के विधेयकों में चर्चा है कि भाई सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। दो विधायक ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी बहुत ज्यादा है। वो मुझे रोज़ फ़ोन

करते हैं, भाई साहब दो दो अटल कैंटीन और खुलवा दो। दो होटल कैंटीन भाई साहब और खुलवा दो। मेरे इलाके में दो अटल कैंटीन और खुलवा दो। उन्होंने मुझे बताया और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया, अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में बैठे डरे हुए कई विधायक यहाँ आकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट की और पिछले साल के इम्प्लिमेंटेशन की तारीफ ना कर दे इसलिए बाहर रोका हुआ सबको इसलिए रोक रखा है बाहर सबको जबरदस्ती। forcefully रोका हुआ है। मुझे मालूम है पक्का वो सुन रहे होंगे आज। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से उनके लिए तीन लाइन कहना चाहता हूँ उनके लिए है ये :

''तुम्हारी आंख में आंसू, हमारे घर में शहनाई

तुम्हारी आंख में आंसू, हमारे घर में शहनाई,

हमारे दिल में ऐसी दुश्मनी पाली नहीं जाती।''

और चाहे वो किसी भी प्रकार का रुख रखें, पर्सनल निजी टिप्पणियां करें, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दें, हमारी मुख्यमंत्री जी को निजी टिप्पणी में belittle करने की कोशिश करें, दिल्ली की बेटियों को belittle करने की कोशिश करें, मगर हम दिल्ली के डेवलपमेंट के काम से पीछे रहने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में उसे रुकने नहीं देंगे। आपने पिछले बार मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया था। तब मैंने दो लाइन कही थी। मैंने दो लाइन कही थी:

''तुमने गिरा डाली एक लम्हें में इमारत,

अरसे लगेंगे हमें मलबा हटाने में।''

मैंने पिछले बजट में ये बात कही थी अध्यक्ष जी। क्यों कही थी? मात्र 33 दिन में हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री मात्र 33 दिन, आज हम 25 तारीख को बात कर रहे हैं। पिछले साल 24 मार्च को बजट प्रस्तुत हुआ था। मात्र 33 दिन में दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने एक लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था एक लाख करोड़ रुपए का। मात्र 33 दिन में एक लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। अध्यक्ष जी तब मैंने उस बजट को रिवाइवल ऑफ दिल्ली का बजट कहा था क्योंकि उस समय उस समय जरूरत थी। उस समय जरूरत थी व्यवस्था को संभालने की, सिस्टम को पटरी पे लाने की और आज उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ठीक तीन उस दिन से ठीक 364 दिन बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं इस वर्ष के बजट को budget of re- defining governance का नाम देना चाहता हूँ। इस ग्रीन बजट को मैं कहता हूँ This is re- defining of governance.

''तूफान से कश्ती को निकाला ही नहीं है,

तूफान से कश्ती को निकाला ही नहीं है,

हमने मंजिल का पता भी बता दिया है,

हमने मंजिल का पता भी बता दिया है।''

मंजिल का पता क्या बता दिया है, क्या मंजिल का पता बता दिया है? हमने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, हमने दिल्ली को विकास की राह पर चला दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी मंजिल का पता क्या है? मंजिल का पता है कि दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग का बजट है ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत बजट। दिल्ली की आज तक की सबसे बड़ी कैपिटल स्पेंडिंग है। इस बजट में। 23-24 में 21,000 करोड़ रुपए की कैपिटल स्पेंडिंग थी, 24-25 में 15,000 करोड़ रुपए की कैपिटल स्पेंडिंग थी और 25-26 में जहाँ मुख्यमंत्री जी ने 28,115 करोड रूपये की कैपिटल स्पेंडिंग कही थी, आज इस वर्ष के बजट में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैपिटल स्पेंडिंग है। ये कैपिटल स्पेंडिंग क्या है? ये कैपिटल स्पेंडिंग से दिल्ली की विकास को क्या रिश्ता है? जब कोई हर सरकार जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, तनख्वाह के पैसे उसको देने ही पड़ेंगे, टीचरों की तनख्वाह देनी पड़ेगी, ड्राइवर्स की तनख्वाह देनी पड़ेगी, डॉक्टर्स की तनख्वाह देनी पड़ेगी, रेवेन्यू का खर्चा तो करना ही पड़ेगा, मगर राज्य में विकास कब होता है? राज्य में विकास होता है जब कैपिटल स्पेंडिंग हो, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती है। स्कूल पे, कॉलेज पे, बिल्डिंग पे, हॉस्पिटल पे, ट्रांसपोर्ट पे, बस पे, पुल पे, नाली पे, ब्रिजेस पे, इन सब पर जब पैसा खर्च होता है तब, तब तब इकॉनमी में buoyancy आती है, तब इकॉनमी में लोगों का विश्वास जगता है। जिस सेक्टर में सरकार का पैसा लगता है। उस सेक्टर में पब्लिक भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी आकर पैसा लगाता है और उसके कारण रोजगार का भी सृजन होता है। विकास कार्यों को भी गति मिलती है तो 32 हजार करोड़ रुपए की सबसे बड़ी कैपिटल स्पेंडिंग के साथ और केवल इतना ही पता नहीं बताया हमने, केवल इतना ही पता नहीं बताया हमने। सबसे बड़ी उपलब्धि जिसके लिए मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी को नेतृत्व को उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को बधाई देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी अगले वर्ष नगर निगम का चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री चाहती तो लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा सकती थी, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। ऐसा होता ही है जब बजट आता है चुनाव से पहले के बजटों में सरकारें बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं करती है। कहा जा सकता था मेट्रो के पास फ्री हो जाएंगे। कहा जा सकता था हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा पिछली सरकारें हर साल किया करती थी, मगर दृढ़ राजनीति की इच्छा शक्ति के साथ श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बजट को ,बजट को इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी 1 मिनट सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है 4 .15 तक के लिए सदन बढ़ाया जाता है।

श्री आशीष सूद, गृह, शहरी विकास, शिक्षा मंत्री: श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इकोनॉमिक्स को, बजट को पॉलिटिक्स के साथ डिहाइफोनेट कर दिया है। घोषणाएं की जा सकती थीं, बड़ी बड़ी घोषणाएं। मगर लोकलुभावन, आसान रास्ते को छोड़कर हमने रास्ता चुना प्रशासनिक सुधार का, हमने रास्ता चुना स्टेबिलिटी का, हमने रास्ता चुना कंटिन्यूटी का क्योंकि उनके लिए तो बजट केवल हेडलाइन मनेजमेंट का बजट था। अध्यक्ष जी जब मैंने इस बार बजट पे बोलने से पहले देखा पिछले 10 साल में क्या चला। तो 1 साल स्वराज बजट आया। 16-17 में जीरो टैक्स बजट आया, 17-18 में आउटकम बजट आया 19-20 में डेडिकेटेड टू दी मार्टरस ऑफ पुलवामा बजट आया पुलवामा के मार्टरस को डेडिकेट हुआ मगर उसी साल बालाकोट के एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रही थी सरकार। देशभक्ति का बजट आया, रोजगार का बजट आया, 23-24 में साफ-सुन्दर और आधुनिक दिल्ली का बजट आया, साफ सुन्दर और आधुनिक दिल्ली का बजट। कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों ने जनवरी में हड़ताल की, नवंबर में हड़ताल की और दिवाली से ठीक पहले हड़ताल की। मगर बजट का नाम क्योंकि हेडलाइन मैनेज करनी थी, साफ सुन्दर और आधुनिक दिल्ली का बजट था। और सबसे बड़ी बात तो ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 24-25 के बजट था रामराज्य का बजट। आदरणीय नानी जी, मेरी नहीं, आदरणीय नानी जी केजरीवाल जी की कहा करती थी उस राम मंदिर में नहीं जाना जो किसी और की जमीन पे बना हो। मगर राम मंदिर पे दुनिया पूरा देश उद्वेलित था राम मंदिर का बजट आया और कैसे राम जी का भी, राम जीके बजट के नाम पे भी राम जी का भी सामान खर्च में धोखा दे दिया वो अगले 2 मिनट बाद आपको बताऊँगा अध्यक्ष जी। We chose the politics of order instead of chaos, इसलिए हमने उसमें कंसिस्टेंसी रखी। 2023-24 में 78,000 करोड़ का बजट था, 2024-25 में 76 हजार कर दिया। हमने 2025-26 में 1,00,000 करोड़ का बजट दिया। इस बार हमने 1,03,700 करोड़ रूपए का बजट दिया ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक विश्वास जागृत हो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करने वाले का, इकॉनमी में व्यापार करने वाले का, इकॉनमी में कारोबार करने वाले का। इस विश्वास को जागृत करने में हम सफल हुए हैं। We have been able to increase the optimism in the economy. हम चाहते हैं तो लोक लुभावन योजनाएं दे सकते थे, मगर हमने क्या किया हमने किया कंटिन्यूटी और उसके साथ प्रशासनिक सुधार का काम कठिन काम चुना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए पिंक कार्ड लाने का काम चुना। 2007 से बढ़ रहे रेग्युलेटरी एसेट्स की व्यवस्था क्योंकि लोड को, से निपटाने का काम, एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने का काम, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के विवाद खत्म कराने का काम और कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का रास्ता हमने चुना, ये हमने चुना और इन सबने इकॉनमी में एक

एक बहुत बड़ी ऑप्टिमिज्म दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि हमने बजट का साइज बढ़ा दिया। गले में एक तगमा लगा के घूमते थे खुद ही आइआइटी मुख्यमंत्री, ये आइआइटी मुख्यमंत्री हैं, आइआइटी पास है मुख्यमंत्री। अभी बताता हूँ देखो आइआइटी पास ने क्या क्या किया और हमारी मुख्यमंत्री जी ने कैसे उन गड्ढों को भरने का, जो मैं कहता हूँ कि हमने पता भी बता दिया कैसे पता बता रहे हैं हम। आइआइटी मुख्यमंत्री है, आइआरएस थे, आइआरएस थे अरे साहब देशभर में आप सबका ध्यान चाहता हूं, देश भर में 2023-24 में विकास दर थी 8.6% मगर दिल्ली की विकास दर थी 7.4%, 2024-25 में देश की विकास दर थी 6.5% दिल्ली की विकास दर थी 6.1% ये आइआइटी का मुख्यमंत्री था, ये आइआइटी पास मुख्यमंत्री की करामत है। गले में तगमा लगा के घूमते थे, आइआरएस है और उसके विपरीत इस वर्ष देश में विकास दर है 7.4% और हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की विकास दर 8.53% पर है नेशनल एवरेज से ज्यादा विकास दर हमने अचीव की है। ये अचीवमेंट होती है, ये अचीवमेंट होती है, ये अचीवमेंट होती है। ये फिर ये 15 मिनट में फिर कर देंगे। 10 ही मिनट रह गए। जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये ये अचीवमेंट हो पाती है कब जब दृढ़ राजनीति की इच्छा शक्ति और जनता की सेवा करने की भावना तब हो पाती है और आइआइटी का मेडल खुद पहन के घूमते थे, खुद को तो यहीं पे खड़े होके कहते थे दिल्ली के मालिक हमें हैं, आइआइटी पास मुख्यमंत्री है, क्या गुल खिलाए 2023-24 में कोई भी बजट, कोई भी राज्य, किसी भी इकॉनमी को आगे बढ़ना है तो उधार पर नहीं बढ़ सकती है, अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ानी पड़ती है अपनी टैक्स की ताकत को अपने, अपने सोर्स इन का सोर्स ऑफ इन्कम बढ़ाने पड़ते हैं। 2023-24 में स्टेट का अपनी टैक्स रेवेन्यू था 55,000 करोड़ रुपए जो 2024-25 में 58,750 करोड़ रुपए हुआ, 58,750 करोड़ यानी 6.4 %की वृद्धि अचीव हुई 1 साल में। 2024-25 में 59,200 करोड़ रूपए का रीवाइज एस्टीमेट बना बजट के टैक्स कलेक्शन का और श्रीमती रेखा गुप्ता जी की कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 25-26 में 16.4% की वृद्धि के साथ 68,700 करोड़ रूपए का टैक्स रेवइन्यू हमने कलेक्ट किया ताकि राज्य अपने पैर पर खड़ा हो। हमारा बजट जो हम स्पेंडिंग करना चाहते हैं, उसकी इन्कम हमें अपने आप मिले और आज जो सुबह से मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया बहुत सारे बेरोजगार लोग बजट पर कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। एक सदस्य हमारे विरोधी दल के कर्जे के बारे में बोल रहे थे। तो 2023-24 में वो आइआइटी का टैग गले में लगाए हुए वो आइआइटी वाले मुख्यमंत्री दिल्ली पर 40,323 करोड़ रूपए का कर्ज छोड़ कर गए थे 40,323 करोड़। हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करंट गवर्नमेंट के नेतृत्व में 2025-26 में वो घटकर 30,557 करोड़ रूपए हो गया है, ये होता है वित्तीय प्रबंधन, ये होता है फिसक्ल मनेजमेंट इस फिसक्ल मनेजमेंट के चलते और मैं आप सब साथियों को ये बताने में बहुत गर्व अनुभव करता हूँ, बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। किसी भी सरकार का

वितीय प्रबंधन कैसे पता चलता है। आप सब राजनीतिक लोग हैं और मुझे जीतने भी लोग सुन रहे हैं किसी भी सरकार की किसी भी सरकार की निंदा की जाती है तो किस बात पे की जाती है, सरकार फेल हो गई महंगाई रोकने में। मैं आपको गर्व के साथ कहता हूँ पूरे विश्वास के साथ आंकड़ों के सबूत के साथ दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को साबित किया है। वर्ष 2022-23 में,20 22 की जनवरी से लेकर 2022 के दिसंबर तक जनवरी में महंगाई दर दिल्ली की थी 6.14 फरवरी में 5. 70, मार्च में 5.75 अप्रैल में 6.58, मई में 5.57, जुलाई में 4.13 ऐसे करते करते दिसंबर में 2.98 की महंगाई दर थी। कुल महंगाई दर थी 4.61, 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसी तरह महंगाई दर थी 2.81, 2024 के जनवरी में शुरू हुई 2.56 से फरवरी में 2.42 पे, मार्च 2.29 और एनुअल इन्फ्लेशन रेट दिल्ली में था 2.59 परसेंट। आप सबको गर्व की अनुभूति होगी क्योंकि आप सबके परिश्रम के कारण मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनवरी में 2025 में महंगाई दर थी 2.02, फरवरी में 1.54, मार्च में 1.41, अप्रैल में 1.77, मई में 2.07, जून में 1.72, जुलाई में .52 आधा परसेंट। अगस्त में .8, सितंबर में .5, अक्टूबर में -.28 और नवंबर में 0.34 और दिसंबर में 1.17 with an annual inflation rate of ever lowest 1.13 %in Delhi 1.13 की महंगाई दर पे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लाकर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट, ये बजट मोदी जी के वादों को पूरा करने का बजट है। ये बजट मोदी जी के मार्गदर्शन में 'अंत्योदय' और 'सबका साथ सबके विकास' की भावनाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। इस बजट में हमारी बेटियों के लिए साइकिल है ताकि उनके जीवन का और उनकी शिक्षा का रास्ता आसान हो। और साथ ही साथ गरीब के लिए 5 रुपए का पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन भी है ताकि कोई भी भूखा ना सोए। इस बजट में स्कूल के बच्चों के लिए एआई पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम हैं ताकि वो फ्यूचर रेडी हों। और नागरिकों के लिए पानी और सीवर की समस्या दूर होने के लिए 9 हजार करोड़ रुपए भी हैं। इसमें महिलाओं की बस सेवा है ताकि उनकी मोबिलिटी और सेफ्टी बढ़े। पॉल्यूशन से लड़ने के लिए इवी बसेस हैं ताकि दिल्ली का एनवायरनमेंट साफ हो। हमारी बहनों के लिए रानी हाट है ताकि महिला बेनीफिशरीज आगे बढ़ सकें। और इस बजट में योजनाओं का वो संग्रह है, उस सोच का प्रतीक है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेता है। इस वर्ग में, इस बजट में सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को दिया गया है, 19 हजार 148 करोड़ रुपए। क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की बैकबोन है। मगर इससे पहले कि मैं ये यहाँ पर आपको लेकर जाऊं, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें मिला क्या था? शिक्षा में हमें मिला क्या? सलेमपुर माजरा का ये स्कूल डीटीडीसी में, इतने, 37 करोड़ रुपए देने के बाद भी आज अधूरा है और अभी भी, अभी भी 8 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं। ऐसे आधे अधूरे स्कूल, ऐसे आधे अधूरी बिल्डिंग्स, ऐसे आधे अधूरे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रोजेक्ट्स को छोड़कर गई थी ये सरकार। हमें यहाँ मिला है, जब मैं ये कहता हूँ, जब मैं ये

पढ़ता हूँ पहले, पहले वाक्य में जब मैं ये पढ़ कर बताता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कश्ती को निकाला ही नहीं है उसका पता भी बताया है, कश्ती यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है कश्ती, ये हालात मिले हैं हम लोगों को। इसलिए डीटीडीसी के अधूरे स्कूल, पीडब्ल्यूडी के टूटे हुए स्विमिंग पूल, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सीएसआर पे लिए गए कुछ छोटे -मोटे स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब्स। 2014 में आईसीटी लैब्स के नाम पर 10 कंप्यूटर की लैब बनाने की बात थी, केंद्र सरकार के पैसे से बनाई गई थी। एक सीपीयू लगाकर, 10 मॉनिटर लगाके बोला ये लैब बन गई। एक भी फंक्शनल लैब नहीं थी।

और जिसको भारत रत्न की मांग करते थे ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री के भारत रत्न की मांग करते थे कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दे दो, भारत रत्न दे दो। मैं करनैल सिंह जी के साथ गया पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर के पास। 2018 में शिक्षा क्रांति, 2018 में स्विमिंग पूल बनना शुरू हुआ, अब ये बंगाल में गए हुए थे, मैं जाकर अब 7 साल बाद, 8 साल बाद उसका उद्घाटन करके आया हूँ। ये पीडब्ल्यू, 200 मीटर दूर केवल, माननीय अध्यक्ष जी, सत्येंद्र जैन जी यहाँ हैं नहीं,

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): कितना समय और लेंगे आप?

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री) :कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। 15-16 मिनट और लगेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): जितना समय आप लेंगे उसी हिसाब से समय बढ़ाऊंगा मैं।

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री): तो फिर यही कह दो जब तक खत्म नहीं होता एक्सटेंड कर देते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): नहीं, नहीं।

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री): मेरे भाषण के लिए कह दो ना, अगला मत करना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष):आपको 15 मिनट में और दे रहा हूँ।

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री): ठीक है जी, मैं करता हूँ। बहुत आभार आपका।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): सदन का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री): बहुत -बहुत आभार, माननीय अध्यक्ष जी आपका बहु बहुत आभार। क्योंकि मामला ऐसा हैं ना जी। और पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर के पास, चिराग तले अंधेरा किसे कहते है, पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर के पास, पीडब्ल्यूडी का स्विमिंग पूल 8 साल

में पूरा हुआ, उसके लिए वहाँ की जनता को करनैल सिंह को जिताना पड़ा और मुख्यमंत्री जी को दिल्ली का नेतृत्व संभाल के हर विभाग को वापस अपनी पटरी पर लाने का काम करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय जी, जब हम एजुकेशन में access की बात करते हैं तो मुझे पूर्व प्रधानमंत्री - भारत रत्न, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं, जिन्होंने 'सर्व शिक्षा अभियान' के माध्यम से शिक्षा को घर -घर पहुंचाया। और जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री -नरेंद्र मोदी जी की याद आती हैं और जिन्होंने एनईपी के माध्यम से पूरे देश को गुणवत्ता परक शिक्षा देने की नई दिशा दी है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में access और क्वालिटी, दोनों एजुकेशन में एक साथ देने का काम किया है। Access यानी कैसे, access यानी 1 लाख 30हजार के लगभग बेटियों को साइकिल दिया जाएगा ताकि वो स्कूल आसानी से आ सकें। ज्यादा से ज्यादा नए स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम। ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में साइंस पढ़ाने का काम। क्वालिटी डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से आईसीटी लैब, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब्स, निपुण संकल्प के माध्यम से, नींव के माध्यम से और टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से।

माननीय अध्यक्ष जी, आज, आज हमारे पिछले साल के बजट के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरोजनी नगर का सीएम श्री स्कूल या दिल्ली का कोई भी दूरस्थ स्कूल वो सिर्फ बिल्डिंगें ही नहीं बन रही हैं, शिक्षा के बेंचमार्क बन रहे हैं। वे इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में एजुकेशन केवल अनाउंसमेंट में नहीं, access और क्वालिटी के, दोनों के blend के साथ ग्राउंड पे दिख रही है। अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि सीएम श्री स्कूल क्या है? बार -बार हमारे इन प्रयास को भी लिटिल करने की कोशिश की जाती है। सीएम श्री स्कूल वो 75 स्कूल हैं जिसमें हर स्कूल का 100% एनईपी 2020 से अलाइनमेंट है। Every classroom will be not, it's not classroom, एआई पावर्ड लैंग्वेज लैब है हर स्कूल में। डिजिटल लाइब्रेरिस है हर स्कूल में। मल्टी सेक्टोरियल लैब है, मल्टी सेक्टोरियल स्किल लैब्स हैं, करियर काउंसलिंग के लैब्स हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स है और सोशल इमोशनल लर्निंग है। इन आठ पिलर्स ने सीएम श्री स्कूल बनाया, इन आठ गुणों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किया है। यहाँ आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं रविंद्र भाई के साथ गया था। मैं और रविंद्र भाई शाहबाद डेयरी के लाल स्कूल में गए थे, लाल स्कूल में। शाहबाद डेयरी का लाल स्कूल, आम आदमी पार्टी सरकार की जो आज जानबूझकर नजर छुपाके गए, उन्हें पता था मैं पूछुंगा ये, वो लाल स्कूल आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की पोल

खोलता है और उसके बदले मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ सरोजिनी नगर में, सरोजिनी नगर के सीएम श्री स्कूल की विजिट जरूर करें। आपको मालूम पड़ेगा....

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): आशीष जी, चेयर की तरफ देख के बात करिए।

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री): आपको मालूम पड़ेगा। आप, आप सब उस स्कूल की, उन स्कूल में विजिट करें ताकि मालूम पड़े कि किस प्रकार से शिक्षा में दोनों मॉडल ऑफ गवर्नेंस में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है, दोनों मॉडल्स में क्या अंतर है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ जाने से पहले प्रिन्सिपल से समय लेकर जाइएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो।

2025-26 की अचीवमेंट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बताना चाहता हूँ। 31 मार्च तक 9 हजार स्मार्ट क्लासरूम्स पूरे हो जाएंगे। 9 हजार नए कंप्यूटर्स की आईसीटी लैब्स पूरी हो जाएंगी। 100 डिजिटल लाइब्रेरी, सौ स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी पूरी हो जाएंगी। 100 लैंग्वेज लैब पूरे हो जाएंगे। और 5 हजार से ज्यादा टीम्स को, 5 हजार से ज्यादा टीम्स को, बच्चों को उनके नए पंखों को उड़ान देने के लिए, नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए 20 हजार प्रति टीम यानी 10 करोड़ रूपये देकर उनको नई उड़ान भरने का अवसर हम दे चूके हैं।

और 2026- 27 के इस बजट में मैं, मैं दिल्ली के गरीब बच्चों, गरीब जनता की ओर से, दिल्ली के सभी नागरिक की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत -बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बार भी 9 हजार से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स, 175 से ज्यादा आईसीटी लैब्स और, और साथ ही साथ जो आप और हम अपने बच्चों के स्कूलों में देखते रहे हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चे की तबियत खराब हो गई, सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर साहब बैठेंगे, बेहतर बताएंगे। बच्चा बीमार हो जाता है, सरकारी स्कूल में लेकर भागते, प्राइवेट स्कूल में मेडिकल रूम बनाया हुआ है। दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में मेडिकल रूम बनाने के लिए बजट दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। दिल्ली की, दिल्ली की शिक्षा विभाग में और अन्य जगहों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए क्रैच खोलने का काम और AI into assessment of examination के लिए एक्सपोजर विजिट्स इंटरस्टेट और इंटर कंट्री विजिट कराने के लिए बच्चों को पैसा, प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी, सैनिक स्कूल। मैं कहाँ तक बोलूं, क्या-क्या बताऊँ आपको दिल्ली की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ 90 करोड़ रुपये से ज्यादा दिल्ली की बेटियों को उड़ान देने के लिए। इसको आप केवल एक साइकिल मत समझिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये केवल एक साइकिल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के माता-पिता संपन्न हैं। दूर स्कूल होता है, प्राइवेट बस मिलती है, एसी बस मिलती है माता-पिता बड़े गर्व से बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और यूं ले जाकर बस में फूल की तरह भेज देते

हैं। रिक्शा, रोड पार करना, कठिनाइयां और कैसे-कैसे वो बेटियां लगातार दूरी से आती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई की वृद्धि के लिए, ये जो विलक्षण सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने उड़ान भरने का उन्हें अवसर दिया है, वो 90 करोड़ रुपये केवल अमाउंट नहीं हैं ये दिल्ली की बेटियों के आगे बढ़ने का रास्ता है। छिछोरी मानसिकता पर सुबह इस सदन ने प्रस्ताव पारित किया ही है। मैं जब अच्छे काम होने वाले होते हैं ना जी तो एक नजर बट्टू चाहिए। ऐसे छिछोरे लोगों को उसमें नजर बट्टू की तरह हो और पीछे ये सोच कर चलिएगा बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला कहते हुए हम सब मिलकर इन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पुनः दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा और केवल स्कूलों पर बात नहीं रुकिए साहब। दिल्ली के एजुकेशन सेक्टर का ओवरऑल, ओवरऑल सुधार करने का काम आपको मालूम है, कहाँ हैं संजय जी। इनके यहाँ शाहदरा आईटीआई है, शाहदरा आईटीआई 1962 में बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1962 में बनी हुई आईटीआई आज, कितने बच्चे हैं, आठ एकड़ जमीन है आठ एकड़ जमीन। ये शिक्षा मॉडल शाहदरा के नजदीकी। हाँ जी, बिल्डिंग तो आठ एकड़ में बनी हुई है ना बिल्डिंग की बात बताई मैंने, बिल्डिंग की बात बताई। बस शाहदरा से परे रोड पार करते ही शिक्षा मंत्री रहते थे जिनको ये बता रहे हैं उसके लिए भी मांग रहे थे, अशोक जी आपने बताया उसके लिए भी मांग रहे थे भारत रत्न मनीष सिसोदिया जी के लिए। आज उस आठ एकड़ के भवन में केवल 300 बच्चे आईटीआई में पढ़ते हैं, केवल 300 बच्चे। दिल्ली की सबसे बड़ी टेक्निकल, सबसे पुरानी टेक्निकल एजुकेशन देने वाला संस्थान बिलकुल जर्जर हालत में, बिलकुल जर्जर हालत में उसकी हालत देख के वहाँ एडमिशन नहीं लेते। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका जीर्णोद्धार करते हुए, उसको नया निर्माण करते हुए साथ ही साथ, साथ ही साथ चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर दिल्ली की स्किल एजुकेशन और दिल्ली के बच्चों की स्किल में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वर्ल्ड क्लास नरेला एजुकेशन हब, 160 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके पैसे दिए गए हैं। खरीद कर वर्ल्ड की विभिन्न बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरह शेयर्ड कैंपस के रूप में उसको बनाना और अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस और आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। 8 साल हो गए, 8 साल से कॉलेज को शिफ्ट कर दिया, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, बनाने का नाम नहीं लिया, अब जाकर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीबी पंत का समाधान हुआ और 500 करोड़ रुपये की लागत से जीबी पंत इन्स्टिट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होगा। कितना पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है जीबी पंत। दिल्ली में शिक्षा की, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो पूसा पॉलीटेक्निक, शाहदरा पॉलिटेक्निक, जीबी पंत पॉलिटेक्निक, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। इन सबको बर्बाद करने का काम जिस सरकार ने किया था। इसीलिए, इसीलिए मैं

बार-बार कहता हूँ कि इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ तूफान से कश्ती को निकाला ही नहीं है, तूफान से कश्ती को निकाला ही नहीं है, हमने उस कश्ती को मंजिल का पता भी बता दिया है। इन सब चीजों का पुनर्निर्माण करने का काम हम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत लंबा समय ना लेते हुए केवल आपको दो-तीन विषयों में और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, श्रेष्ठ गीतकार शैलेंद्र जी ने एक बार गरीब की भूख का वर्णन करते हुए लिखा था।

''सूरज, सूरज ज़रा आ पासा आ,

सूरज ज़रा आ पास आ,

आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम।

ए आसमां तू बड़ा मेहरबान,

ए आसमां तू बड़ा मेहरबां,

आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम,

चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है,

गरमागरम रोटियां, क्या हँसी ख्वाब है।''

ये शैलेन्द्र जी ने बहुत साल पहले लिखा था, बहुत साल पहले और दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब आदमी के लिए अपना घर छोड़कर अकेला सुबह से शाम रोजगार के लिए अपने हाडमांस तोड़ने वाले आदमी के लिए अब गरमा गर्म रोटियां हसीन ख्वाब नहीं हैं, हसीन ख्वाब नहीं हैं अब अध्यक्ष जी, 28 लाख लोगों को 90 दिन में 5 रुपये में स्वादिष्ट भोजन हमनें दिया है और आगे 28 लाख लोगों को 28 लाख 5 हजार मील्स सर्व कर दिए गए हैं, 70 कैंटीन बनी हैं, 25 दिसंबर से शुरू हुई हैं। शैलेंद्र जी के इस गीत को जो पुरानी सरकारों की हकीकत था। कल्पना तो करके देखिए, कल्पना करिए वो पल्लेदार, वो पल्लेदार, वो टेम्पो पर पेटियां उठाकर रखने वाला। ऐसा आदमी एक बार सुबह बनाता है रात की भी बांध कर रखकर आ जाता है। उसको 5 रुपये में दोनों वक्त गर्म खाना मिल जाए, इज्जत से मिल जाए इस सोच के लिए और अटल जी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी ने इसे दिया और उसके साथ-साथ उसके साथ-साथ इस वर्ष भी, इस वर्ष भी ड्यूसिब की इस कैंटीन के लिए और इन झुग्गी-झोपड़ी के निवासियों के लिए। पिछले साल मैंने आप सबको इस सदन में खड़े होकर बताया था। पिछली सरकार ने 31 मार्च को 100 करोड़ रुपये का बजट रात को 10 बजकर 30 मिनट पर दिया था उसे खर्च नहीं कर पाए। 600 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये का ड्यूशिब का बजट

था पूरा हम स्पेंड कर चुके हैं और इस वर्ष 800 करोड़ रुपये का बजट झुग्गी-झोंपड़ी की सड़क, नाली, बहनों के बाथरूम, टॉयलेट और साथ ही साथ इन अटल कैंटीन की संख्या बढ़ाकर गरीब व्यक्ति को मोदी जी के सपनों का अंत्योदय की सरकार देने का काम श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो रहा है, जिसके लिए इन गरीबों के लिए, इन गरीबों के लिए जो बड़ा काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं पूरे सदन को अनुरोध करता हूँ एक बार मेज थप-थपाकर इन गरीबों की ओर से, इन गरीब बहनों-भाइयों की ओर से हम सब मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करें, धन्यवाद करें क्योंकि ये सरकार जहाँ बड़े-बड़े पुल बना रही है, ये सरकार जहाँ बड़े-बड़े नालों को ठीक कर रही है। ये सरकार जब बारिश के बाकी सामानों को ठीक कर रही है, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग इन सबको बना रही है वहाँ अपने कंधे पर बोझ लेकर काम करने वाले उस मजदूर को भी ये सरकार भूली नहीं है मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई की पात्र है और जिस प्रकार से इसमें बजट आवंटन किया गया है। मैं अटल कैंटीन मोदी जी की दिल्ली के मज़दूरों को गारंटी है और इस गारंटी को पूरा करने का काम श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हुआ है और बहुत सारे सेक्टर्स में बड़ा काम हुआ है अध्यक्ष जी। केवल विषयों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ पावर सेक्टर, पावर सेक्टर। हम जब से आए हैं डीटीएल को उठाकर देखें तो 8 साल में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में 8 साल से कोई भी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च नहीं हुआ है। डीटीएल के पीक पावर लोड के समय पर हर समय पूरे एसेट 90 परसेंट के ज्यादा लोड पर चलते हैं, 90 परसेंट से ज्यादा लोड पर। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आप सभी की विधानसभाओं में डिस्कॉम्स ने जितने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जितनी तारे बदली है, जितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, उसको सूचित करके आगे

के सुझाव मैं आपसे लेने वाला हूँ। ये सब दिल्ली का डिस्कॉम्स के पावर एक्शन, दिल्ली के डिस्कॉम्स का पावर है, मास्टर प्लान 17 हजार करोड़ रुपये और डीटीएल को अब, डीटीएल को 8 हजार करोड़ रुपये, 8 हजार करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑलरेडी हुआ है। चांदनी चौक में तारों को अंडरग्राउंड करने का काम 156 करोड़ की लागत से चल रहा है और 400 करोड़ रूपये की लागत से इन तारों को और अंडरग्राउंड करने का काम हम कर रहे हैं। जो मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ ना जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है तो प्राइवेट इंडीविजुअल भी उसमें पैसा लगाता है और इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। समाज में अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, रोजगार आता है इसलिए ये 400 करोड़ रूपये जो ऑलरेडी आपकी हाई टेंशन लाइन्स को अंडरग्राउंड करने के लिए अलॉटमेंट हो चुका है और 200 करोड़ रूपये इस वर्ष और हमने किया और 160 करोड़ रूपये की चांदनी चौक में अंडरग्राउंड होने का काम चल रहा है। कल, परसों में ही हमने फायर की एक दु:खद घटना के संदर्भ में चर्चा की

है। फायर की इस दु:खद घटना पे हम सब दु:खी हैं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पीड़ित परिवार से मिलकर Ex-gratia की राशि भी उनको सौंपी है और हर तरह की मदद उनको देने का आश्वासन दिया है। केवल एक व्यक्ति के यहाँ केवल एक व्यक्ति या एक परिवार का विषय नहीं है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए इस बार बजट को और बढ़ाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बार-बार हर मुद्दे पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। 674 करोड़ रूपये का बजट देकर और साथ ही साथ नए फायर स्टेशन, फायर का नया मॉडर्न कंट्रोल कमांड सेंटर आदि बनाने के लिए बजट का आवंटन एक नई दिल्ली को, नई दिल्ली से मेरा अर्थ विकसित भारत की राजधानी विकसित दिल्ली को बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के जो भागीरथी प्रयास चल रहे हैं इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको भी एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोगों को अब एक बजट से एक नई दिशा मिल गई है। हम सब दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ। बजट से एक नई दिशा मिल गई है। हमारे विरोधी कभी हमारी तारीफ करेंगे, ऐसी उम्मीद हम में से किसी को नहीं है। यहाँ उपस्थित किसी भी सदस्य को ये उम्मीद नहीं है क्योंकि वे तो खुद ही डिक्लेयर्ड अराजक हैं। वे तो खुद को अपने आप में ही anarchist कहते हैं, anarchist किसी सिस्टम में भरोसा नहीं रखते हैं। क्यों हमारा, हमसे चुनाव हार के गए हैं। रोज़ सपने में देखते होंगे, हाय मैं तो वहाँ बैठा था। हाय मैं तो वहाँ बैठा था, आज मेरे बदले श्रीमती रेखा गुप्ता वहाँ बैठी हैं, कैसे करवट बदलते समय जैसे ही नींद टूटती होगी, कितना दु:खी रहता होगा वो आदमी और उसके स्ट्रूजल्स कभी हमारी तारीफ करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा कहते रहेंगे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया मगर 1 लाख।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): बेरोजगारों को काम दे दिया आपने अच्छा किया।

श्री आशीष सूद(शिक्षा मंत्री): 1 लाख 3 हजार 7 सौ करोड़ रूपये के बजट में हर सैक्टर के लिए काम है। ठीक है कि किन्हीं-किन्हीं चीजों में थोड़ी-थोड़ी, आगे-पीछे प्रायोरिटीज, बजट की सैंक्शन्स, उपलब्धता हम जितना अपना टैक्स रेवेन्यु बढ़ा पाएंगे इस वर्ष 76 हजार करोड़ रुपये इस 1 लाख 3 हजार 7 सौ करोड़ में से seventy six thousand two hundred crore rupees सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर वित्तीय प्रबंधन, बेहतर फिजिकल मेनेजमेंट के चलते seventy six thousand two hundred crore rupees अपने टैक्स सोर्स से जनरेट करने का लक्ष्य दिया, अपने टैक्स सोर्स से seventy six thousand two hundred crore rupees ये इतना बड़ा परिवर्तन है दिल्ली की फिसकल मेनेजमेंट में, दिल्ली के वित्तीय प्रबंधन में जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मगर हमारे विरोधी कुछ कहते ही रहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ इसलिए मैं केवल चार लाइन उनको कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ, ''तुम ये ना समझ लेना'', वहाँ देख रहे होंगे, पक्का देख रहे होंगे ना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): लगे होंगे, अभी तो देख ही रहे हैं सारे। उनको बता दो कि भई तुम सुन रहे हो तो सुन लो पूरी बात।

श्री आशीष सूद(शिक्षा मंत्री): हाँ

''तुम ये ना समझ लेना की हम वादा शिकन निकले

तुम ये ना समझ लेना की हम वादा शिकन निकले

कुछ देर तो लगती है वादों को निभाने में

कुछ देर तो लगती है वादों को निभाने में।''

एक-एक वादा जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को किया है। एक-एक गारंटी जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को दी है, उस गारंटी को पूरा करने का बीड़ा हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने उठाया है। ये बजट उन आशाओं का, उन गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है जिसको हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और मैंने समय को आपकी अनुमति से थोड़ा ज्यादा ले लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थना के साथ। बहुत-बहुत धन्यवा,द साधुवाद जयहिंद, जय भारत, जय दिल्ली।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है । माननीय सदस्यगण, आज सदन को मैं अंत में सूचित कर रहा हूँ कि एक और हॉक्स कॉल, एक मेल आज दिल्ली विधानसभा में स्पीकर कार्यालय को भेजी गई है और जिसमें ये नक्सली और पाकिस्तान से जुड़ी इकाइयों की मदद से कुछ मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने 1 बजकर 40 मिनट दोपहर में धमाकों की बात की थी लेकिन हमारी कार्यवाही निरंतर और सतत चलती रही और सदन की कार्यवाही ऐसे नापाक इरादों के जो लोग है राष्ट्र विरोधी, हाँ जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): मैं इस पर एक मिनट लेना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष: ये पूरी कर लूँ बात। उनको ये जवाब है की लोकतंत्र जिंदाबाद। मैं एक मिनट आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिर मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा(उद्योग मंत्री): अध्यक्ष जी मेरा कहना है कि ये स्वाभाविक नहीं हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो मैंने आज आपको दिन में पढ़ के सुनाया था शायद आपके ध्यान में हो कि एक आम आदमी पार्टी के एमएलए ने एसडीएम को ये धमकी

दी कि मैं तेरे को गैंगस्टरों से मरवा दूंगा। अगर आम आदमी पार्टी गैंगस्टरों की धमकी एक एसडीएम को दे सकता है, ये स्वाभाविक नहीं हो सकता कि कल हमारा बजट आना था 1 लाख 3 हजार करोड़ का और हमें मेल आ गई। भई एक बात बताइये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इन सब चीजों के अंदर योगदान है। स्कूलों के अंदर मेल आ जाती है, ऐसा नहीं है उस मेल की जानकारी हमसे पहले आम आदमी तक पहुँच जाती है। ये इसके पीछे कौन है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कल के बजट को लेकर और क्योंकि आम आदमी पार्टी का आजकल गैंगस्टरों के साथ सरगनाओं के साथ उनका सारा लेन-देन है, ऐसे में मेरा मानना है कि इसकी गहराई में जांच होनी चाहिए कि इसमें आम आदमी पार्टी की क्या इन्वॉल्वमेंट है? आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या काम है? क्या बजट वाले दिन वैसी धमकियों खुद भिजवा रहे हैं, क्या स्कूलों में दहशत पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी खुद ऐसा काम कर रही है इन सब की भी जरूर गहरी जांच होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: ये बात जो मंत्री जी यहाँ कह रहे हैं। उसमें मैं आगे ये भी जानकारी दे रहा हूँ कि 16 RDX IED लगाए गए हैं, ये मेल में लिखा गया और बुधवार दोपहर 1 बजकर 40 पर धमाके की योजना है। अभी जो सिरसा जी ने कहा है क्योंकि सदन में वो ये बात कह रहे हैं और मंत्री हैं और जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो ये बात तो निश्चित है की इसको इस संदर्भ में पुलिस को हमने मेल करके और पूरी ये मेल जो प्राप्त हुई है ये भी, कल भी जो मेल प्राप्त हुई थी वो भी। कल भी भेज दी थी, आज भी भेज दी है, आज भी यहाँ पर स्क्वाड आया था और उन्होंने पूरी जांच की थी। जो पुलिस से हमारा यही कहना है की वो इसको हर एंगल से जो आप एंगल कह रहे हैं उस एंगल से भी इसकी जांच करें क्योंकि जिस तरह की आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो इस देश में किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के द्वारा जो उनको शह दी जा रही है उसका खुलासा होना चाहिए। दूसरा, मैं अंत में विपक्ष की नेता और विपक्षी विधायकों से फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि वो सदन को अवॉइड ना करें। किसी भी बहाने से सदन से बाहर ना रहें, सदन में आयें और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। सदन में ना आकर सदन को ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है ऐसा लगता है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चाहे वो सीएजी की आ रही है, चाहे वो पीएसी से आ रही है, चाहे वो प्रिविलेज से आ रही है या फिर बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं उस पर बोलने के लिए शायद उनके पास कुछ है नहीं। ऐसा लग रहा है मुझे तभी वो किसी ना किसी बहाने से सदन से बाहर जाकर बैठ गए तो जो बात सदन में आकर करने के लिए हम उनको समय देना चाहते हैं, उसकी बजाय वो बाहर जाकर के बैठ गए हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी जो विपक्ष की भूमिका जनता ने उनको दी है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है अगर विपक्ष की जिम्मेदारी भी एक जिम्मेदारी है और जनता देख रही है कि आप अपने विपक्ष की जिम्मेदारी के प्रति गैर जिम्मेदार

है और ऐसी स्थिति में लोग विपक्ष की जिम्मेदारी भी देने में संकोच करेंगे अगर वो इस तरह का व्यवहार विपक्ष का रहेगा तो क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी है विपक्ष की और उसका निर्वाहन ठीक प्रकार से विपक्ष कर नहीं रहा है। मैं दिल्ली की जनता को देश की देश को ये बताना चाहता हूँ की दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। सदन में ना आकर चर्चा में भाग ना लेकर जनता की जो उम्मीदें थी विपक्ष से कि वो उनके मुद्दे उठाएंगे वो उससे भाग रहे हैं। फिर अपील करता हूँ वो 27 तारीख को सदन में उपस्थित हों, जी।

श्री आशीष सूद, माननीय शिक्षा मंत्री : ये बात जरूर रिकॉर्ड पे आपके वक्तव्य के साथ जुड़नी चाहिए तीन सदस्यों वाली पार्टी ने भी यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाई और डेढ़ साल डेढ़ साल।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :पांच 5 मिनट के लिए सदन और बढ़ा रहा हूँ।

श्री आशीष सूद, माननीय शिक्षा मंत्री : डेढ़ साल डेढ़ साल बाहर निकालने के बाद भी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए यहाँ काम होता था वो तो 22 सदस्य हैं। इसका मतलब या तो है नहीं और जैसा सिरसा साहब कह रहे हैं कहीं बम बम लगवाके खुद ही बाहर तो नहीं बैठ रहे जाकर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :देखिये ये बात सही है कि पूर्व में विपक्ष की संख्या बहुत कम थी और 2015 से 2020 का जो समय था उसमें तो 67 लोग सत्ता दल के थे और तीन लोग पहले शुरू में 2015 से 17 तक विपक्ष के थे। लेकिन कभी विपक्ष के साथियों ने मेरे समेत सदन को छोड़ा नहीं। हमें बाहर फेंक दिया जाता था, फिर भी हम सदन में आते थे और उपहास के बाद भी सरकार की कमियों को उजागर करते थे, जनता की आवाज उठाने के लिए आते थे कि जनता की हमसे अपेक्षाएं हम संख्या में कम है लेकिन जनता की हमसे अपेक्षा थी की हम बात कहे। इसलिए जो मंत्री जी ने बात कही है बिलकुल सही है। अब मैं सदन की कार्यवाही..

......व्यवधान........

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब हो गया बस। शार्ट में कहिए और फिर ऐसे तो।

डॉ अनिल गोयल: सर, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ इसको हमने साइबर क्राइम और इसके आईपी एड्रेस से ट्रैक किया है कि कहाँ से है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष :हाँ, ये साइबर क्राइम को भी दिया गया है और इसकी इसकी पूरी जांच की कार्रवाई चल रही है। पूरा इस पर कॉग्निजेंस लिया गया है। अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 27 मार्च 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 27 मार्च 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)